मूल्य रु० ६/-

ण-भाद्रपद २०५८ अगस्त २००१

स्वदेशी पत्रिका

स्वाभिमान, आर्थिक स्वावलंबन, राष्ट्रीय पुनर्रचना तथा स्वदेशी संदेश की संवाहिका

र्थ-दैत्य एनरॉन के पंजे में कैलिफोर्निया

आर्थिक मंदी कितनी भयावह

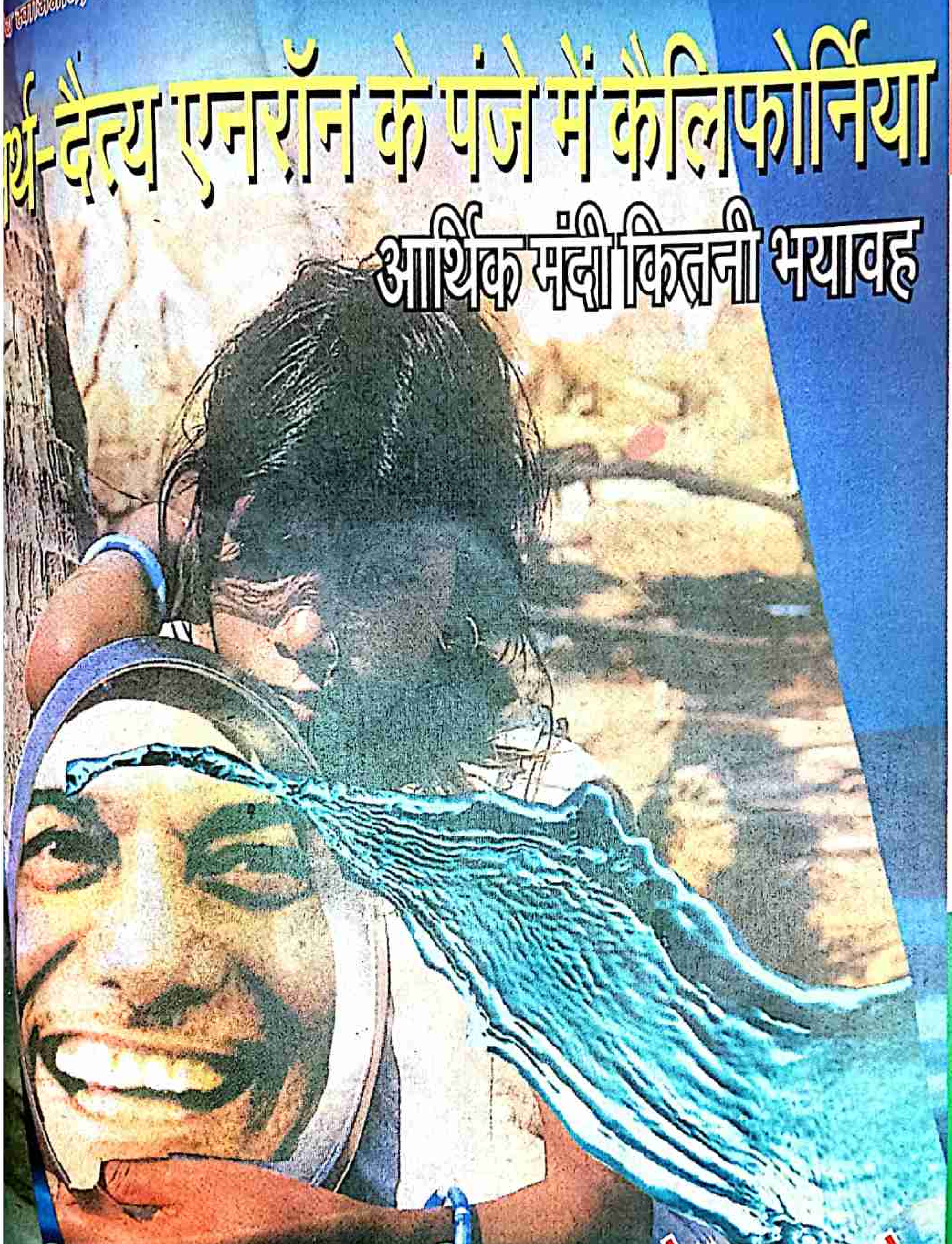

कहीं अमरीका की मंदी भारत को न डूबा दे

Scanned with OKEN Scanner

फिर भी आपको पुकारते हैं ये शब्द

■ पारिजात

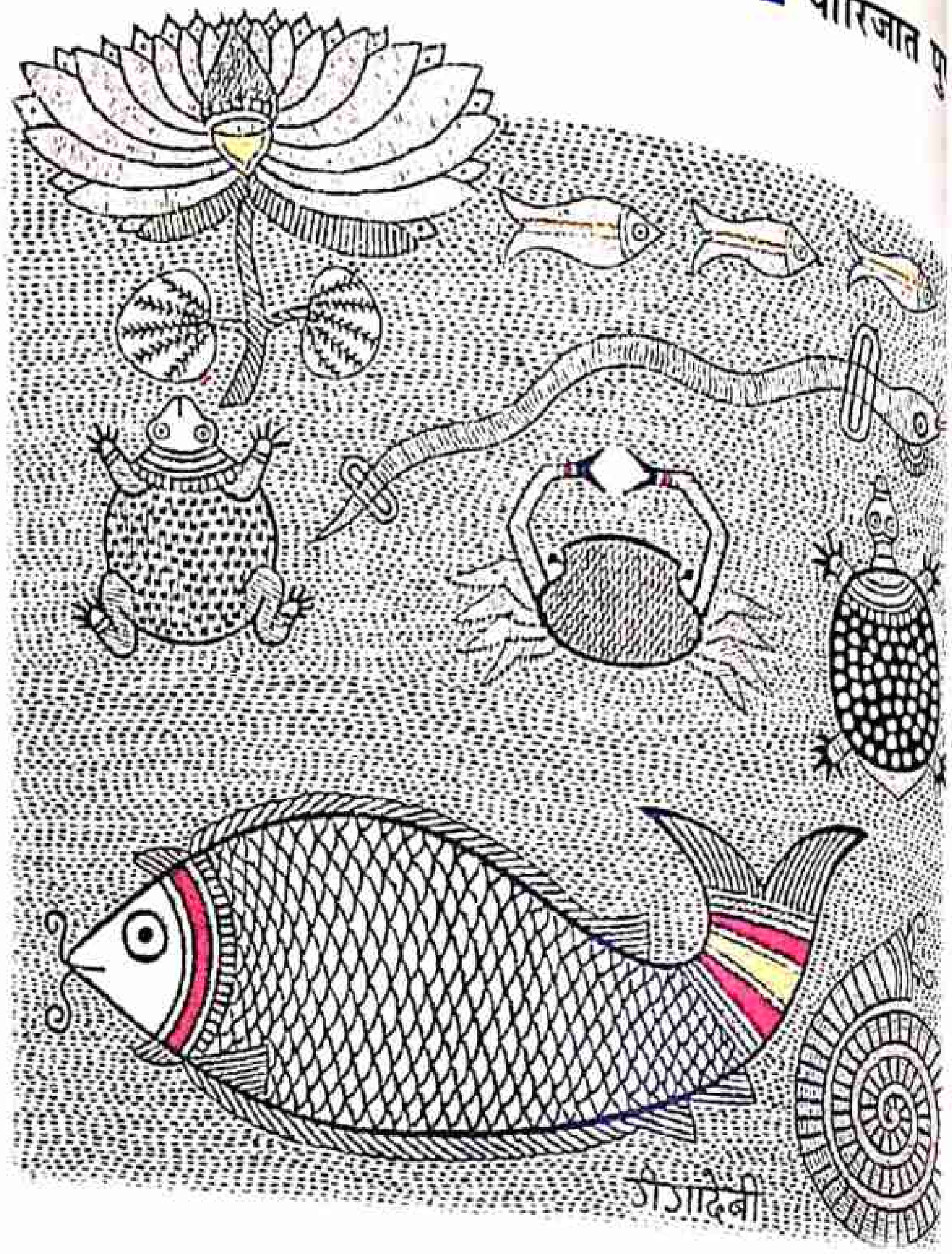

वे लोग आपके करीब
जा रहे हैं,
हम आपको अपने करीब
बुला रहे हैं।
वे नाच-गाकर
मनमोहक दृश्यों-सम्वादों से
रीझा रहे हैं,
हम कुछ नीम-से कड़वे सच को
बार-बार बता रहे हैं।
वे अँधेरा बाँट रहे है
गा रहे हैं लोरी,
सुला रहे हैं आपको
कर रहे हैं आपके हिस्से की चोरी,
वे आपको प्यार से
बना रहे हैं उपभोक्ता,
आप शौक से बन रहे हैं उपभोक्ता।
और हम शब्दों में भरकर
सुबह का उजाला
आपको जगा रहे हैं,
आपकी सुख निदिया उड़ा रहे हैं कि
आप जगें –
जागरण के समवेत गान में गूँजे
आपका भी स्वर,
आप जुड़ें
शब्दों के चेतन-नभ से
भरे आपका भी अंतःकरण,
आप उठें,
उठे आपका समुज्ज्वल भविष्य
है न, ये कुछ सीधे-सादे नीरस शब्द,
सुनने-पढ़ने-जानने से अधिक
आपसे अपेक्षा करते हुए शब्द,
नीम की कडुआहट में भीगें हुए शब्द,
है न, ये प्रयत्न की प्रेरणा से
पीड़ा पहुँचाते हुए शब्द।
मगर किसी और के लिए नहीं
सिर्फ आपके लिए हैं ये शब्द;
इसीलिए ये आपको
अपने करीब बुलाते हैं,
अपने से जोड़ने की
करते हैं आशा,
रूठते हैं आपसे,
सहते हैं आपके दुत्कार,
फिर भी आपको पुकारते हैं ये शब्द। ■

वार्ता

क वृन्द,

ह अगस्त के स्वतंत्रता दिवस को आपके साथ हमारा भी प्रणाम, इस
 साथ कि हर वर्ष उत्तरोत्तर प्रसन्न मुखमंडल लेकर आता रहे, हम इसकी
ई डोर की गाँठें खोलते रहें। आजादी-आर्थिक आजादी में परिवर्त्तित हुए
र्थक नहीं होती। इसी परिवर्त्तन की लड़ाई है – स्वदेशी आंदोलन। यह
लोकतंत्र के लिए स्वतंत्रता का दूसरा संघर्ष है और हम सब हैं इस लड़ाई
ही। इसी ध्येय के संधान में स्वदेशी पत्रिका का यह अंक ज्वलंत विषयों के
पके सम्मुख है।

मस्कार।

आपका

प्रमोदकुमार दुबे

म

अर्थ-दैत्य एनरॉन के पंजे में कैलिफोर्निया................................/६

आर्थिक मंदी कितनी भयावह
डॉ. रमाकांत पाण्डेय................../१०

कहीं अमरीका की मंदी भारत को न डूबा दें
विक्रम उपाध्याय................../१३

दसवीं पंचवर्षीय योजना लक्ष्य की मरीचिका
विद्यानंद आचार्य................../१६

स्वदेशी अपनाए बिना इसे फेल मानना ऐतिहासिक अपराध
जय दुबाशी........................../१९

यूएस-६४ का ओर-छोर
मुकुन्द कुमार........................../२१

भारतीय कृषि के साथ ऐसा अन्याय क्यों?
मूँगालाल सुरेका..................../२३

स्वयं सहायता बंद कीजिए
डॉ. भरत झुनझुनवाला................../२७

दुश्मन की बेटी और नूर मियाँ के बीच से
डॉ. प्रमोदकुमार दुबे................../३३

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन में कृषि श्रमिकों का पक्ष........................../४३

पाठकनामा/४, उन्होंने कहा/४, ऊर्जा विकल्प/३०, माध्यम/३६,
घर गृहस्थी/४१, हलचल/४४, व्यंग्य/४५ समाचार परिक्रमा/४७

संपादकीय कार्यालय : ६०, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-११० ००१ ● दूरभाष : ३०१८१७५
ई-मेल : swadeshisampark@rediffmail.com

स्वदेशी पत्रिका

वर्ष–६, अंक–११
श्रावण–भाद्रपद २०५८, अगस्त, २००१

:: अमर वाणी ::

ये देवानां यज्ञिया यज्ञियानां मनोर्यजत्रा अमृता ऋतुज्ञाः। ते ना रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥

जो आप विद्वानों में भी अत्यंत पूजनीय और मननशील सत्यज्ञानी हैं, वे आप संन्यासी लोग विद्या के उपदेश हमें देवें और कल्याणकारी पदार्थों से हमारी रक्षा करें।

• • •

येभ्यो माता मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिरद्रिबर्हाः। उक्थशुष्मान् वृषभरान्त्स्वप्नसस्ताँ आदित्याँ अनुमदा स्वस्तये॥

जिन विद्वानों के लिए, सबको निर्माण करने वाली पृथ्वी मीठे दुग्धादि पदार्थ देती है और अखण्डनीय मेघों से भरा हुआ अंतरीक्ष-लोक सुंदर जल देता है, अत्यंत बल वाले यज्ञ द्वारा वृष्टि करने वाले, उन लोगों को उपद्रव न होने के लिए हमें प्राप्त कराइए।

(भक्ति दर्पण)

मुख्य संपादक :
डॉ. महेश चंद्र शर्मा
कार्यकारी संपादक :
डॉ. प्रमोदकुमार दुबे

मूल्य : एक अंक - ६ रुपए
वार्षिक सदस्यता शुल्क - ६० रुपए
आजीवन सदस्यता शुल्क - १०००/-

विशेष सूचना : अपनी सदस्यता सूची एवं सदस्यता फार्म कृपया अपना नाम व पता, पिनकोड सहित साफ-साफ शब्दों में लिखकर भेजें।

Scanned with OKEN Scanner

पाठकनामा

सौर ऊर्जा का विकल्प

प्रिय संपादक

तीसरी दुनिया के अविकसित मुल्कों में सौर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है दुर्भाग्य है कि इस ऊर्जा का बड़े पैमाने पर उपयोग करने के प्रयास नहीं हो रहे। विकसित देश इस क्षेत्र में कोई कदम नहीं उठाएँगे। यह काम उन्हीं देशों को करना होगा जो अविकसित है इस अकूत और पर्यावरण मित्र ऊर्जा भंडार का लाभ जिस दिन मिलना शुरू हो जाएगा हम विकसित देशों को बहुत पीछे छोड़ सकते हैं। अपने देश को इस दिशा में कार्य करना चाहिए।

धीप्रज्ञ द्विवेदी का लेख 'भविष्य की ऊर्जा सौर ऊर्जा' वैकल्पिक ऊर्जा को इंगित करने वाला उचित लेख लगा। कई अंकों में इस विषय पर इनके लेखों को पढ़ चुका हूँ। आशा है इनका नियमित लेख फलदायी होगा।

रवीन्द्र सिंह
सीवान, बिहार

राष्ट्रीय-सुरक्षा का प्रश्न

प्रिय संपादक,

प्रतिरक्षा क्षेत्र में २६ प्रतिशत का एक प्रतिशत भी विदेशी पूँजी निवेश ऐसे हस्तक्षेपों की शुरूआत बन सकती है जिससे राष्ट्र की सुरक्षा का मनोबल गिरेगा। शायद सरकार ने आँख बंद कर लिया है। पत्रिका के जुलाई अंक के अग्रलेख में पूर्वरक्षा वैज्ञानिक गिरिश अवस्थी के उधृत कथन 'कि प्रमोद महाजन सरीखे लोग यह कहते हैं कि मोजा से लेकर रॉकेट तक हम निजी क्षेत्र से बनवाएँगे। क्या वह राष्ट्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं' बहुत अच्छा लगा। सार्थक प्रयत्न के लिए धन्यवाद।

– लालकृष्ण शर्मा, रोहतक

प्रतिभा पलायन रुके

संपादक जी,

पत्रिका विलम्ब से मिली डाक के अलावा खुले बाजार में भी पत्रिका की उपलब्धता होनी चाहिए। मुझे रक्षा अनुसंधान से संबंधित सी० उदय भास्कार के साक्षात्कार में जागरुकता की कमी कुछ खल-सी गई। इस साक्षात्कार में सरकारी बोल का पक्ष दिखाई पड़ा बोफोर्स तोप जैसी खरीददारियाँ तो होती हैं उनमें साफ सुथरा लेन-देन रहे तो इसे स्वीकारना विवशता है पर क्यों हमें अपने विकास में मानव संसाधन प्रतिभा और कौशल प्रयोग नहीं करनी चाहिए। हमारे वैज्ञानिक देश में उपेक्षित होकर विदेश चले जाते हैं और वहाँ के उत्पादन की खरीद में देश कंगाल बनता है उन प्रतिभाओं को देश में प्रश्रय देने के प्रयत्न क्यों नहीं हो रहे कि दूसरों का मुँह देखा जा रहा है?

– कमलेन्दु मिश्र
देवरिया, उत्तर प्रदेश

उन्होंने कहा

दुनिया में स्थाई एवं ताकतवर रैंक हमारे हित में हैं। वे हमें अपने उत्पाद निर्यात करेंगे समस्याएँ नहीं।

अमेरिकी
जार्ज बु

इस वैश्वीकरण में राष्ट्रीय अस्मिता पहचान बनाए रखने वाली एकमात्र शिक्षा है। इस क्षेत्र को विदेशी निवेश लिए खोलना आत्महत्या के समान हो अगर ऐसी स्थिति आती है तो हमें वि व्यापार संगठन छोड़ना होगा।

स्वदेशी जागरण मंच के सं
एस० गुरु

हमारा अन्न उत्पादन पर्याप्त पोषक प्रदान नहीं कर रहा है और प्र व्यक्ति दालों की उपलब्धता घट जा रही है। अन्न उत्पादन निर्यात क वालों की मनमर्जी से हो रहा पोषकता हमारे अन्न उत्पादन नीति केंद्र होना चाहिए।

भारतीय पोषकता प्रतिष्ठान के अ
सी. गोपाल

वैश्वीकरण नया नहीं है और न यह पश्चिमीकरण है।

प्रख्यात अर्थ
अमर्त्य

वैश्वीकरण के इस दौर में सामाजि सुरक्षा तंत्र स्थापित नहीं किया सका है यह हमारी नीतियों की व है।

पूर्व वि
मनमोहन

प्रचुर मात्रा में अन्न होने के बाव अधिकारियों ने देश में अन्न की क बना रखी है।

उच्चतम न्याया

Scanned with OKEN Scanner

वैश्विक और दैशिक परिदृश्य में कहाँ खड़े हैं हम.....?

पन्द्रह अगस्त का दिन कहता – आजादी अभी अधूरी है . . . . एक प्रसिद्ध कविता की यह पंक्ति हमारी आजादी को चाहे जिस किसी संदर्भ में अधूरी मानती हो, पर देश को इस अधूरेपन का अहसास जिस रूप में गहराता जा रहा है वह है आर्थिक पराधीनता। स्वतंत्र होने के बाद भी आर्थिक पराधीनता अवशेष बनी रही और इन दिनों में पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी के नए संस्करण बहुदैशिक कंपनियाँ देश में अपने पाँव जमाने लगी है अभी एनरॉन इंडिया की बिजली के झटकों से हम बदहाल हो रहे थे कि एनरॉन स्टील के क्षेत्र में भी आने के लिए दाँव फेंकना शुरू कर चुका है। इन कंपनियों से ही आज भूमंडलीकरण का दौर निर्मित हुआ है। यह पुराने समय की साम्राज्यवादी शक्तियों के नए चेहरे हैं। आज भूमंडलीकरण का विरोध आर्थिक स्वतंत्रता का एक जरूरी अंग बन गया है।

अभी इटली के तटीय शहर जेनोआ में हुए विश्व के आठ धनी देशों के त्रिदिवसीय सम्मेलन के सम्मुख हजारों प्रदर्शनकारियों ने भूमंडलीकरण के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का प्रयास किया, लेकिन यह प्रदर्शन दमन का शिकार हुआ और हिंसा भड़क उठी। एक युवक की मौत हुई, साठ घायल और दर्जनों गिरफ्तार हुए तोड़–फोड़ की वारदातें भी हुईं। यह भूमंडलीकरण कुछ और नहीं नए चेहरे में आर्थिक उपनिवेश का विस्तार है जिसके लिए नए–नए अस्त्रों का निर्माण हो रहा हैं, नई–नई रणनीतियों की खोज हो रही है। इस भूमंडलीकरण की परिभाषा विभिन्न देशों में बहुदैशिक कंपनियों के पाँव जमाने और आर्थिक शोषण करने से मुकम्मल होती है बतौर उदाहरण भारत में पाँव जमा कर खड़ी आर्थिक दैत्य के रूप में कुख्यात कंपनी एनरॉन को देखा जा सकता है।

अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति रिचर्ड चेनी से बातचीत करती हुई काँग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गाँधी ने संभवतः अनुभव किया होगा कि अमेरिका की कृपा के लिए एनरॉन की बिजली–छड़ी हाथ में लेकर कांग्रेस शासित राज्यों को झटके लगाना क्यों आवश्यक है। चेनी ने स्पष्ट कहा कि उनके विचार राष्ट्रपति जार्ज बुश के ही है इस पर संशय करना जरूरी नहीं इसमें कोई छिपावा भी नहीं है कि एनरॉन अमेरिकी गणतंत्र का सबसे बड़ा कम्पेन फाइनेन्सर रहा है निजी तौर पर एनरॉन कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष केनेथ ले का सबसे बड़ा सहयोग जार्ज बुश के साथ रहा है। यदि एनरॉन भारत में कामयाब नहीं होता है तो इससे विदेशी पूँजी निवेश से भारत को वंचित रहना पड़ सकता है अमेरिका के व्यापार और कृषि विषयक, उप–विदेश मंत्री एलेन लारसन के वक्तव्य में भी एनरॉन को कठिनाई में डालने पर विदेशी निवेश के प्रभावित होने की बात आई है। मतलब साफ है कि एनरॉन कोई छोटी चीज नहीं है उसके पीछे अमेरिका की पूरी ताकत है वह आर्थिक उपनिवेश स्थापित करने वाला एक प्रचण्ड योद्धा है भूमंडलीकरण का स्तंभ है इससे टक्कर लेना और इसे उखाड़ फेंकना एक बड़ी विजय का उदाहरण बन सकता है। वास्तव में यही विश्व में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का रास्ता भी है। अमेरिका पर निर्भर होकर एनरॉन को देश में आर्थिक शोषण की छूट देनी पड़ेगी। एनरॉन आर्थिक शोषण से अर्जित धन का व्यय अमेरिका सरकार को अनुकूल बनाने में करता रहेगा और अमेरिका उसके भूमंडल पर विस्तार के लिए बाहुबल का प्रदर्शन करेगा अमेरिकी मित्रता और भरोसा घोषित रूप से जनहित के संकल्प से किसी जनतांत्रिक सरकार को विचलित करता है, यह नहीं भूलना चाहिए।

अभी अमेरिका में छायी आर्थिक मंदी से सहानुभूति रखकर भारत ने निर्यात में कमी लाई है और स्वयं भी आर्थिक मंदी के सन्नाटे से घिरने लगा है। अमेरिकी बाजार का विकल्प क्या हो, इस दिशा में भारत के निर्यातक चिंतित हैं। देश की आर्थिक मंदी और औद्योगिक शिथिलता से उबरने के लिए एकमात्र उपाय के रूप में घरेलू माँग को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की राय सामने आ रही है इस राय से स्पष्ट हो रहा है कि जिस भारत को बड़े बाजार के रूप में बहुदैशिक कंपनियाँ देख रही है उसे देश के उद्योगपति अपने हाथ में रखना चाहते हैं। पर क्या इस समय देश में प्रचलित शीर्ष के दस ब्राण्डों में कोई उत्पादन ऐसा है जिसे स्वदेशी कहा जा सके? क्या इसके लिए आवश्यक रणनीति और भविष्य दृष्टि की कमी इन उद्योगपतियों में नहीं रही है। बहुदैशिक कंपनियों के वर्चस्व की चुनौतियों को इन्हें अपने घर में भी झेलना पड़ेगा।

आर्थिक उपनिवेश के बढ़ते वर्चस्व को कम करने में सार्क देशों के बीच घने व्यापारिक संबंध होने से सहयोग मिलता। लेकिन देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाक फौजी हुकुमरान परवेज मुशर्रफ के बीच हुई आगरा शिखर वार्ता आर्थिक रणनीतियों से दूर भू–राजनीति के सबसे विकृत रूप आतंक और अलगाव की पाकिस्तानी मानसिकता में फँस गई। जिस तरह के दृश्य इस पूरे प्रकरण में सामने आए, उससे यही लगा कि अंग्रेजों की वेशभूषा–भाषा और कुछ दिखावे के रंग–ढंग सभ्यता के नाम पाकिस्तानियों ने ओढ़ लिया है जो उनकी आधुनिकता कही जा सकती है। पर, इस खोल में उनका असली चेहरा मध्यकालीन बर्बर आक्रांताओं का ही है जिससे कभी उम्मीद नहीं की जा सकती कि आज के वैश्विक अर्थ युद्ध के प्रति उनमें कोई जागरूकता उत्पन्न हो सकती है इस मानसिकता में आर्थिक गुलामी की जंजीर गले में अवश्य लटक सकती है।

व्यक्ति–व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो, राज्य और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था सबल हो, हमारे उपमहाद्वीप और दक्षिण एशिया के कदम आर्थिक समृद्धि और आपसी सौहार्द की ओर अग्रसर हो, इसके साथ विश्व के उन सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण आर्थिक संबंध हो जो अत्यंत समृद्ध एवं शोषक देशों के आगे हतप्रभ है, जो अपने हितों की रक्षा बिना एक साथ खड़े हुए नहीं कर सकते। इसके बावजूद कि उनके पास मानव और खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं है तब जाकर हम विश्व व्यापार संगठन अथवा अन्य वैश्विक संगठनों में शक्तिशाली देशों की मनमानी पर रोक लगाने में कामयाब हो सकते है और अपने आर्थिक लोकतंत्र का ध्वज लहरा सकते हैं। इस मार्ग की बाधाएँ देश में यू.एस.६४ जैसी वित्तीय क्षेत्र की दुर्घटनाओं से खड़ी होती हैं। जब तक यह ध्यान नहीं रहेगा कि समष्टिहित से मुँह फेरने वाली किसी व्यवस्था पर स्वयं प्रश्न चिन्ह खींच जाता है, व्यवस्था का औचित्य समझ में नहीं आ सकता।

Scanned with OKEN Scanner

अग्रलेख

अर्थ-दैत्य एनरॉन के पंजे में कैलिफोर्नि

पी.डी. कार्तिकेय

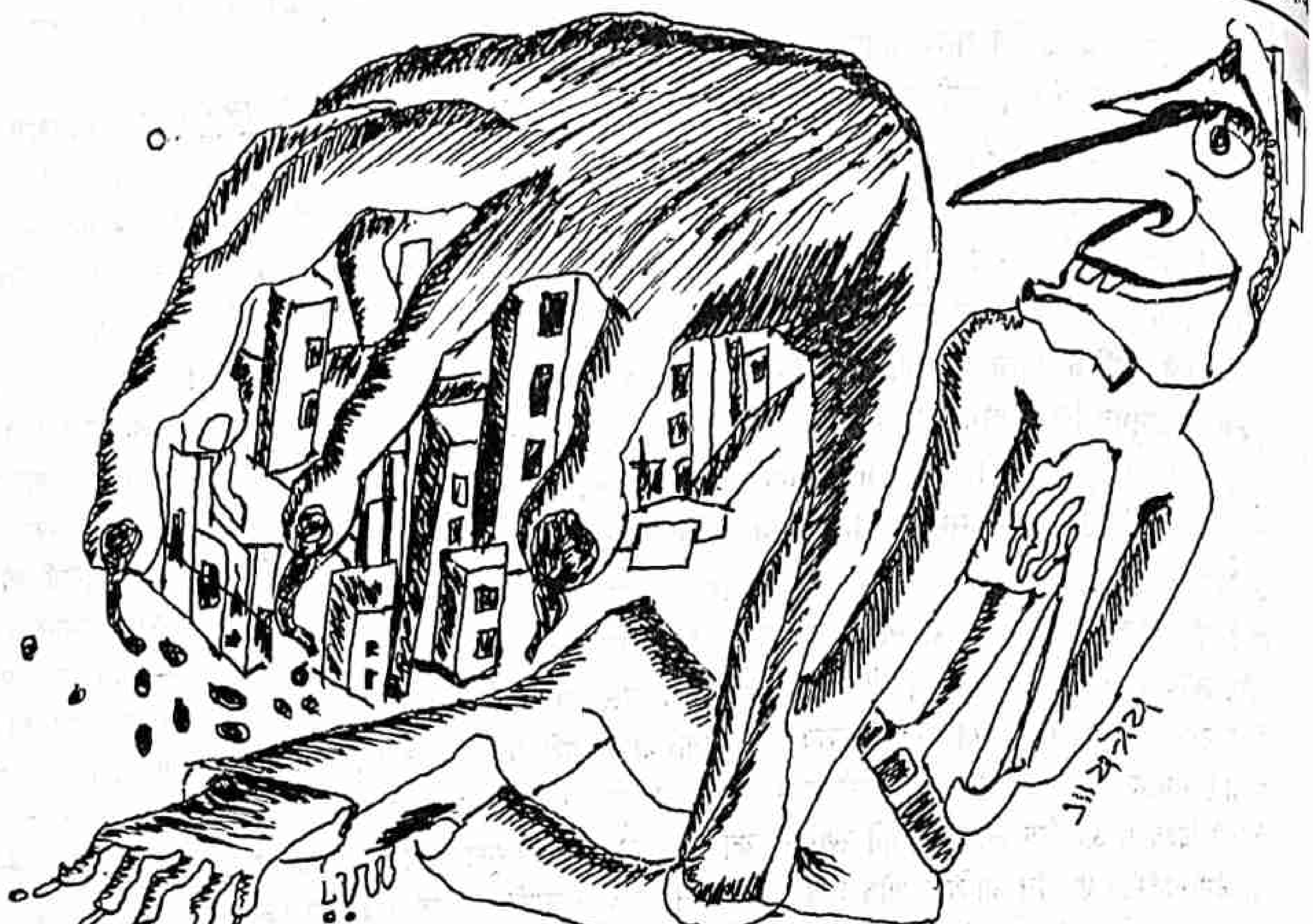

एनरॉन नाम की अमरीकी कंपनी वास्तव में कोई उत्पादक कंपनी नहीं है। यह एक चमत्कारी कंपनी है जिसके विषय में कुछ भी स्पष्ट बताना कठिन है। इसकी स्थापना ह्युस्टन, अमेरिका में १९८५ ई० में हुई थी। इसकी स्थापना दो ऐसी प्राकृतिक गैस पाइप लाइन की कंपनियों को मिलाकर हुई जो कबाड़ा हो चुकी थीं। इसका मुख्यालय ह्युस्टन में है। इसमें एक से एक कानून विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री और सरकारी तंत्र को पटाने में दक्ष व्यक्ति कार्यरत है।

एनरॉन कारपोरेशन प्राकृतिक गैस बेंचनेवाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है लेकिन इसने आज तक किसी प्राकृतिक गैस के खादान की खुदाई करने में हाथ नहीं डाला यह प्राकृतिक गैस के खदानों की खुदाई करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता देती है लेकिन यह कोई बैंक नहीं है। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी बिजली बेंचने वाली कंपनी है लेकिन यह ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनी नहीं है।

एनरॉन पेपर, स्टील मालवाहन के व्यापार में भी लगी हुई कंपनी है। इसने गैस पाइप लाइन बिछाने के पुराने कारोबार के साथ फाइबर नेटवर्क भी बिछाकर इंटरनेट वैण्डविथ की बिक्री शुरू की। अभी इसके पास दुनिया का सबसे बड़ा वेव आधारित आर्थिक साइट है – एनरॉन ऑन लाइन, जिसने १९९९ में ३३६ विलियन डॉलर का व्यापार किया था।

इतना सच है कि एनरॉन कारपोरेशन में उर्वर मस्तिष्क के षड्यंत्रकारी कार्यरत हैं। ये पैसा कमाने के एक से एक त की खोजकर सरकारी तंत्र को प्र करके अपने मतलब के काम निक वाले गहरे खिलाड़ी हैं। इस कंप दावा है कि यह ऊर्जा क्षेत्र में का करने वाली एक कंपनी है लेकि अवसर देखकर जाल फेंकने वाली लाभकारी धंधे में हाथ डालने कंपनी है। इसके कारोबार में प्रकार की ईमानदारी और स्थापित लिए कोई स्थान नहीं रहने के कार षड्यंत्रकारी दस्यु उद्योगपति के रू देखा जाने लगा है। यह कानूनी दाँ बनाकर बच निकलने में भले ही है लेकिन इस पर उन सभी लोगों पैनी नजर भी जिन्हें इसने चूना लगा काम किया है।

कैलिफोर्निया के एटॉर्नी ज

Scanned with OKEN Scanner

को पूरी आशा है कि एनरॉन
क रूप से आर्थिक शोषण
ी चल रही जाँच जुलाई माह
में पूरी हो जाएगी। बिल
खुलेतौर पर कहा है कि 'मैं
कि एनरॉन कारपोरेशन के
नेथ ले को ८ बाई १० की
पहुँचा दूँ'। एनरॉन के प्रमुख
बिल लॉकर की नजर में
षण का एक अपराधी है जो
जनहित और लाभ को एक
लित करना नहीं जानता। वह
कमाने के कानूनी दाँवपेंच
ार को प्रभावित करने में
रखता है।

दिनों एनरॉन नामक दैत्य के
अमेरिका का एक राज्य
या फँसा हुआ बिजली के
जूझ रहा है। वहाँ उपभोक्ताओं
करने के सिलसिले में एनरॉन
चल रही है। कैलिफोर्निया में
न पर उसी तरह के आरोप
ए है जैसे आरोप महाराष्ट्र में
के डाभोल विद्युत परियोजना पर
है।

रॉन ने कैलिफोर्निया के बिजली
ताओं का बेहताशा शोषण किया
वहाँ बिजली की काफी कमी
दो वर्ष पहले जिस दर पर वहाँ
भोक्ता बिजली खरीद रहे थे
तुलना में बिजली की कीमत
बढ़ाते हुए एनरॉन ने कई बिलियन
खींच लिया है। इस कंपनी से तबाह
कैलिफोर्निया के गवर्नर ग्रेडेवीस
ी केन्द्र सरकार से एनरॉन की
ी की कीमत कम करवाने की
कर रहे हैं। एनरॉन पर लगे आरोपों
लड़ाई में उसका दावा है कि उसकी
का पैसा पूरी तरह वैद्य है उसने
लोगों की तुलना में कही अधिक ईमानदारी से पैसा कमाया है। उसने बिजली की खरीद और बिक्री में बाजार को अपने ढंग से नियंत्रित किया है। उपभोक्ताओं से भरपूर मुनाफा कमाया है। एनरॉन के तर्क में यह स्पष्ट दिखता है कि वह खेल के नियम बनाना जानती है। वह अपने नियमों को पहले लागू करती है और अवसर के अनुसार नियम में बदलाव करती हुई आगे बढ़ती जाती है। उस पर निर्भर उपभोक्ता आपूर्ति के बदले मजबूर होकर पैसे देते जाते हैं। एनरॉन के नियमों को वैधानिक स्वीकृति देने में सरकार की भूमिका होती है। सरकार बनाने वाले राजनीतिकों से उसकी अलग सहभागिता है, जिसके आधार पर वह जनता के शोषण की स्वीकृति पाती है। एनरॉन के चेयरमैन केनेथ ले कोई छोटी चीज नहीं नहीं है। इस व्यक्ति की पकड़ सत्ता के शीर्ष पर है। यह वाशिंगटन को प्रभावित करने में सक्षम है। यह व्यक्ति तेल का एक व्यापारी है और टेक्सॉस का पूर्व गवर्नर भी रह चुका है। इसने जार्जबुश

फिर जारी है एनरॉन का प्रयास

दुनिया के कुशल व्यापारिक देश भी एनरॉन जैसे मुद्रा दैत्य के हाथ पकड़ने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, एनरॉन इंडिया के मकड़जाल में फँसा भारत शायद अभी भी होश में नहीं है यदि होश में होता तो वह इस जाल से निकलने का प्रयास करना छोड़कर फिर से समझौता के चक्कर में नहीं फँसता। इस कंपनी के निदेशक वाडे क्लीन से वित्त सचिव अजित कुमार की आधे घंटे तक बातचीत नहीं होती और इस बातचीत में एनरॉन कॉरपोरेशन के चेयरमैन केनेथ ले के साथ वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा की संभावित वार्ता की तैयारी नहीं चलती। जबकि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सुरेश प्रभु ने एनरॉन को अपना कारोबार समेट लेने के लिए स्वतंत्र माना। महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल को दुर्दशा तक पहुँचा देने और महाराष्ट्र सरकार की वित्तीय स्थिति को खराब करने में एनरॉन की षड्यंत्रकारी रवैया के जख्म अभी भरे नहीं हैं, तब तक एनरॉन के पक्ष में विचार–विमर्श का दौर शुरू हो गया है। एनरॉन के दाभोल विद्युत परियोजना को पुनर्जीवित करने के बाद महाराष्ट्र और देश के किसी उपभोक्ता राज्य की आर्थिक दशा चौपट होने से रोका नहीं जा सकता।

जुलाई २००१ के पहले पखवाड़े में एनरॉन कॉरपोरेशन के चेयरमैन केनेथ ले भारत सरकार के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा से वार्ता के लिए आए। ले का कहना था कि दाभोल विद्युत परियोजना के पुनर्जीवन से सरकार और देश दोनों का हित होगा। उन्होंने बताया कि वित्त मंत्री से उनकी बातचीत का नतीजार अभी सामने नहीं आया है। केनेथ ले ने बिजली मंत्री सुरेश प्रभु से भी दो घंटे बातचीत की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख से भी उनकी वार्ता एनरॉन को पुनर्जीवन प्रदान करने के सिलसिले में चलने वाली थी ताकि दाभोल विद्युत परियोजना और महाराष्ट्र विद्युत मंडल के बीच भुगतान को लेकर खड़ा विवाद समाप्त हो। इस दिशा में भारत सरकार के संबंधित मंत्री सुरेश प्रभु और वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के निदानदायी पहल की चर्चा सामने आई। एनरॉन के प्रयासों को अमेरिका के वाणिज्य दूत सैमुअल किडर ने यह कह कर बढ़ावा दिया कि एनरॉन विवाद के चलते विदेशी निवेशकों के बीच भारत के बारे में गलत संकेत गए हैं। इसका भारत में विदेशी पूँजी निवेश पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। दाभोल विद्युत परियोजना में भारत के बैंकों के अलावा जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को–ऑपरेशन ने ३५ करोड़ डॉलर लगाए हैं और ओपेक देशों के ४० करोड़ डॉलर। अमेरिकी निर्यात–आयात बैंक के अलावा ओमान और आबूधाबी की सरकारों ने भी ने भी निवेश किया है। दबाव बनाने के उपकरणों में इन निवेशकों का उपयोग स्वाभाविक होगा। ■

Scanned with OKEN Scanner

को चुनाव के दौरान एक लाख डॉलर से अधिक पैसे दिए थे। बुश के चुनाव प्रचार में एनरॉन ने अपने व्यापारिक गुर्गों को अपने खर्च से लगाया था। बुश के चुनाव में सबसे अधिक खर्च करने वालों में एनरॉन का नम्बर ऊपर है। एनरॉन कंपनी और इसमें कार्यरत व्यक्तियों ने बुश के चुनाव में १.३ मिलियन डॉलर लगाकर प्रचार किया था। यही कारण है कि जॉर्ज बुश सरकार के उपराष्ट्रपति रिचर्ड चेनी जब राष्ट्रीय उर्जा नीति बनाने जा रहे थे उन्होंने एकमात्र उद्योगपति एनरॉन के चेयरमैन केनेथ ले को ही विचार-विमर्श के लिए बुलाया। इन दिनों एनरॉन इस प्रयास में लगा है कि अमेरिका की केंद्रीय सरकार सार्वजनिक सेवा के अंतर्गत आने वाले विद्युत वितरण व्यवस्था को उसके हाथों में सौंप दे।

सैन डियागो के वकील माइकेल अग्यूर जिन्होंने एनरॉन के खिलाफ दायर

एनरॉन अपने देश अमेरिका में उसी रास्ते पूरी ईमानदारी से चल रही है जिस रास्ते पर कई अमेरिकी कंपनियाँ अपने ही देश की जनता के धन का पूरी निर्दयता से शोषण करती हुई अपराधी घोषित हुई। जब एनरॉन का चरित्र जग-जाहिर है तो इसके विषय में कोई सहानुभूति पूर्वक विचार करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

पाँच जनहित याचिकाओं में से एक याचिका स्वयं दायर की थी, एनरॉन को आने वाले समय का स्टैंडर ऑयल कंपनी जैसी ही भयंकर आर्थिक शोषण करने वाली कंपनी मानते हैं। उनका

मानना है कि जिस प्रकार कंपनी
के रेलवे ट्रांस्पोर्ट जॉन लो रॉके
नियंत्रण करके तेल के कारो
एकाधिकार कर लिया था, एन
ऊर्जा वितरण प्रणाली पर
कब्जा कर लेना चाह रहा है।

एनरॉन को बिजली के
१९९० के दशक में तब भारी
मिलनी शुरू हुई थी, जब उसने
हटाने के लिए लाविंग को
कैलिफोर्निया राज्य में उसने
दाँवपेंच से भारी धनार्जन किया।
व्यवस्था को समाप्त करवा कर
की कीमत में मनमानी बढ़ोत्तरी
जाने की चालाकी को कैलिफोर्नि
राजनेता बेइमानी मानते हैं। १९९
कैलिफोर्निया की सार्वजनिक जन-
के कानून में बदलाव लाया गया,
ऊर्जा के क्षेत्र में लम्बे समय तक
समान लागू होने वाले नियम को हट

सोनिया गाँधी के हाथ में होगी एनरॉन की बिजली-छड़ी

सोनिया गाँधी की अमेरिका यात्रा संयुक्त राष्ट्र महासभा को सम्बोधित करने के लिए हुई, उनकी अवकात में इस यात्रा से हुई वृद्धि को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वाशिंगटन में उनकी अगवानी अमेरिका के उप-राष्ट्रपति रिचर्ड चेनी ने की। रिचर्ड चेनी के विषय में सर्वज्ञात है कि ये एनरॉन के चेयरमैन केनेथ ले से काफी करीबी रखते हैं। केनेथ ले का अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्जबुश से भी सहयोगी का संबंध है। इसका मतलब हुआ कि एनरॉन के कारोबार के पीछे इस समय अमेरिका की ताकत खड़ी है। अर्थात् जो भारतीय राजनीतिक पार्टी एनरॉन का विरोध करेगी, उसे अमेरिका के सहयोग से वंचित रहना पड़ सकता है? सोनिया गाँधी की रिचर्ड चेनी से हुई बातचीत में एनरॉन का विषय भी आया इस पर उन दोनों ने विचार विमर्श किया। एनरॉन के प्रति सोनिया गाँधी के दिल में पैदा हुई सहानुभूति का रहस्य यही हो सकता है। इसीलिए वह कॉंग्रेस पार्टी की सरकार वाले राज्यों में एनरॉन की बिजली खरीदने का फार्मूला लागू करने में लगी है।

कॉंग्रेस शासित राज्यों में एनरॉन के पहले चरण की ८४० मेगावाट बिजली खरीदकर इनमें बाँटने के फार्मूले पर अमल होने वाला है। जिन राज्यों में बिजली की खपत कम और उत्पादन अधिक है उनमें एनरॉन की बिजली नहीं बेची जाएगी। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य को 'पॉवर स्टेट' माना जाता है, यहाँ बिजली की जरूरत नहीं होगी। लेकिन मध्यप्रदेश में बिजली का संकट रहता है इसे एनरॉन की बिजली खरीदनी पड़ सकती है। यूँ तो मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री एनरॉन की महँगी बिजली खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखते, इस पर

उनका सार्वजनिक रूप से बयान
चुका है, लेकिन सोनिया गाँधी का नि
उन्हें विवश करने के लिए पर्याप्त हो
महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री
एनरॉन की बिजली के झटके से ह
कष्ट झेलना पड़ता रहा है। अब
सोनिया गाँधी ने अमेरिकी सरकार
दबाव से एनरॉन की बिजली की छ
अपने हाथ में थाम रखी है तो
अमेरिका की कृपा प्राप्त करने के लि
अपनी पार्टी के मुख्यमंत्रियों को झट
जरूर देना चाहेगी। इससे एनरॉन
आर्थिक शोषण का जाल भारत में
फैल सकता है। और इसका दुष्परि
भारत की दुर्बल अर्थव्यवस्था को
साँस तक झेलना पड़ सकता है। इ
बाद सही मायने में देश की राजनी
विदेशियों के हाथों का चाबुक बनेगी
जनता सचमुच की रैयत।

Scanned with OKEN Scanner

बदलते बाजार भाव के अनुसार की खरीद-बिक्री का प्रावधान था। बिजली उत्पादकों के लिए उपभोक्ता खोजने वाले दलाल का भी निभायी थी।

लिफोर्निया के अधिकारी एनरॉन में बतलाते है कि बाजार को रखकर यह कंपनी बिजली में कमी कर देती हैं और बिजली बढ़ाने के लिए विवश कर देती लिफोर्निया के पॉवर ग्रिड के ने पाया कि एनरॉन की बिजली रात की सप्लाई में भी कम नहीं जबकि नियमानुसार कम आपूर्ति मूल्य में कमी आनी चाहिए। परिणाम यह हुआ कि १९९९ में र्निया का बिजली बिल ७ डॉलर का था, वह २००० तक आते ५० बिलियन डॉलर हो गया।

कैलिफोर्निया में आए बिजली के पहले वहाँ बिजली की कीमत गावाट औसतन ३० डॉलर थी। इस पहले तीन महीनों में एनरॉन ने डॉलर प्रतिमेगावाट की दर से बेची है। इसका लाभ ३२% और १.३ बिलियन डॉलर तक गया। इसका कुल वार्षिक व्यापार वर्ष १०० बिलियन डॉलर था सर्वाधिक कमाई कहा जा सकता एनरॉन इस आशा में है कि आने वर्ष में लाभ में दुगुनी वृद्धि होगी।

एनरॉन के प्रवक्ता मार्क पामर का है कि 'हमें कैलिफोर्निया के संकट का दोषी मत मानिए' यह बताते है कि एनरॉन ने केवल मूल्य पर बिजली बेंची है। इस के अधिकं होने के पीछे जटिल है। इसमें एक कारण यह भी है कैलिफोर्निया में कोई ऊर्जा संयंत्र स्थापित नहीं है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री फ्रैकवोलाक यह कहते है कि एनरॉन यह समझ चुका है कि अब यहाँ पैसे का खुला बाजार है। अब यहाँ अधिक समय तक बिजली की खरीद-बिक्री का अनियंत्रित कारोबार करना संभव नहीं होगा। इस बात को समझने में कैलिफोर्निया की सरकार विफल रही है।

एनरॉन अपने देश अमेरिका में उसी रास्ते पूरी ईमानदारी से चल रही है जिस रास्ते पर कई अमेरिकी कंपनियाँ अपने ही देश की जनता के धन का पूरी निर्दयता से शोषण करती हुई अपराधी घोषित हुई। जब एनरॉन का चरित्र जग-जाहिर है तो इसके विषय में कोई सहानुभूति पूर्वक विचार करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

एनरॉन कंपनी की अधिकतम पूँजी कागजों पर है न कि पॉवर प्लांट या पाइप लाइन जैसी बाहरी वस्तुओं में। इससे एनरॉन की पूँजी का सही-सही अनुमान लगाना कठिन है उसके सभी कारोबार के विषय में जानकारी लेना भी टेढ़ी खीर है। एनरॉन के आर्थिक चक्रव्यूह को समझना आसान नहीं है, यह कंपनी किसी को स्पष्ट नहीं बताती कि उसके पास कितना पैसा है और इन पैसों को वह किस तरह कमाती है।

अमेरिका के शेयर बाजार वाल स्ट्रीट में एनरॉन की बड़ी चलती है। इसके बावजूद कि पिछले वर्ष ८० डॉलर की तुलना में इसका मूल्य ४० डॉलर गिरकर, ५० डॉलर प्रति शेयर हो गया लेकिन ५० डॉलर पर भी एनरॉन की साख गिरी नहीं। इसका वार्षिक व्यापार लगभग २०० बिलियन डॉलर का अनुमान किया जाता है। जिसमें दिन-दूनी बढ़ोत्तरी होती चली जा रही है। ■

अवतार का अवतरण

भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसे अंतरिक्ष यान का डिजायन तैयार किया है जिसका अंतरिक्ष यात्रा में सैकड़ों बार उपयोग हो सकेगा। इससे बेहद कम लागत पर उपग्रह का प्रक्षेपण भी किया जा सकेगा। इसे रक्षा शोध एवं अनुसंधान संगठन के अंतर्गत विकसित किया जा रहा है। इस प्रयोजना के अध्यक्ष राघवन गोपालस्वामी के अनुसार अवतार का उपयोग सैकड़ों बार किया जा सकेगा और उड़ान के दौरान ईंधन यह स्वयं तैयार करेगा। विभिन्न देशों में वर्तमान में उपयोग किए जा रहे रॉकेट प्रक्षेपक एक बार उपयोग के बाद बेकार हो जाते हैं। अत: कई अन्य देशों में भी इस तरह के यान बनाने की कोशिशें हो रही हैं। अमेरिका का कोलम्बिया इसी श्रेणी का अंतरिक्ष यान है। रूस को भी इसमें सफलता मिली है। लेकिन अवतार में और अन्य यानों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर है। अवतार बाकी यानों की तुलना में हल्का है केवल २५ टन का। यह एक ही चरण में १०० कि०मी० की पहली कक्षा में पहुँच सकता है। इसमें क्रायोजेनिक इंजनों का उपयोग किया जाएगा। सौ परिक्रमा में यह अंतरिक्ष में १०० टन भार ले जा सकेगा। अवतार का ईंधन संग्रहण भी अन्य यानों से अलग है। अवतार में टेक ऑफ के लिए तरल ऑक्सीजन का संग्रह नहीं रखना पड़ता है। यह आवश्यक २१ टन आक्सीजन वातावरण से ही उड़ान के दौरान ध्वनि के वेग से आठ गुना अधिक तेजी से तैयार कर लेता है। यह ऑन बोर्ड व्यवस्था के जरिए वातावरण के वायु से आक्सीजन अलग का उसे तरलीकृत करते हैं। अवतार का उपयोग उपग्रह प्रक्षेपक के स्थान पर यात्री यान के रूप में हो सकेगा। सवारियों को लेकर यह बोइंग की भाँति उड़ान भर सकेगा। अवतार से अंतरिक्ष भ्रमण में पैसा भी कम लगेगा [डेनिस टीटो ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा के लिए कॉसमॉस (रूसी अंतरिक्ष एजेन्सी) को २ करोड़ डॉलर दिए थे] और विशेष प्रशिक्षण भी आवश्यक नहीं होगा। उम्मीद है कि अवतार अगले दस वर्षों में उपयोग में आने लगेगा। ■

Scanned with OKEN Scanner

आर्थिक मंदी कितनी भयावह

■ डॉ० रमाकांत पांडेय

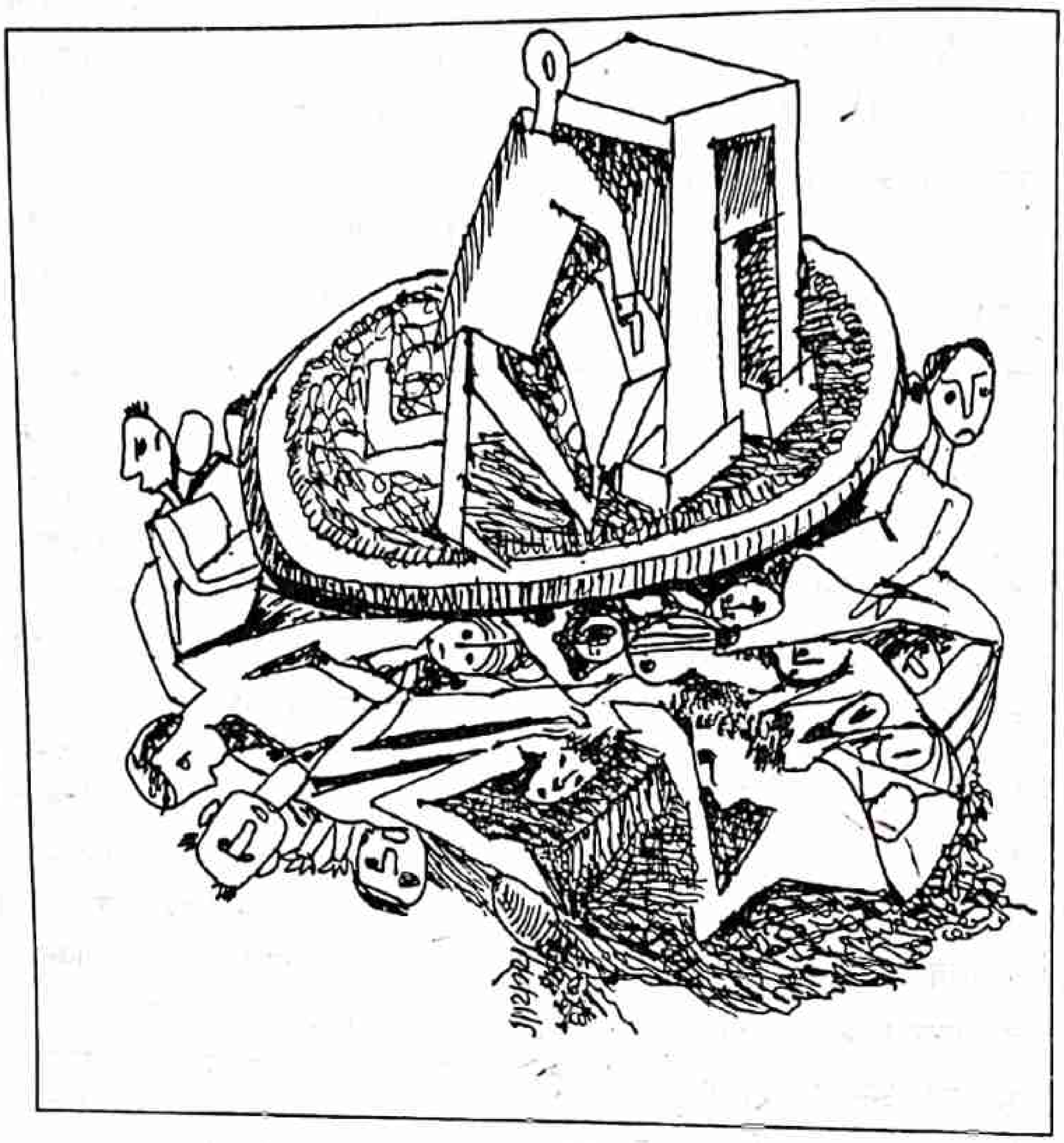

दिल्ली के इंस्टीच्यूट
इकानॉमिक ग्रोथ के
हमारी जी०डी०पी०
दर ६ प्रतिशत से घट
प्रतिशत पर आ गया
इसमें और भी गिराव
सकती है। क्योंकि अ
में ३ प्रतिशत से नीचे
से गिरावट आ रही
इसका पूरा प्रभाव भार
निर्यात पर पड़ेगा, क्यो
भारत कुल निर्यात का
प्रतिशत अमरीका को
है। भारत के कुल निय
अभी ही १०० प्रतिशत
कमी आ गयी है।

प्रत्येक देश की अपनी अर्थव्यवस्था होती है। उत्पादन, बाजार और वितरण पर उसी देश का नियंत्रण रहता है। किंतु वैश्वीकरण के कारण अगर देश की अर्थव्यवस्था पर बाहरी शक्तियों का प्रभाव पड़ने लगे तो समझना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था की चाभी गायब हो गयी है। यही स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था की हो गयी है। हम अपनी संस्कृति और प्रकृति प्रदत्त साधनों को दूसरे देश के हवाले करते जा रहे है। हाल में ही हमारे वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा है कि अमरीका में तथा विश्व के उन्नत देशों में मंदी छायी हुई है। कुछ अर्थशास्त्री इसे अल्पकालिक घटनाक्रम बता रहे हैं किंतु यह आर्थिक मंदी का चक्र चल रहा है। इसके परिणाम भयावह होंगे।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष एवं विश्व बैंक की ओर से दुनिया के औसत जी०डी०पी० की विकास दर ३.३ प्रतिशत से भी कम अर्थात् २.२ प्रतिशत पर सीमित रहने का अनुमान लगाया गया है। अमेरिका के शेयर बाजार में संकट आया तो उसका प्रभाव वहां के सभी आर्थिक क्षेत्रों पर पडा। आज अ
में कहा जाता है कि शेयर बाज
मंदी के कारण वहां बडे पैमा
छंटनी चल रही हैं। वहां की बड़ी
कंपनियां अपने कर्मचारियों की
कर रही हैं। यही स्थिति अगर भ
उत्पन्न होती है तो क्या भारत अ
के कब्जे में नहीं है? भारत में भ
तेजी से हो रही है।

भूमंडलीकृत अर्थव्यवस्था
दुनिया के उभरते बाजारों को भी
कर सकती है। अर्जेंटीना,
मलेशिया, फिलीपीन, कोरिया, ता
थाईलैंड इत्यादि में खलबलाहट
हुई है। दिल्ली के इंस्टीच्यूट
इकानॉमिक ग्रोथ के अनुसार
जी०डी०पी० विकास दर ६ प्रति
घटकर ५ प्रतिशत पर आ गय
इसमें और भी गिरावट आ सकती
क्योंकि अमेरिका में ३ प्रतिशत से

Scanned with OKEN Scanner

...वट आ रही है। इसका ...रत के निर्यात पर पड़ेगा, ...ा कुल निर्यात का १८.९ ...रीका को करता है। भारत ...त में अभी ही १०० प्रतिशत ... गयी है। मंदी का दूसरा ...कारण खुला बाजार और ...ओं का प्रत्यक्ष एंव अप्रत्यक्ष ...पभोक्ता का विश्वास देश ...ओं पर से समाप्त हो रहा ...ी वस्तुओं के प्रति आकर्षण ...उदाहरण स्वरूप सन् २००० ...त में कार की बिक्री ५७ ...थी और २००१ में मात्र ७ ...इसी प्रकार इस्पात का ...गया हुआ है। औद्योगिक ...०० में ४.९ प्रतिशत था जो ...अब मात्र २.८ प्रतिशत रह ...०१ के जनवरी में यह गत ...ट अनुमान से आधा हो गया ...में प्रतिवर्ष १० प्रतिशत की ...ी, ऐसा अनुमान भारतीय ...पार संस्थान दिल्ली का है। ...क देश में बचत दर जो दो ... प्रतिशत थी, वह घटकर ... रह गयी है।

...में बेरोजगारी तेजी से बढ़ ...तिवर्ष हमारा रोजगार दर जो ...दशक में ६.४ प्रतिशत था वह ...र २००१–०२ में मात्र ०.८ ...ह गया है। सरकार ने नये ...जन की जिम्मेवारी प्रायः निजी ...ड़ दिया है। यह एक भयावह ... कृषि क्षेत्र में रोजगार का ...अवसर था। ५५वें राष्ट्रीय ...अनुसार कृषि में १९९३–९४ ...मिलियन लोग रोजगार में थे। ...०० में उनकी संख्या घटकर ...यन रह गयी। निर्माण उद्योग ...में जहां अशिक्षित नवयुवक ...यरत रहे है वहां गत १० वर्षों

देश में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है। प्रतिवर्ष हमारा रोजगार दर जो १९९० के दशक में ६.४ प्रतिशत था वह अब घटकर २००१-०२ में मात्र ०.८ प्रतिशत रह गया है। सरकार ने नये रोजगार सृजन की जिम्मेवारी प्रायः निजी क्षेत्र पर छोड़ दिया है। यह एक भयावह स्थिति है। कृषि क्षेत्र में रोजगार का सर्वाधिक अवसर था।

में मात्र ३.७ मिलियन नवयुवक लगे हुए है। निर्माण उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि ५.५ प्रतिशत हुआ है, वही रोजगार में वृद्वि मात्र एक प्रतिशत हुई है। यह विश्लेषण राष्ट्रीय आर्थिक परिषद् भारत सरकार का है। केवल होटल एवं सेवा क्षेत्र में कुछ रोजगार के अवसर बढ़े हुए हैं किंतु यहां भी आकस्मिक मजदूर रखे जाते है। अगर यही स्थिति रही तो २०१० के अंत तक ७० मिलियन शिक्षित नवयुवक उपाधियों की सर्टिफिकेट लेकर शहरों में आश्रय खोजने आएंगे। जिससे वहां की आबादी बेतहाशा बढ़ेगी।

बैंकिंग क्षेत्र में गिरावट चौतरफा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारियो की छँटनी योजना लागू है। स्वैच्छा से अवकाश प्राप्त करने की योजना दबावपूर्वक अमल में है। "मशीन लाओ, मनुष्य भगाओ" का सिद्धांत काम कर रहा है। गत ६ वर्ष (१९९४ से) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जमा में ९.८३ प्रतिशत की कमी आयी है। सिंडीकेंट बैंक का १० रूपया का शेयर ९.२५ रूपया कर कोट किया गया। ऐसी परिरिथति में देशी बैंक अवश्य ही कमजोर पड़ेंगे। एन०पी०ए० (गैर निष्पादक आस्तियाँ) जो १९९६ में १८,६६१ करोड़ रूपया थी वह २००० में ६०,८४१ करोड़ रह गयी। एन०पी०ए० की समस्या के समाधान के लिए रिजर्व बैंक ने सार्वजनिक बैंकों के लिए एक मुस्त समाधान का फार्मूला जारी किया है जो ३१ मार्च २००१ को समाप्त होना था किंतु उस योजना को सितंबर २००१ तक बढ़ाया गया है। इस योजना के बावजूद एन०पी०ए० के समाधान में रिजर्व बैंक को सफलता नहीं मिली। ३५.६३ लाख ऋण धारकों ने समाधान पर ध्यान नहीं दिया। मात्र ६ लाख ऋणी से केवल रूपया ३,४००० करोड़ ३१ मार्च २००१ तक वसूल हुआ। इस तरह हम देखते हैं कि एन०पी०ए० का समाधान निकल नहीं रहा है। अभी भी एन०पी०ए० कुल जमा राशि का १० प्रतिशत से अधिक है।

रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूँजी अनुपात जो ९ प्रतिशत है, वह भी पूरा करना बैंकों के लिए कठिन है। बैंक आवश्यक क्षेत्र को छोड़कर जोखिम रहित विनियोग पर अधिक जोर दे रहे है। कुल विनियोग का ३७ प्रतिशत विनियोग जोखिम रहित क्षेत्र में बैंक कर रहे हैं। इसका भी प्रभाव आर्थिक संरचना पर पड़ेगा। रिजर्व बैंक ने मार्च २००० में एक सुझाव दिया था कि प्रत्येक बैंक १८ महीने के अन्दर एक जोखिम प्रबंध समिति बना लें। इस समिति का उद्देश्य यह है कि प्रत्येक बैंक वित्तीय बाजार के जोखिम पर नजर

Scanned with OKEN Scanner

रखें। प्रायः इस प्रकार की समिति बैंकों में है। परंतु यदि बाजार में यदि छुपे रूस्तम ढंग से कोई घटना उच्च स्तर पर होगी तो समिति क्या कर सकती है। उदाहरण के लिए मार्च २००१ में जो विनिमय बाजार की घटना घटी तो उस परिस्थिति में समिति जाँच ही कर सकती है। जोखिम रोकना दूर की बात होगी। जोखिम प्रबंध लेखाशास्त्र का विषय है, परंतु यह उच्च स्तरीय घोटालों को नहीं रोक सकता है। जहाँ तक रूपये के अवमूल्यन का प्रश्न है, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक संदेश है। मार्च २००१ में एक डालर का दाम ४७.१० रूपया था । यह अपने आप में एक विचित्र स्थिति उत्पन्न करता है। १६ अप्रैल को रिजर्व बैंक के गर्वनर ने कहा था कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। उनकी आवाज में आवाज मिलाते हुए वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा था कि रूपये का अवमूल्यन एशिया की अन्य मुद्राओं की दृष्टि से देखना चाहिए। किंतु हम लोग भारतीय दृष्टि से देखते है तो लगता है कि दाल में काला है। खोटी नीयत से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती है। देश के कई लोगों ने यहाँ तक कह दिया है कि सरकार ही रूपये का मूल्य गिराना चाहती है। यही कारण था कि बैंक और आयात करने वाले व्यापारी डॉलर खीरदने लगे क्योकि उनको अंदाज हो गया था कि डॉलर का मूल्य और बढ़ेगा।

किंतु इस सबंध में यह जानने की जरूरत है कि जब देश में डालर अधिक आ रहा है, विदेशी मुद्रा का भंडार बढ रहा है तो रूपये का मूल्य क्यों गिर रहा है। यह कहना कि भारतीय निर्यात को बढ़ाने के लिए रूपये का अवमूल्यन आवश्यक है तो यह धारणा आर्थिक दृष्टि से गलत है। अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है कि आंतरिक साधन बढ़ाये जाए क्योंकि जब देश की अर्थव्यव्स्था डूबने लगती है तो बाहरी शक्तियाँ उसे गिद्ध दृष्टि से देखती है। अंतिम समय का ऋणदाता कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था भूमंडलीकरण के कारण डरावनी होती दिखाई पड़ रही है। यह अकारण नहीं है। अर्थव्यवस्था के कुछ खास नियम है जिनकी अवहेलना करने पर वह डाँवाडोल हो जाती है। विश्व की सबसे बडी आर्थिक ताकत [illegible] मंदी की मार से ग्रस्त है इसलिए आर्थिक आधित्पय विश्व के जि[illegible] मुल्कों पर है वे भी इस [illegible] अछूते नहीं रहे सकते हैं। [illegible] बड़ी–बड़ी कंपनियाँ अपने कर्म[illegible] की छंटनी कर रही है। भारत[illegible] आर्थिक मंदी अब स्टॉक एक्स[illegible] निकलकर देश के दूर–दराज [illegible] फैल रही है। यह खतरनाक [illegible] बीमारी है।

कर्मचारियों में कटौती क[illegible] अभिप्राय कम उत्पादन होता है। [illegible] अर्थ है कि औद्योगिक इका[illegible] उत्पादन की मात्रा कम कर[illegible] उत्पादन में कटौती का मतलब [illegible] बिक्री में गिरावट। बिक्री में गिरा[illegible] सीधा अर्थ है कि आम उपभोग[illegible] क्रय शक्ति में कमी । क्रय शक्ति [illegible] कम होती है जब आय कम हो[illegible] क्रय शक्ति की कमी और आर्थि[illegible] में गहरा संबंध है। अर्थशास्त्री [illegible] लिखा है कि "बाजार में जब वा[illegible] मांग अनुमान के स्तर से नीचे [illegible] तो उत्पादन की मात्रा एवं श्रमि[illegible] संख्या में कटौती करनी पडती है[illegible]

मांस खाने से कैंसर होने की संभावना अधिक

मांसाहार करने वालों को सिर्फ डराने के लिए नहीं यू.एस. नेशनल कैंसर इन्स्टीच्यूट के डॉक्टर आर्थर सेजकिन यह कहने पर तुले हुए है कि मांस खाने से बीमारी की संभावना अधिक होती है ताजा और लाल मांस खाना भी कैंसर को बुलावा देने के समान है। पहले से संचय करके रखा हुआ मांस खाने से आंत का कैंसर होने की संभावना ५०% अधिक होती है। मतलब यह है कि दो साल से फ्रिज करके रखी गई मुर्गी की टांगे यदि अमेरिका से भारत में अनेक मांसहारी अददों के साथ बिकने आतीं हैं तो उन्हें खरीद खाने वालों के रोगी होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

यूँ तो नई-नई खोजों का दौर चल रहा है जिसके आधार आज के विश्व के वैज्ञानिक कहने लगे है कि खान-पान की प्रतिकूलता कई बीमारियों का कारण होती है। दक्षिण ग्रीस और उत्तरी नार्वे के लोगों पर हुए अध्ययन में पाया गया कि कैंसर का प्रमुख कारण आहार की गड़बड़ी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है।

मांसाहार से कैंसर होने की सं[illegible] पर कार्य कर रहे वैज्ञानिक मांस [illegible] की विधि, उसे पकाने का समय [illegible] मांस काटने के तरीके को अपने [illegible] का आधार बना रहे हैं। कुछ शोध-का[illegible] ने यह पाया है कि तले हुए अधपके मांस से कैंसर की संभा[illegible] अधिक होती है।

प्रोफेसर मार्टिन वाइज मैन [illegible] मानना है कि मांस ताजा हो या [illegible] किया हुआ यह दोनों प्रकार से [illegible] बीमारियों के लिए उत्तरदायी होता [illegible] इससे हम सभी को बचना चाहिए[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

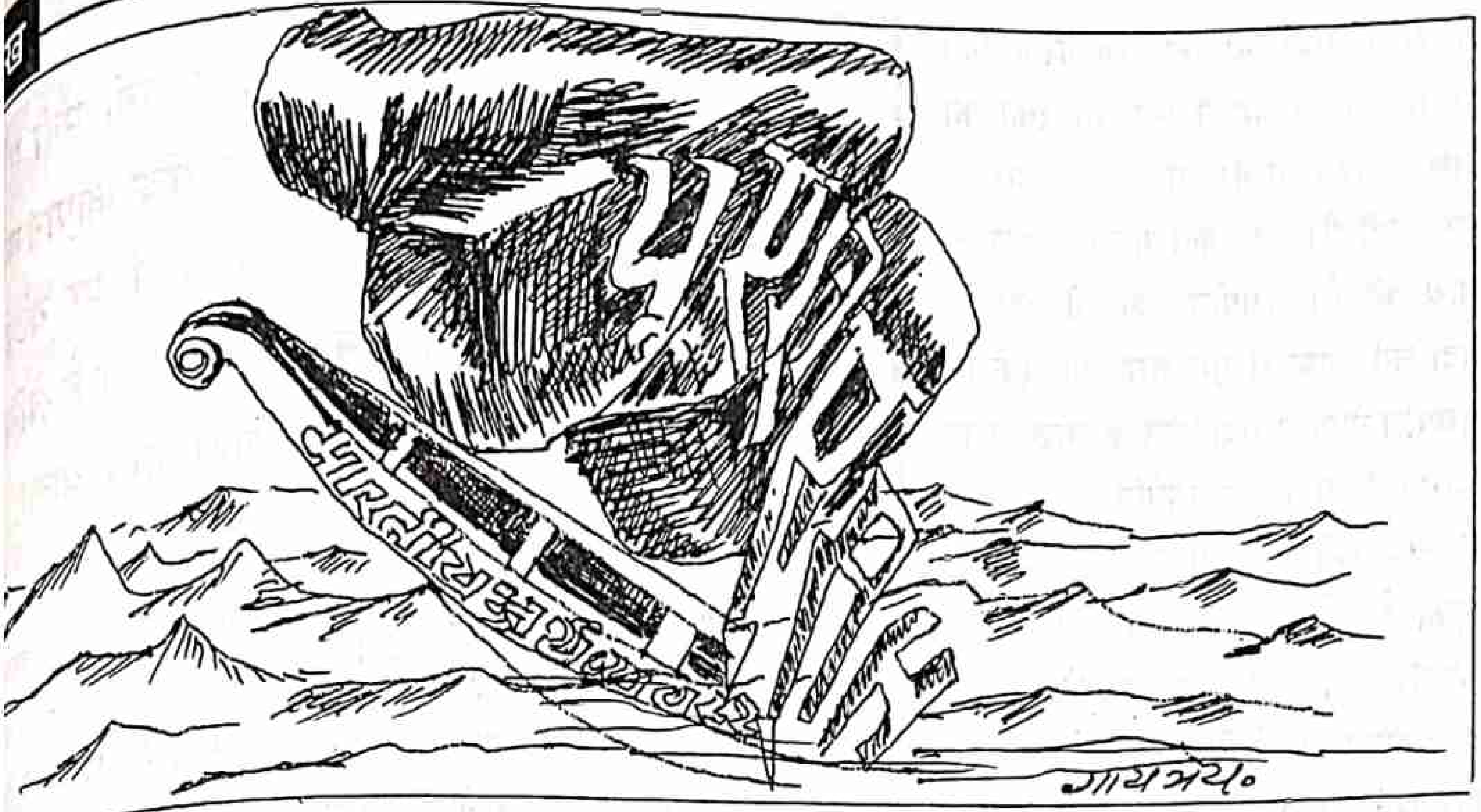

ं अमरीका की मंदी भारत को न डूबा दें

विकसित देशों की हालत बिगड़ रही है। अमरीका के लिए कुबेर के ख़जाने के सिलीकन वैली धीमे-धीमे पिघल रही है। वहाँ बेरोजगारी तेजी से फैलती जा रही छले एक वर्ष में सॉफ्टवेयर का व्यवसाय आधाा रह गया है। सिलीकॉन वैली में पैसा वाले गायब हो रहे हैं और अपना निवेश वापस निकालने वाले बढ़ गए हैं. . . .

म उपाध्याय

Iवधान पश्चिम की मंदी एशिया पर छाने वाली है। बड़े ही कुटिल और ी तरीके से अमेरिका और देश अपने पैरों पर खड़े हो रहे देशों को फिर से लंगड़ा बनाने हैं। उनका मकसद साफ है। वे देशों के बाजार से एक बार फिर डॉलर खींच कर अपनी स्थिति रना चाहते हैं। जैसा कि वे ण के दस वर्षों में १५ बार कर पश्चिम के ये देश एशियाई देशों ोहण सकारात्मक तरीके से नहीं ते। व्यापार और उद्योग के जरिए ा करने में दशक जाया करने होंगे। जो कि उनके अनुसार तेज तर्रार आर्थिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। इसलिए वे एशियाई देशों के बीच दहशत फैलाकर, बाजार में अफरा-तफरी मचाकर और आम आदमी में भय पैदा करके अपनी थाती भरना चाहते हैं। यह कोई संयोग नहीं है कि जब-जब विकसित देशों की आर्थिक स्थिति बिगड़ती है उसके दो चार माह बाद विकासशील देशों में हादसे शुरू हो जाते हैं। औद्योगिक उत्पादन गिरने लगता है, निर्यात घटने लगता है। शेयर बाजार टूटने लगता है। मुद्रा बाजार की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। डॉलर लुप्त होने लगता है तथा येन और रुपए मरनासन्न स्थिति में पहुँच जाते हैं।

फिर से विकसित देशों की हालत बिगड़ रही है। अमेरिका के लिए कुबेर के खजाने के समान सिलीकन वैली धीमे-धीमे पिघल रही है। वहाँ बेरोजगारी तेजी से फैलती जा रही है। पिछले एक वर्ष में सॉफ्टवेयर का व्यवसाय आधा रह गया है। सिलीकॉन वैली में पैसा लगाने वाले गायब हो रहे हैं और अपना निवेश वापस निकालने वाले बढ़ गए हैं। कारण यह है कि सिलीकॉन वैली के सॉफ्टवेयर की मांग कम हो चुकी है। कंप्यूटर और इलैक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्माण करने वाली कंपनियाँ उत्पादन या तो बंद कर रही हैं या कम कर रही हैं। यूरोपीय देशों

Scanned with OKEN Scanner

के साथ अमेरिका का व्यापारिक हित टकरा रहा है। पहली बार अमरिका की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। यही बात यूरोपीय देशों के साथ भी है। यूरोपीय देश भी आर्थिक मंदी की चपेट में पूरी तरह आ चुके हैं। यूरोपीय देशों में मंदी छाने के कुछ अलग कारण है। वहाँ मुद्रा स्फीति की दर तेजी से चढ़ रही है। श्रम काफी महंगा हो चुका है और तेल के दाम तेजी से बढ़ रहे है। हाल ही में यूरोप के केंद्रीय बैंक ने अशंका जताई है कि समूचे यूरोप में इस वर्ष विकास दर में काफी गिरावट आएगी। बैंक के अनुसार वर्ष २००१-२००२ में यूरोपीय देशों की विकास दर २.२ फीसदी होगी, जबकि दो वर्ष पूर्व २००० में यूरोपीय यूनियन की विकास दर ३.४ फीसदी की थी। बैंक की यह भी आशंका है कि जिस तरह से मंदी का दौर जारी है उससे यूरोपीय देशों में अगले साल २ फीसदी से भी कम विकास दर रह जाएगी। यूरोप और अमरीका के लिए यह बेहद संकटकालीन स्थिति है। उससे निपटने के लिए विकासशील देशों का खासकर एशियाई देशों का दोहन अनिवार्य बन गया है। उनके सामने दो ही विकल्प हैं या तो वह एशियाई देशों की ओर अग्रसर हो चुके विदेशी निवेशकों को अपनी ओर खींचे या फिर अपने एजेंटों या अपनी कंपनियों के जरिए एशियाई देशों की पूँजी उड़ा ले जाएँ।

अभी तक यह परंपरा बन चुकी है कि जब कभी भी विकसित देश आर्थिक संकट में फँसे हैं एशियाई देशों के खून से ही अपनी अर्थव्यवस्था में जान डाल सके हैं। जैसा कि अभी तक होता आया है कि विकसित देश खासकर अमरीका और यूरोप एशियाई देशों में फैले अपने दमनकारी पंजे को फैला कर विकसित देशों को निचोरते आए हैं। वैसा ही माहौल फिर बनाया जा रहा है। एक नहीं कई माध्यमों से अमेरिका और यूरोप की मंदी एशियाई देशों में पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। इस काम में विकसित देशों की कई एजेंसियाँ लगी हैं। कुछ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है तो कुछ तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विश्लेषक। यह डर पैदा किया जा रहा है कि पूर्वी एशियाई देशों के बाजार एक बार फिर टूटने जा रहे हैं। लंदन से निकलने वाली पत्रिका द इकोनौमिस्ट ने लिखा है कि अमेरिका के सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के बिखरने के कारण पूर्वी एशियाई देशों में फिर से भयानक मंदी आने वाली है। द इकोनौमिस्ट पत्रिका लिखती है कि पूर्वी एशियाई देशों का निर्यात मुख्य रूप से अमरीका पर टिका है। इसलिए अमेरिकी बाजार में मंदी का सीधा असर एशियाई देशों पर पड़ेगा ही। पत्रिका के अनुसार इलैक्ट्रॉनिक वस्तुओं के क्षेत्र में सुपर पावर सिंगापुर, ताइवान और थाईलैंड में मंदी पैर पसार चुकी है। जापान पहले से ही मंदी के चपेट में है। सिंगापुर का औद्योगिक उत्पादन ११ फीसदी गिर चुका है। साऊथ कोरिया और हांगकांग में विकास दर दो से तीन फीसदी पर ही सिमट जाएगी। चाईना को छोड़ सभी पूर्वी एशियाई देशों के बाजार ध्वस्त होने के कगार पर पहुँच चुके हैं। अमेरिका से प्रकाशित वाल स्ट्रीट जर्नल ने तो भारत

> **आखिर क्यों यूरोप और अमेरिका अपनी मंदी एशि देशों पर थोपने की कोशिश में है। जबकि जापान को बाकी एशियाई देशों में आर्थिक मोर्चे पर कोई अफरा-तफरी नहीं है। जापान में मंदी जरूर है लेकिन पर अमेरिकी बाजार का असर नहीं होने वाला.....**

के खिलाफ जमकर जहर उगला
स्ट्रीट जर्नल ने अपने आकलन
है कि भारत निवेश करने ला
नहीं है। दस साल के उदारीकरण
भी भारत में अभी तक २४.४
डॉलर का ही निवेश हो सका है
चाईना को हर साल इससे ज्याद
निवेश प्राप्त होता है। वॉल स्ट्री
का कहना है कि भारत किसी
में ७ से ९ फीसदी की विकास
नहीं कर सकता जब तक कि
डॉलर की सालाना विदेशी निवे
न हो। जर्नल ने एनरॉन को मुद्द
भारत की नकारात्मक तस्वीर पे
में कोई कसर नहीं छोड़ी है।
लिखता है कि एनरॉन के प्रति
नजरिए से साफ हो गया है
विदेशी निवेश सुरक्षित नहीं है।
की इनसीजिनीया ग्रुप के एशिय
के प्रमुख अधिशासी अधिकारी
रॉबिंसनस ने भी कहा है कि
की मंदी का असर भारत पर जरू
भारत को भी इसका खामियाजा
ही पड़ेगा। क्योंकि भारत का
निर्यात काफी हद तक अमेरि
निर्भर है। अमरिकी मंदी का अ
होगा कि भारत अपने निर्यात ल
पूरा ही नहीं कर पाएगा।

आखिर क्यों यूरोप और
अपनी मंदी एशियाई देशों पर थो
कोशिश में है। जबकि जापान

Scanned with OKEN Scanner

...ई देशों में आर्थिक मोर्चे पर
...अफरा-तफरी नहीं है। जापान
...र हैं लेकिन उस पर अमेरिकी
...ा असर नहीं होने वाला। चीन
...ी स्थिति में अमेरिका और
...बाजार का मुकाबला करने को
... आठ फीसदी विकास दर के
...न किसी भी विकसित देश के
...बढ़कर बात करने की हिम्मत
...ता है। लेकिन खतरा भारत पर
...ं भारत पर अमरीका हावी है।
...बाजार पर उनका नियंत्रण तो है
... निर्धारकों पर भी अमरीकी
...का खासा असर है। आज भी
... अमेरिकी संस्थागत निवेशकों
...ा और उनका निवेश सबसे
...है। इसलिए अमेरिका अपनी मंदी
...र आसानी से थोप सकता है।
...की भी स्थिति डवाडोल है। वहाँ
...द्योगिक इकाईयाँ सिंगापुर छोड़
...ार जगह तलाशने में लगी है।
...चीन-जापान को छोड़ छोटे-छोटे
...शियाई देश अमेरिकी और यूरोपीय
... चंगुल में फँस सकते हैं। ऐसा
... नहीं कई बार हो चुका है। अभी
... साल पहले १९९७-९८ में भारत
...र्वी एशियाई देश भयंकर मंदी का
...ख चुके हैं। १९९५-९६ की
... मंदी ने भी हमें अमरीका के
...त-मस्तक कर दिया था।

...मेरिका और यूरोप आखिर क्या
... करना चाहते हैं यह सबको पता
...रिका और यूरोपीय देश जानते हैं
...क कृत्रिम और थोपी हुई मंदी के
...ह भारत और छोटे एशियाई देशों
...ों डॉलर निकाल सकते हैं और
...स्थिति सुदृढ़ कर सकते हैं। उनके
...सबसे कमजोर और कोमल शिकार
...ई देशों के शेयर बाजार और मुद्रा
...है। जिन पर लगभग उनका कब्जा

> ***यह मंदी की लहर कृत्रिम होगी। इसके पीछे एक खास मकसद होगा। मंदी की इस आँधी के पीछे अमेरिका और यूरोप का साझा प्रयास होगा। क्योंकि दोनों महाद्वीप इस बात पर लगभग सहमत हो चुके हैं कि आपसी मतभेदों को भुलाकर विकसित देशों के पूँजी रोहण का अभियान जारी रखा जाए।***

है। पिछले पंद्रह महीनों में ही भारतीय शेयर बाजार से विदेशी संस्थागत निवेशक चार लाख पचास करोड़ रुपए निकाल चुके हैं और ये सारे पैसे टैक्नोलॉजी और सूचना उद्योग के शेयर से निकले हैं। अभी डेढ़ साल पहले भारत के शेयर बाजारों में सूचना संचार और मीडिया के शेयरों की भागीदारी ५५ फीसदी हुआ करती थी, लेकिन अब यह भागीदारी घटकर ३० फीसदी रह गई है। यानि पिछले डेढ़ साल में ही सूचना, मीडिया और संचार क्षेत्रों में लगे २५ फीसदी निवेश बाहर चले गए। सबको पता है कि इन क्षेत्रों के शेयरों पर अमरीका का कितना कब्जा है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी और नासदाक शेयर बाजार का टूटना सबसे ज्यादा भारत को महंगा पड़ा है। नासदाक शेयर बाजार अमरीका का वह बाजार है जहाँ सिर्फ सूचना, संचार और मीडिया के शेयर ही सूचीबद्ध होते हैं। इस शेयर बाजार में भारत की कई नामी-गिरामी कंपनियाँ हाथ जला चुकी हैं। विप्रो, इंफोसिस जैसी कंपनियों का तो कुछ नहीं गया, लेकिन इनके चढ़ते शेयरों में पैसा लगाने वाले भोले-भाले भारतीय अपना सब कुछ लूटा चुके हैं।

अमेरिकी और यूरोपीय एजेंसी जिस अभियान में लगी है उससे तो लगता है कि नवंबर तक पूर्वी एशियाई देशों में मंदी की एक लहर जरूर आएगी। यह मंदी की लहर कृत्रिम होगी। इसके पीछे एक खास मकसद होगा। मंदी की इस आँधी के पीछे अमेरिका और यूरोप का साझा प्रयास होगा। क्योंकि दोनों महाद्वीप इस बात पर लगभग सहमत हो चुके हैं कि आपसी मतभेदों को भुलाकर विकसित देशों के पूँजी रोहण का अभियान जारी रखा जाए। नवंबर तक मंदी आने की आशंका इसलिए भी है कि दोहा में नवंबर में ही विश्व व्यापार संघ यानि डब्ल्यू.टी.ओ. की बैठक होने वाली है। इस बैठक में नए दौर के समझौते पर अंतिम निर्णय होने वाले हैं। विकासशील देश नए दौर की बातचीत के लिए तैयार नहीं है। विकासशील देशों की ओर से भारत ही मोर्चा संभाल रहा है। इसलिए अमरीका और यूरोप के निशाने पर भारत ही होगा। डब्ल्यू.टी.ओ. के डायरेक्टर जनरल माइक मूरे पहले से ही यह भूमिका बना रहे हैं कि नए दौर की बातचीत के मसौदे और नए दौर के समझौते विकासशील देशों के विकास को ध्यान में रखकर ही तैयार किए जाएँगे। १६ मई को ऑर्गनाइजेशन फॉर कोऑपरेशन फोर डेवलपमेंट की मंत्री स्तरीय बैठक में अमेरिका और यूरोप इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि नए दौर की बातचीत और नए दौर के समझौते होने चाहिए। निश्चित तौर पर नए दौर की बातचीत विकासशील देश नहीं चाहते। जब तक उन पर दबाव नहीं डाला जाता या मजबूर नहीं किया जाता तब तक विकसित देशों के जाल से बचने की कोशिश करते रहेंगे। अमेरिका और यूरोपीय देश भी यह जानते हैं इसलिए मंदी निर्यात करने की जुगत में लगे हैं। ताकि हाहाकार करते बाजार के भय से भारत समेत सभी विकासशील एशियाई देश विकसित देशों के षड़यंत्र को जानते हुए भी उसमें फँसने को मजबूर हो।■

Scanned with OKEN Scanner

सरकार द्वारा योजना निर्माण में सभी पक्षों एवं वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु एक दृष्टिकोण पत्र चर्चा के लिए प्रस्तुत किया गया। जून तक सभी तरह के सुझाव आने के बाद जुलाई के शुरू सप्ताह में योजना-आयोग के सदस्यों की बैठक में प्रधानमंत्री ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया हैं।

दसवीं पंचवर्षीय योजना : लक्ष्य की मरीचिका

■ विद्यानंद आचार्य

यो जनागत विकास अर्थव्यवस्था को पूरे पचास वर्ष हो १९५१ में प्रथम पंचवर्षीय शुरुआत तत्कालीन सरकार उम्मीद से की गयी थी कि वाले पचास वर्षों में पंचवर्षीय अनुरूप विकास प्रक्रिया चल भारत आर्थिक रूप से समृद्ध महाशक्ति के रूप में स्थापि पचास वर्ष पूरे होने के योजना-आयोग में पिछले कुछ दसवीं पंचवर्षीय योजना को स्वरूप देने पर विचार चल सरकार द्वारा योजना निर्माण में स एवं वर्गों की भागीदारी सुनिश्चि हेतु एक दृष्टिकोण पत्र चर्चा प्रस्तुत किया गया। जून तक सभी सुझाव आने के बाद जुलाई के सप्ताह में योजना-आयोग के सद बैठक में प्रधानमंत्री ने इस पर कर दिया है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना का वर्ष २००२ एवं समाप्ति वर्ष २०० वर्तमान में चल रही नवी पंचवर्षीय का कार्यकाल १९९७-२००२ तक अगर एक नजर हम वर्तमान योजना के निर्माण के साथ निर्धा गए लक्ष्यों की ओर देखें और आ समाप्ति वर्ष पर कितना लक्ष्य हुआ, यह भी देखें तो तस्वीर स पाएगी।

नवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष

१. खाद्य उत्पादों को दोगुना करना आने वाले १० वर्षों में भार से मुक्ति' पा सके।
२. सामाजिक अवसंरचना का एवं विकास जैसे, पेयजल,

, स्वास्थ्य, सफाई आदि। नवी
वीं योजना के अंत तक सभी
को पेयजल उपलब्ध कराना।
ढ़ अवसंरचना का विकास एवं
त उदाहरणार्थ – बिजली, तेल,
, यातायात, बंदरगाह, टेली का
र आदि।
त राजस्व नीति का अनुपालन,
केंद्र, राज्य एवं सार्वजनिक
ों सहित सरकार के राजस्व घाटे
मी लाया जा सके।
य जल नीति एवं सूचना प्रौद्योगिकी
प्राथमिकता देना।

पंचवर्षीय योजना पूरा होने को
भी घरों तक पेयजल की आपूर्ति
न बन कर रह गया। शिशु मृत्यु दर
सुधार नहीं हुआ है। अपितु यह ७२
०० के स्तर पर स्थिर है। इतना ही
ीण क्षेत्रों में करीब ६० प्रतिशत
री क्षेत्रों में २० प्रतिशत घरों में
की आपूर्ति नहीं है। स्वच्छता,
प्रदूषण में कहीं भी सुधार नहीं है।

ज़ादी के पचास वर्ष पूरा होने बाद
चवर्षीय दृष्टिकोण से सोचा जाए
दसवीं पंचवर्षीय योजनाकाल है।
राजनीतिक कारणों से होने वाले
वर्तन एवं अन्य कारणों से अनेक
वर्षीय योजना को छोड़कर वार्षिक
ं अपनानी पड़ी। (बॉक्स में देखें)

...रण एवं पंचवर्षीय योजना

...दारीकरण का एक दशक पूरा हो
। भारत जैसे विशाल आबादी वाले
दस वर्ष का समय पर्याप्त नहीं भी
भी लेकिन कम मान कर आँकना
होगा। सरकार अगर एक ही
ति पर जोर देकर दृढ़ रहे तो उस
से हुई प्राप्ति या हानि का मूल्याँकन
ता है। लेकिन बदली नीतियों की

दसवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य

- गरीबी अनुपात को घटाकर २००७ तक २० प्रतिशत एवं २०१२ तथा १० प्रतिशत करना।
- नए श्रमशक्ति को लाभकारी रोजगार उपलब्ध करना।
- २००७ तक सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करना।
- दस वर्षीय जनसंख्या वृद्धि को घटाकर १६.२ प्रतिशत करना।
- २००७ तक साक्षरता दर को बढ़ाकर ७२ प्रतिशत एवं २०१२ तक ८० प्रतिशत करना।
- शिशु मृत्यु दर को घटकर २००७ तक प्रति हजार ४५ करना एवं २०१२ तक यह २८ करना।
- मातृ मृत्यु दर को भी २००७ तक प्रति हजार २० करना एवं २०१२ तक १० करना।
- जंगल एवं पेड़ों का क्षेत्रफल २००७ तक बढ़ाकर २५ प्रतिशत एवं २०१२ तक बढ़ाकर ३३ प्रतिशत करना।
- २०१२ तक सभी गाँवों को पीने योग्य पानी उपलब्ध करना।
- २००७ तक सभी नदियों को प्रदूषण मुक्त करना।

दशा में मूल्यांकन करना आसान नहीं। एक दशक में एशियाई टाईगर बनने वाले देश देखते ही देखते दो साल के भीतर ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गए। वर्तमान अर्थनीति के इस चौराहे पर पहुँचने के साथ दसवीं पंचवर्षीय योजना का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह देश की विडम्बना ही है कि आजादी के समय जो सरकार सत्ता में आयी, उसने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया एवं मोटे तौर पर पूर्ण समाजवादी व्यवस्था को लेकर नहीं चल पायी। फिर भी रूस से आयातित पंचवर्षीय योजना को अमल में लाने के पीछे के उद्देश्यों का पता नहीं चल पाता

अतिउत्साह में आकर योजना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष एवं देश के प्रधानमंत्री ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के विकास दर का लक्ष्य ९ प्रतिशत घोषित कर दिया। उनका इस घोषणा के पीछे तर्क यह था कि तकनीकी रूप से यह संभव हो सकता है......

है। एक तरफ भारत सरकार १९९१ से आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया चला रही है, फिर भी उसने पंचवर्षीय योजना द्वारा होने वाले विकास का नियंत्रण एवं निर्धारण अपने हाथ में रखी है। वास्तव में देखा जाए तो यह लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु संविधान में उल्लिखित प्रावधानों को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।

ज्ञातव्य है कि देश में जब तक सामाजिक आर्थिक विषमता व्याप्त है, देश के गाँवों-गाँवों तक आधारभूत अवसंरचना का निर्माण नहीं हो जाता, पंचवर्षीय योजना चलाना आवश्यक होगा।

विकास दर का दुर्लभ लक्ष्य

नवी पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में हालाँकि ७ प्रतिशत वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था। किंतु वास्तव में यह लक्ष्य नहीं प्राप्त हो सका। योजना के पहले दो वर्षों में घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय स्थितियों के कारण लक्ष्य में कमी करना अनिवार्य हो गया। वर्ष १९९७-९८ में अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर कम होकर ५.१ प्रतिशत हो गई एवं अगले वर्ष थोड़ा सुधार के बाद

Scanned with OKEN Scanner

पुन: १९९९-२००० में कम होकर ५.९ प्रतिशत पर स्थिर हो गई।

अगर उपयुक्त पृष्ठ भूमि में हम दसवीं पंचवर्षीय योजना को देखते हैं तो यह स्पष्ट मत बनता है कि ८ या ९ प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करना सर्वथा असंभव है। अगर पिछले चार-पाँच पंचवर्षीय योजना के विकास दर पर एक नजर डालें तो दसवीं पंचवर्षीय योजना में अचानक ८/९ प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त करना जादुई करिश्मा के बिना संभव नहीं।

योजना	कार्यकाल	विका[illegible] प्राप्त [illegible]
चौथी	१९६९-१९७४	[illegible]
पाँचवीं	१९७४-१९७९	[illegible]
छठी	१९८०-१९८५	[illegible]
सातवीं	१९८५-१९९०	[illegible]
आठवीं	१९९२-१९९७	[illegible]
नवीं	१९९७-२००२	[illegible]
दसवीं	२००२-२००७	[illegible] ८% अनुम[illegible]

ज्ञातव्य है कि अतिउत्साह में आकर योजना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष एवं देश के प्रधानमंत्री ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के विकास दर का लक्ष्य ९ प्रतिशत घोषित कर दिया। उनका इस घोषणा के पीछे तर्क यह था कि तकनीकी रूप से यह संभव हो सकता है यदि आने वाले दस वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुना करना संभव हो सके। जनसंख्या के वर्तमान १.६ प्रतिशत वृद्धि पर तादात्म्य मिलाने पर सकल घरेलू उत्पाद के वृद्धि दर की आवश्यकता ८.७ प्रतिशत के करीब लाना आवश्यक है। इसी आधार पर प्रधानमंत्री ने ९ प्रतिशत विकास दर के लक्ष्य की घोषणा कर दी। नवीं पंचवर्षीय योजना की लब्ध सूची से दसवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य प्राप्ति का अनुमान एक सामान्य व्यक्ति भी लगा सकता है।

सरकार को स्वयं भय है कि ८ प्रतिशत की विकास दर हासिल करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्रों की क्षमता का पूर्ण उपयोग एवं राजनीतिक स्थिरता आदि आवश्यक है। अर्थात् सरकार के पास इन सबको नियंत्रित करने की कोई जादुई छड़ी नहीं है अत: लक्ष्य न प्राप्त होने की स्थिति में इन्हीं कारणों का रोना रोया जाएगा। ज्ञातव्य है कि वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा था कि निजी क्षेत्र के पास जी०डी०पी० वृद्धि को गति प्रदान करने की अपार क्षमता है। अत: मैं योजनागत मद में कटौती करना वाजिब समझता हूँ। उन्होंने ऐसा किया भी। लेकिन, घोषणा के ठीक बाद जब विनिर्माण क्षेत्र ने ७.१ प्रतिशत के लक्ष्य प्राप्ति के मुकाबले केवल ५.५ प्रतिशत की वृद्धि दिखायी तो वित्त मंत्री ने वृद्धि दर को गति देने हेतु सभी मंत्रालयों को योजनागत मदों में खर्चा बढ़ाने की मंजूरी दे दी।

राज्यों द्वारा असहयोग

लक्ष्य प्राप्ति में जो अन्य सबसे बड़ी बाधा है, वह है – राज्यों द्वारा मिलने वाला असहयोग। १९८० एवं १९९० के पूरे दशक में राज्यों द्वारा जी०डी०पी० में कर का हिस्सा ५.४ प्रतिशत पर स्थिर रहा। जबकि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त उधार बढ़ता गया क्योंकि प्राप्त उधार में से अधिकांश राजस्व का उपयोग राज्य सरकारों ने अपने यहाँ राजस्व घाटा कम करने में खर्च किया अन्यथा तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, भुगतान में।

शुरू में योजना आयोग ने इस लक्ष्य को प्राप्त पूर्णत: तर्क दिया। लेकिन जब दृष्टिकोण पत्र पर सभी क्षेत्रों से इस लक्ष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाने लगा तब योजना आयोग ने स्पष्ट किया कि ९ प्रतिशत विकास दर प्राप्त करना संभव नहीं (स्रोत 'द हिंदू २८ जून, २००१)।

इतना ही नहीं ८ प्रतिशत का [illegible] प्राप्त करना भी इतना आसान [illegible]

दृष्टिकोण पत्रक में स्पष्ट [illegible] है कि दस वर्ष के भीतर प्रति व[illegible] को दुगुना करने हेतु आवश्यक [illegible] ८.७ प्रतिशत अपेक्षित है, लेकि[illegible] ८ प्रतिशत विकास दर को संकी[illegible] मान लिया गया है। यह एक दु[illegible] है। क्योंकि वर्तमान में सकल घ[illegible] कम होकर ६ प्रतिशत पर आ[illegible] विश्व बाजार में मंदी का दौर च[illegible] भारतीय अर्थव्यवस्था में भी [illegible] झलक रही है। राजनीतिक अ[illegible] की तलवार हमेशा लटकती रहती [illegible] परिस्थितियों में एक दुर्लभ ल[illegible] करना एवं उस लक्ष्य की प्रा[illegible] मरीचिका ही है।

अगर हम नवीं पंचवर्षीय य[illegible] लक्ष्य एवं प्राप्तियों पर गौर करें [illegible] शंका को और बल मिलता है।

मद	१९९६-९७	२००१-[illegible]
सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि (% प्रतिवर्ष)	६.८	[illegible]
बचत दर	२३.८	[illegible]
निवेश दर	२४.९	[illegible]
बेरोजगारी दर	६.०३	[illegible]
कृषि	४.०	[illegible]
उद्योग	७.१	[illegible]
सेवा	७.२	[illegible]

...देशी अपनाए बिना इसे फेल
...ना ऐतिहासिक अपराध

■ जय दुबाशी

...पेयी सरकार ने जिस ...रीकरण को अपनाया है ...उदारीकरण हमारी सोच ...उदारीकरण से कहीं मेल ...खाता। कुछ उद्योगों को ...दें तो हमारी अर्थव्यवस्था ...ग विदेशियों की भेंट चढ़ ...की है। दस साल में दस ...ख रोजगार के अवसर ...हो गए या यूँ कहिए कि ...लाख लोग बेरोजगारी की ...गार पर पहुँच गए। यदि ...रीकरण का यह परिणाम ...है तो देश को ऐसा ...दारीकरण क्यों चाहिए।

...र्थव्यवस्था की हालत देख बहुत ही कोफत होती है। जब हम विपक्ष में थे तब हमारी यह ...थी कि जब भी सत्ता में आएंगे, ...को स्वावलंबी, आत्मनिर्भर और ...वाभिमानी बनाएंगे। इस कल्पना को ...करने के उपायों पर भारतीय जनता ...के लोग बडी गंभीर चिंतन मनन ...करते थे। भारतीय जनता पार्टी के ...के अध्यक्ष और अब के गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी इस अभिकल्पना के प्रेणता थे। उनको स्वदेशी पर पूरा भरोसा था, पर आज यह सुनकर घोर आश्चर्य होता है कि वही लालकृष्ण आडवाणी गृहमंत्री बनने के बाद स्वदेशी की भूमिका पर सवाल खड़ा करते है। वही लालकृष्ण आडवाणी स्वदेशी को समीचीन मानने से इनकार कर रहे हैं। "बाबू" से वित्त मंत्री बनें यशवंत सिन्हा दलील देते है कि उदारीकरण के बिना देश खड़ा नहीं रह सकता। खैर यशवंत सिन्हा जैसे "बाबू"से हम जैसे लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की । उम्मीद वाजपेयी से भी नहीं थी, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी से जरूर थी । पर उन्होंने भी स्वदेशी को विकास यात्रा के लिए असफल यंत्र मान लिया है। स्वदेशी अपनाए बिना इसे फेल मान लेना मेरी नजर मे ऐतिहासिक अपराध है।

दस साल के उदारीकरण से हमें क्या मिला? अब सबके सामने आ रहा है। मैं यह नहीं कहता कि हमें कुछ भी नहीं मिला। यह भी नहीं कहता कि उदारीकरण का आंख मूंद कर विरोध किया जाए। जब भारतीय जनता पार्टी को एक पहचान देने मे हमलोग लगे थे तभी से हम उदारीकरण का सर्मथन करते आ रहे है। लेकिन हमारे उदारीकरण का मतलब भारतीय कम्पनियो को बेचना, विदेशी कम्पनियो कों उनकी शर्त पर भारत मे पूँजी लगाने की अनुमती देना या सत्ता को नचाने का अधिकार देना कतई नही था। हम आंतरिक उदारीकरण के पक्षधर थे और आज भी है। प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा से मुँह चुराने की कभी कल्पना ही नही की । लेकिन स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हो ऐसा विचार हमेशा रहा । लेकिन वाजपेयी सरकार ने जिस उदारीकरण को अपनाया है वह उदारीकरण हमारी सोच के उदारीकरण से कहीं मेल नहीं खाता। कुछ उद्योगों को छोड दें तो हमारी अर्थव्यवस्था लगभग विदेशियों की भेंट चढ़ चुकी है। दस साल में दस लाख रोजगार के अवसर खत्म हो गए या यूँ कहिए कि दस लाख लोग बेरोजगारी की कगार पर पहुँच गए। यदि उदारीकरण का यह परिणाम है तो देश को ऐसा उदारीकरण क्यों चाहिए।

उदारीकरण हमारी नीतियों, हमारे कार्यक्रमों और हमारे उद्देश्यो के अनुरूप होने चाहिए न कि विदेशियो की जरूरत और उद्देश्यों के अनुरूप। हम अपने कार्यक्रम रोज नही बदल सकते। हम यह नही कह सकते आज उदारीकरण, कल बंद अर्थव्यवस्था, परसों स्वदेशी और अगले दिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपना लें। कोई गंभीर राष्ट्र ऐसा कर भी नहीं सकता। लेकिन मौजूदा समय में यही तो हो रहा है। उदारीकरण की कोई दिशा नहीं है। किसी को मालूम नहीं कि क्या हो रहा है? पता नहीं क्यों यह सरकार भारतीय कंपनीयों को दनादन बेचने मे लगी है। किस बात की जल्दीबाजी है। जब औने–पौने दामों में सार्वजनिक कंपनियों के शेयर बेचे जाने लगे तो किसी को भी विनिवेश कार्यक्रम पर आशंका करने से कैसे रोका जा सकता है। एक बात और

Scanned with OKEN Scanner

मैं चिंदबरम के मुख से यह सुनकर हैरान रह गया कि विदेशी पूँजी के बिना भारत मे स्थाई राजनीतिक स्थिरता नहीं आ सकती । मैंने भरी सभा मे चिंदबरम का विरोध किया। हमने कहा कि क्या इस दिन के लिए हमारे राष्ट्र पुरूषों ने बलिदान दिया, क्या भारत का आत्मविश्वास मर गया है। मेरे इस सशक्त विरोध का परिणाम यह हुआ कि चिंदबरम तीन दिन तक मुझसे मिलने नहीं आए।

समझ मे नहीं आ रही कि प्रमुख भारतीय कंपनियों को विदेशी कंपनियों के हाथों ही क्यों बेचा जा रहा है। क्या सिर्फ इसलिए कि विदेशी कंपनियो के साथ अनैतिक लेन देन आसान है या इसलिए कि केवल विदेशी कंपनियां ही भारतीय कंपनियों को चलाने का माद्दा रखती है। मार्डन फूड को हिंदुस्तान लीवर के हाथों बेंच दिया गया। बाल्को को एस्टरलाइट के हाथ। हिंदुस्तान बहुराष्ट्रीय कंपनी है सबको पता है। लेकिन शायद कम लोगों को पता है कि एस्टरलाइट कि प्रमुख अनिल अग्रवाल भारतीय नहीं ब्रिटेन के नागरिक है। मुझे तो यह भी लगता है कि विदेशी कंपनियों ने कुछ भारतीय कंपनियों के साथ एक ऐसा गिरोह बना लिया है जो रणनीति के तहत भारतीय कंपनियों को औने–पौने दामों खरीदने में लगा है। यह गिरोह पहले ही तय कर लेता है कि किस कंपनी को किस सार्वजनिक कंपनी की खरीददारी के लिए निविदा लेना है और किसे नहीं। ताकि प्रतिस्पर्धा की स्थिति ही नहीं बनें। यदि इसमें जरा भी सच्चाई है तो यह बडी भयंकर स्थिति है।

हमारे उदारीकरण की दिशा विदेशी क्यों तय करे। शायद यह ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि अभी तक भारत की पहचान एक कमजोर देश की रही है। हमें न तो आर्थिक दृष्टि से और न ही सामरिक दृष्टि से मजबूत राष्ट्र के रूप मे मान्यता मिली है। हमारे नीति–निर्धारक भी कभी भारत को इस रूप मे पेश नहीं कर पाये है। भारतीय जनता पार्टी से ऐसी उम्मीद थी लेकिन आडवाणी, वाजपेयी और सिन्हा में से किसी ने भी भारत को मजबूत राष्ट्र के रूप में पेश करने की कोशिश नहीं की। उदारीकरण के बाद से अब तक लगातार विकसित राष्ट्रों को यही अहसास दिलाया जाता रहा है कि

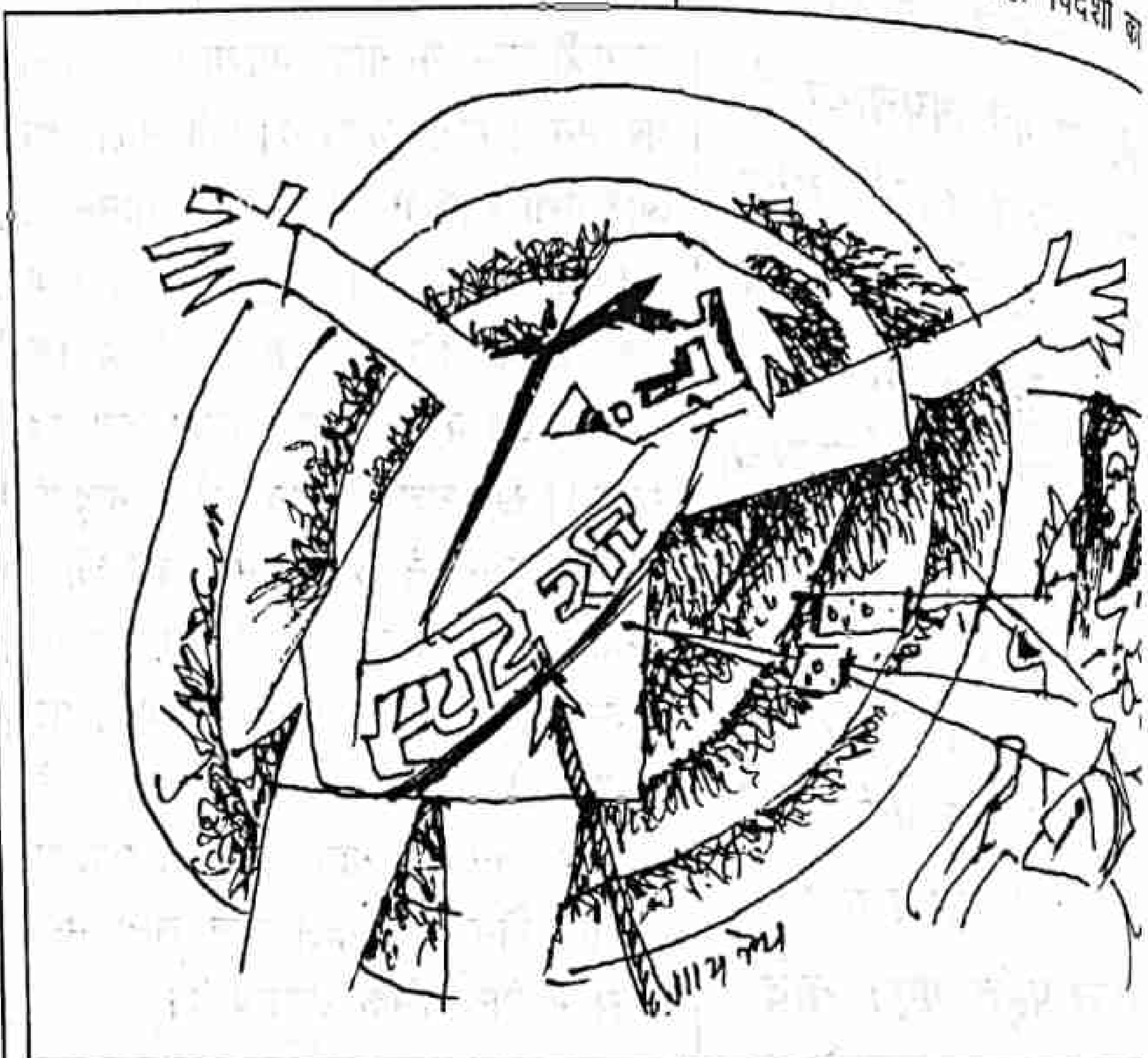

विदेशी पूँजी के बिना भारत कुछ भी नहीं कर सकता । मुझे याद है कि १९९३ मे ब्रिटेन के विदेश विभाग ने एक सम्मेलन करवाया था जिसका विषय था उदारीकरण और दक्षिण ऐशियाई देशो मे स्थायीत्व । इस सम्मेलन मे चिंदबरम भारत सरकार के प्रतिनिधि थे। सम्मेलन मे मुझे भी जाने का मौका मिला था। मैं चिंदबरम के मुख से यह सुनकर हैरान रह गया कि विदेशी पूँजी के बिना भारत मे स्थाई राजनीतिक स्थिरता नहीं आ सकती । मैंने भरी सभा मे चिंदबरम का विरोध किया। हमने कहा कि क्या इस दिन के लिए हमारे राष्ट्र पुरूषों ने बलिदान दिया, क्या भारत का आत्मविश्वास मर गया है। मेरे इस सशक्त विरोध का परिणाम यह हुआ कि ... तीन दिन तक मुझसे मिलने नहीं ...

सचमुच भारत के राजनीति... आत्मविश्वास का भाव मर गया है ... के प्रति जो गर्व की भावना होनी ... वह नहीं दिख रही है। मैं कोरि... लोगो को प्रणाम करता हूँ कि ... अन्दर राष्ट्रीयता कूट–कूट कर ... यह जानकर आश्चर्य होगा कि ... कोरिया मे बमुश्किल पाँच सौ विदेशी ... होगी। कोई भी कोरियाई नागरिक ... वाहनों को बर्दास्त नही करता। ... कि विदेशी गाड़ियाँ सड़कों पर ... जाती है। हमारे यहाँ विदेशी का... चलना शान माना जाता है। केवल ... या बिगड़े हुए लोग ही नहीं, ... सेवा का दम्भ भरने वाले राजनी... विदेशी गाडियों पर शान से चल... दुनियाभर में अपने उत्पादों को ज... पहुँचाने वाले अमेरिकी खुद कम ... विदेशी उत्पादों का इस्तेमाल क... शायद सबको मालूम न हो लेकि... तथ्य है कि अमेरिकी सरकार विदे... या पेंसिल तक इस्तेमाल नही कर... लेकिन भारत सरकार धड़ल्ले से ... वस्तुओं का इस्तेमाल करती है। ... ही जब यह इच्छाशक्ति नहीं रख... विदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहित नहीं ...

(शेष पृ...

एस-६४ का ओर-छोर

द कुमार

यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (यू.टी.आई.) कोई सामान्य म्युअल फण्ड नहीं है। इसकी स्थापना सरकार ने छोटे निवेशकों को निवेश का एक साधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की थी।

इसमें निवेशित रकम को सरकारी प्रतिभूतियों, शेयरों आदि में निवेश किया जाता था। आकर्षक डिविडेंड देने और सुरक्षित निवेश उपलब्ध कराने के कारण यू.टी.आई. को निवेशकों का विश्वास प्राप्त हुआ। यू.टी.आई. हमेशा अपने सूत्र वाक्य 'सुविनियोगात् समृद्धिः' पर अमल करती थी। आज यू.टी.आई. के ६० हजार करोड़ विशाल निवेश भंडार को देखकर आसानी से अनुमान लगाया जा सकता है कि यह देश का सबसे बड़ा म्युचुअल फण्ड है।

कहा गया है कि जो इतिहास से सबक नहीं सीखते वे उसे दोहराने को अभिशप्त होते है। यू.टी.आई. में इतिहास अपने को दोहरा रहा है। इसकी सबसे लोकप्रिय योजना यू.एस.६४ रही है, जिसके २ करोड़ से ज्यादा निवेशक है और २० हजार करोड़ रुप्ये उसके निवेश फण्ड में था। लेकिन यू.टी.आई. की यू.एस. ६४ योजना ध्वस्त हो गई है। इस योजना में भ्रष्टाचार का प्रवेश तीन वर्ष पहले १९९८ में ही हो गया था और यह विडम्बना ही कही जाएगी कि दोनों बार वाजपेयी सरकार ही सत्ता में थी और वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ही थे। उस समय भी यू.टी.आई. के पुनर्गठन और उसके प्रबंध को ठीक करने की उतनी ही बातें हुई थी जितनी इन दिनों हो रही है। यू.टी.आई. के इस नए संकट को एक प्रहसन की संज्ञा दी जा सकती है, जिसे वित्त मंत्रालय और यू.टी.आई. के प्रबंधन ने छोटे और सामान्य निवेशकों के साथ खेला है। इस खेल में सभी एक-दूसरे को दोषी ठहरा रहे है, लेकिन मुख्य रूप से कौन दोषी है, यह जाँच का विषय है।

वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा और उनके मंत्रालय के कहने पर यकीन करे तो मानना होगा कि यू.टी.आई. की दुर्दशा के लिए केवल इसके तत्कालीन अध्यक्ष पी.एस. सुब्रह्मण्यम जिम्मेदार है। वित्त मंत्री के अनुसार यू.टी.आई. में क्या हो रहा है इसकी जानकारी न तो उन्हें थी औ न ही उनके मंत्रालय को। लेकिन वित्त मंत्री की कथनी करनी और दावों में इतना अंतर है कि सच्चाई पर पर्दा डाल पड़ना मुश्किल हो रहा है। वित्त मंत्री और उनके मंत्रालय के अफसर अपने को यू.टी.आई. की मौजूदा दुर्दशा और संकट की सीधी जिम्मेदारी लेने से नहीं बचा सकते है। यह कोई नैतिक जिम्मेदारी लेने भर का मामला नहीं है, बल्कि इससे कहीं आगे यह सीधी जवाब देही का प्रश्न है, जिससे वित्त मंत्री कतरा कर निकलने की कोशिश कर रहे है। लगभग चार महीने पहले शेयर बाजार में जबरदस्त घोटाला हुआ था, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इसका सारा दोष सेबी और रिजर्व बैंक पर मढ़ दिया, अब यू.टी.टी. के मामले में सुब्रह्मण्यम पर सारा दोष लगाकर अपने को बचा रहा है।

यू.टी.आई. और यू.एस.६४ संकट के लिए प्राथमिक तौर पर इसके तत्कालीन अध्यक्ष जिम्मेदार कहे जा सकते है, इनके द्वारा पूर्व में लिये गये कई विवादास्पद फैसले यू.टी.आई. की दुर्दशा का मुख्य कारण है। लेकिन इसकी जिम्मेवारी और जवाब देही सिर्फ सुब्रह्मण्यम की

ही नहीं है, वित्त मंत्रालय का भी उसमें उतना ही हाथ है। वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का कार्यकाल शुरू से ही विवादास्पद रहा है तभी तो उन्हें यू.टी. आई. में २ जुलाई के पहले कुछ गड़बड़ नहीं दिखा और न ही महीनों से अखबारों-पत्रिकाओं में यू.टी.आई. के अंदरूनी हालात और अनियमितताओं के बारे में छप रही रिपोर्टों की ओर ध्यान गया।

यू.एस.६४ प्रकरण में वित्त मंत्रालय ने सफाई दिया कि यू.टी.आई. ने २ जुलाई को यू.एस.६४ की खरीद-बिक्री को ६ महीने के पहले स्थगित करने की घोषणा से पहले उसे अंधेरे में रखा स्वयं वित्त मंत्री के अनुसार उन्हें इस बारे में कुछ जानकारी नहीं थी।

वित्त मंत्री के इस बयान पर कौन विश्वास कर सकता है। यू.टी.आई. इतना बड़ा फैसला लेने जा रही हो और वित्त मंत्रालय को इसकी जानकारी तक नहीं हो यह कैसे संभव है? थोड़ी देर के लिए अगर यह मान भी लिया जाए तो यह अपने आप में वित्त मंत्रालय के कामकाज का पोल खोलता है। सच यह है कि यू.एस.६४ बंद करने का फैसला सिर्फ यू.टी.आई. के अध्यक्ष का नहीं था बल्कि इसके लिए यू.टी.आई. की ट्रस्टी बोर्ड में फैसला लिया गया था जिसमें सरकार नियंत्रित अन्य कई वित्तीय संस्थाओं के प्रमुख के अलावा रिजर्व बैंक के एक कार्यकारी निदेशक सदस्य के रूप में उपस्थित थे। जिस सुब्रह्मण्यम पर वित्त मंत्री आरोप लगा रहे है, उनको स्वयं ही यशवंत सिन्हा १९९८ में लाए थे। यू.टी.आई. के कार्यकारी निदेशक बी.जी. डागा के अनुसार यू.टी.आई. की अंदरूनी स्थिति और मौजूदा संकट के बारे में वित्त मंत्रालय को लगातार सूचना दी गई थी, फिर भी वित्त मंत्रालय ने इसकी अनदेखी की। यू.टी.आई. ने जून के पहले पखवाड़े में ही वित्त मंत्रालय से लगभग ६००० करोड़ रुपए के बचाव पैकेज की माँग करते हुए एक आवेदन दे रखा था, लेकिन वित्त मंत्रालय ने उस माँग को ठुकराते हुए यू.टी.आई. से कहा कि वह स्वयं अपने किए को भुगते। वित्त मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पूँजी बाजार) जैमिनी भगवती के एक बयान से मंत्रालय के नजरिये का अनुमान लगाया जा सकता है। भगवती के अनुसार यू.एस.६४ कोई लाभ योजना नहीं है। एक दिलचस्प तथ्य यह है कि यू.टी. आई. के ट्रस्टी बोर्ड ने यू.एस.६४ की खरीद बिक्री पर रोक लगाने से एक सप्ताह पहले एक बैठक कर नियमावली में संशोधन करते हुए यू.एस. ६४ की खरीद-बिक्री पर रोक लगाने का अधिकार शामिल किया था। इससे साफ... उच्च स्तर पर तैयारी काफी... चल रही थी।

इसके बावजूद अगर वि... यह कह रहे है कि उन्हें कुछ... नहीं था तो इससे यही जाहिर... कि वह या तो स्वयं दोषी है और... तो दोषियों को बचाना चाहते है... तरह से वह और उनका मंत्रालय... अपराध को बढ़ावा दे रहा है... जबकि चारों तरफ यू.टी.आई. और... मंत्रालय के खिलाफ आवाज उठ... है तब जैसा कि सभी सरकारें क... इस सरकार ने भी एक जाँच समिति... गठन कर दिया और यू.टी.आई. के... अफसरों के घरों पर सी.बी.आई... छापे पड़ रहे हैं। लेकिन इसमें... अहम जाँच वित्त मंत्री की भूमिका... होनी चाहिए और यू.टी.आई. के त... अध्यक्ष जो कि अब हिरासत... उनको आगे बढ़कर सच्चाई जाँच... के सामने लाना चाहिए जिससे फि... जनता का विश्वास हासिल हो... और स्वयं वे अपने ऊपर लगे आ... बच सकें।

पिछले कुछ महीनों में जिस... से आर्थिक घोटाले हुए है उससे... उदारीकरण और सुधारों की अस... खुलकर सामने आ गई है। अब... आदमी के समझ में नहीं आ रहा... वह अपनी जमा पूँजी कहाँ निवेश... जिससे उसकी सुरक्षा भी काय... और एक निश्चित आय भी हो। ... जब वित्त मंत्रालय अपने आँख, ... और मुँह बंद किए बैठा हो तो ... क्या उम्मीद की जा सकती है... जितनी चिंता कारपोरेट समूहों के... की है, उसकी एक रती भी चिंता... निवेशकों की नहीं है। अब जबकि... दृश्य सामने है तो इसमें यही तय... है कि मुख्य अपराधी कौन है?... मंत्री या उनका मंत्रालय या यू.टी.आई... के तत्कालीन अध्यक्ष।

केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के अनुसार इस घोटाले में गिरफ्तार अधिकारियों ने कहा कि शेयर खरीदने का फैसला बाहरी कारणों की वजह से किया गया। इस पूछताछ से इस घोटाले में एक बार फिर राजनेता और अपराधियों का गठजोड़ सामने आया है। यू.टी.आई. के अधिकारियों ने यह स्वीकार किया है कि अपने विभाग के इक्विटी रिसर्च सेल तथा फण्ड शाखा के मना करने के बाद भी उन्होंने चार दिन बाद शेयर लेने का फैसला किया था। सी.बी.आई के अनुसार इस बाहरी कारण में राजनीतिक दबाव और कितना पैसा शामिल है इसकी जाँच की जा रही है। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो इस घोटाले में विभिन्न बैंको और मुंबई शेयर बाजार से भी जानकारी प्राप्त करेगा। जाँच अधिकारी इस बात का पता लगा रहे हैं कि लाखों निवेशकों को प्रभावित करने वाले इस निर्णय में किसने सक्रिय भूमिका निभाई।

Scanned with OKEN Scanner

करण के नारों के पूरे विश्व के ा मानव विकास यों को लेकर एक का विश्व स्तरीय निर्धारित करना नही तु भयंकर नताओं के माध्यम ब देशों का अमीर द्वारा दोहन व एक मुख्य उद्देश्य हुआ है...

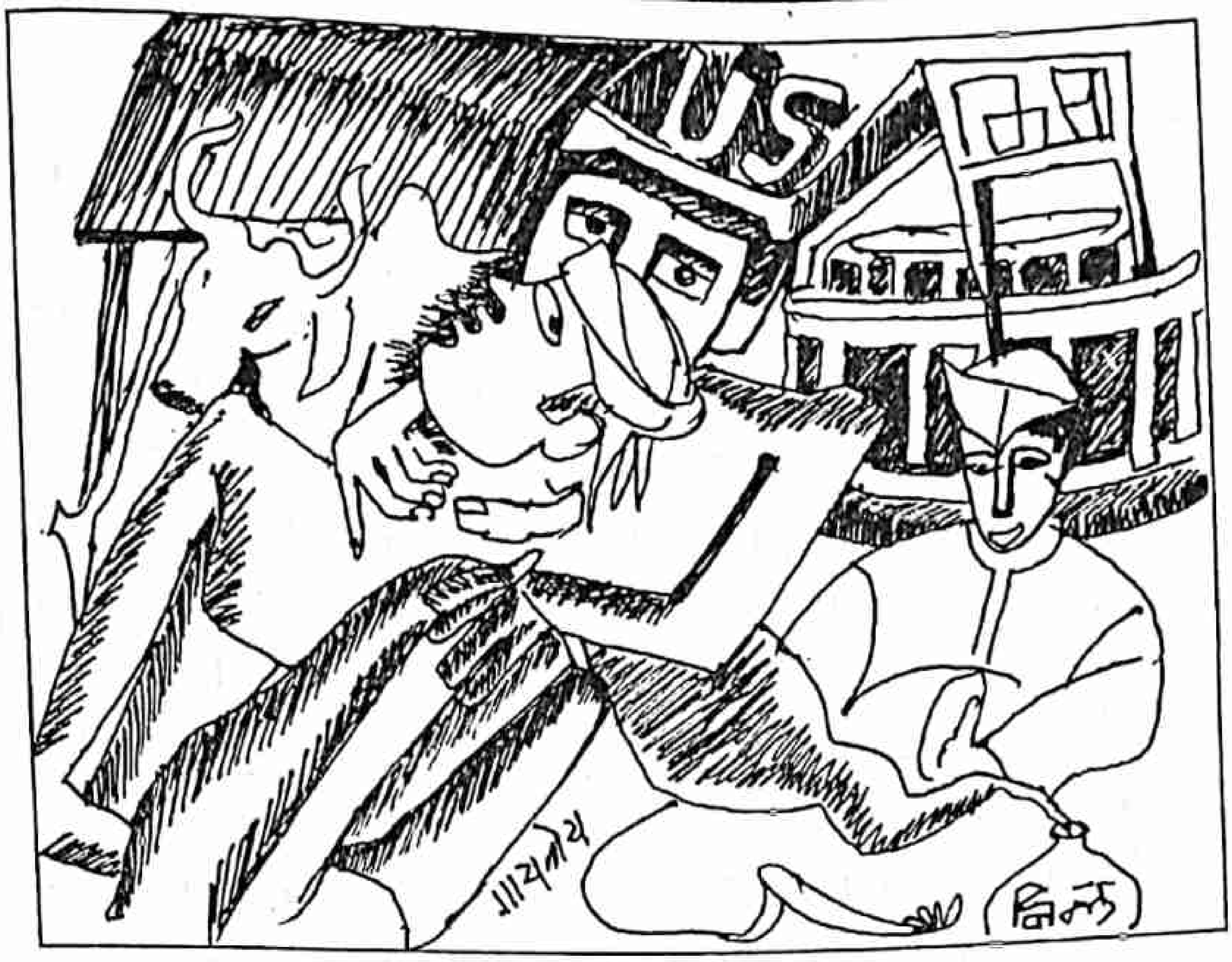

भारतीय कृषि के साथ ऐसा अन्याय क्यों?

■ मूँगालाल सुरेका

श में जनगणना का जो कार्य अभी संपन्न हुआ है उसके घोषित परिणामों के अनुसार की जनसंख्या १,०२,७०,१५,२४७ थी है जिसके अनुसार १९८१-९१ जनगणना के बाद २१.३४ प्रतिशत वृद्धि हुई है। तदनुसार राजस्थान की संख्या ५,६४,७३,१२२ हो गयी है, पर इन १० वर्षों में २८.४४ प्रतिशत हुई है। कृषि देश की आर्थिक आधारशिला है और भारत की जनसंख्या बहुमत का यही मुख्य रोजगार है। : कृषि की उपेक्षा इस देश में किया ा तभी संभव है जबकि देश का मत जाग्रत न रहे। ऐसा निरंतर होता रहेगा तो लोकतंत्र के लिए भी देश में कोई स्थान नहीं रहेगा। अतः देश की कृषि संबंधी नीतियों की समीक्षा व्यापक स्तर पर गाँव-गाँव ढाणी-ढाणी, खलियान से खलियान तक होती रहनी चाहिए। भूमंडलीकरण के नारों के अंतर्गत पूरे विश्व के देशों का मानव विकास के लक्ष्यों को लेकर एक सहयोग का विश्व स्तरीय लक्ष्य निर्धारित करना नहीं है अपितु भयंकर असमानताओं के माध्यम से गरीब देशों का अमीर देशों द्वारा दोहन व शोषण एक मुख्य उद्देश्य बना हुआ है जो भाषा के अनुसार भी भूमंडलीकरण शब्द के साथ एक अन्याय है। जब कभी प्रतियोगिताएँ आयोजित होती हैं तो उनमें कुछ प्रतियोगियों की समानता का ध्यान रखकर खेलों में उम्र के अनुसार व वजन के अनुसार विभिन्न समूहों में प्रतियोगिताएँ आयोजित होती हैं। विश्व में भी विभिन्न देशों को आय की दृष्टि से निम्न आय, मध्यम आय व उच्च आय के समूहों में संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर देशों को विभक्त किया गया है। विश्व व्यापार संगठन में बहुत कम आय वाले कुछ अफ्रीकन देशों की एक अलग श्रेणी बनाई है जो बहुत छोटी है, बाकी एशिया, लेटिन अमरीका व अफ्रीका के विकासशील देशों को अमरीका, यूरोप, जापान आदि उच्च आय के देशों के साथ खुली प्रतियोगिता में खड़ा कर दिया है।

Scanned with OKEN Scanner

असमानताओं का एक डरावना चित्र विश्व व्यापार संगठन के स्वयं की विधाओं में है।

भारतीय किसानों के साथ जैसा अन्याय हुआ है वैसा संभव है पूरे विश्व में किसी वर्ग के साथ नहीं हुआ होगा। भारत पर पाबंदी है कि हम अपनी कृषि को १० प्रतिशत से अधिक सहायता नहीं दे सकते हैं जबकि अमरीका, यूरोपियन संघ व जापान आदि उन्नत देशों के किसानों की सहायता को २४ प्रतिशत कम करके भी २०० से ३०० प्रतिशत छोड़ दिया गया है। देश का ७० प्रतिशत क्षेत्र असिंचित है। मोटा अनाज बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंग, मोंठ की दालों की असिंचित खेती छोटे-छोटे टुकड़ों में भारतीय किसान करते हैं जिन फसलों के उत्पादन में ९०-९१ के बाद नकारात्मक विकास दर रही है।

फिर भी अप्रैल २००१ से बाजरा, ज्वार, चावल, डेयरी उत्पादन, मछली उत्पादन आदि के आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध इन सुधारों के नाम पर इसलिए उठा लिए गए हैं कि भारत के साथ ऐसा अनुबंध १९९४ में विश्व व्यापार संगठन के साथ हो गया था। माना यह जा रहा है कि भारत में विदेशी मुद्रा की स्थिति अब सुविधाजनक हो गई है। इसलिए खुला आयात अप्रैल २००३ से होना चाहिए था उसे अप्रैल २००० से ही प्रारंभ कर दिया गया है। क्या किसी ने सोचा है कि विदेशी मुद्रा जिन लोगों के पास है क्या उन्होंने कभी खेती का कार्य किया है या करने वाले हैं। जिनके पेट भरने के लाले पड़े हुए हैं उनके पेटो पर विश्व व्यापार समझौते के नाम पर अमीर देश और लात मार रहे हैं। क्या कभी किसी ने अमरीका, यूरोप, जापान या आस्ट्रेलिया में भारत में जैसे दरिद्र किसान जैसी परिस्थितियाँ देखी हैं।

भारत में ६४ प्रतिशत श्रम जनसंख्या कृषि के व्यवसाय पर आधारित है जबकि यह श्रम जनसंख्या का प्रतिशत कनाडा में ३, फ्रांस में ५, जापान में ७, ब्रिटेन में २ व अमरीका में केवल ३ प्रतिशत है। कृषि जिन्सों पर विदेशी आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध १/४/२००१ से पूरे रूप से समाप्त कर दिए गए हैं, जबकि कृषि जिन्सों के औसत का प्रति हैक्टेयर उत्पादन की विकसित देशों के साथ तुलनात्मक स्थिति निम्न प्रकार है – (देखें तालिका में)।

इस प्रकार भारत में १० करोड़ से अधिक छोटे-छोटे खेत हैं जिनमें औसत भूमि एक हैक्टेयर से कम का है लेकिन अमरीका का औसत खेत ८०० हैक्टेयर

तालिका : उत्पादन क्विंटल प्रति हैक्टेयर

	भारत	अमरीका	जापान	मिश्र
चावल	२९	६६	६८	८२
गेहूँ	२५	३०	३६	५४
मोटा अनाज	९.७७	७०.४९	–	–
रूई	९	१६	–	२८
गन्ना	६९२	७५०	–	११०२
दालें	५.८७	२९.६३	–	–

> **ऊर्जा के उपयोग मे... विकास व रोजगार का ... साधन है भारत का ... उपयोग प्रति व्यक्ति तेल ... मात्रा के आधार पर केवल ... २४८ किलोग्राम तेल है जबकि यूनाइटेट किंग्डम ... यह उपयोग ३७७२ किलो... प्रति व्यक्ति व अमरीका ... इससे दोगुना से अधिक ७८९१ किलोग्राम प्रति व्यक्ति है।**

का है। अतः उपयुक्त भारतीय ... उत्पादन भारत में भी ९० प्रतिशत ... किसानों को उपलब्ध नहीं है। यह ... भी १० प्रतिशत बड़े व संगठित कि... के आधार पर आती है।

ऊर्जा के उपयोग में जो विकास ... रोजगार का मुख्य साधन है भारत ... ऊर्जा उपयोग प्रति व्यक्ति तेल की म... के आधार पर केवल २४८ किलो... तेल है जबकि यूनाइटेट किंग्डम में ... उपयोग ३७७२ किलोग्राम प्रति व्य... व अमरीका में इससे दोगुना से अधि... ७८९१ किलोग्राम प्रति व्यक्ति है। इ... स्पष्ट है कि भारत की विकास योज... ऊर्जा के उपयोग पर आधारित कि... जाने से अमरीका जैसे विकसित देशों ... साथ प्रतियोगिता करने में हम ... अक्षम रहेंगे और हमारी योजनाएँ जनशक्ति ... प्रधान पर हो सकती है। जनशक्ति ... अधिक से अधिक उपयोग खेती में हो ... है। अतः हमारे लिए कृषि की सर्वो... प्राथमिकता है।

खेद है कि कृषि की पूँजी ... निर्माण सबसे कम भारत में किए ... से यह सर्वसिद्ध है कि हमारी योजनाओं ...

Scanned with OKEN Scanner

...को सबसे कम महत्त्व दिया गया ... देश की अधिकांश जनता के ... इस तरह की विकास नीति को ...करने व क्रियान्वित करने में ...ों द्वारा घोर लापरवाही बरती गयी ...सामाजिक न्याय से उन्हें वंचित ...गया है (१९९३-९४ की कीमतों ...आधार पर) १९६०-६१ में कृषि में ... करोड़ की पूँजी का पूरे देश में ...हुआ था जो सबसे कम था और ...-७९ तक १८२०० करोड़ रुपए ...के निवेश में इसमें वृद्धि हुई, उसके ...१९८६-८७ से यह फिर कम होने ... फिर भी अपने पुराने स्तर १९००० ...पर २० वर्ष बाद १९९८-९९ में ... जिससे स्पष्ट है कि १९७८-७९ से ...९९ तक के २० वर्षों में कृषि में ...निवेश में वृद्धि शून्य रही। इन तथ्यों ...नीतियों का विश्लेषण करके यह ...त किया जा सकता है कि किसानों ...घोषित हितों से चुने जाने वाली ...ों ने उनके कल्याण के लिए ...रूप से अपने वायदों की अवहेलना ...व लक्ष्यों के प्रति लापरवाही बरती। ...देश के घरेलू उत्पादन में कृषि ...दन में कुल घरेलू पूँजी निवेश ...-६१ में कुल पूँजी का १४.५ प्रतिशत ...हिस्सा था जो ७९-८० में १८ ...शत हो गया था। वह हिस्सा, अत्यंत ...का विषय है, कि ९८-९९ में अब ...केवल ६.५ प्रतिशत रह गया है। क्या ...ी संसद में इस गंभीर विषय पर भारत ...कृषि मंत्री या वित्त मंत्री ने कभी कोई ...श डाला कि कृषि में पूँजी निवेश ...में कुल पूँजी निवेश पर इस तरह का ...शत धड़ाम से क्यों गिरा?

...नारों के रूप में देश में सत्तासीन ...नीतिक दल ने ही विरोध में बैठकर ...के सैद्धांतिक नारा दिया था कि देश में हर खेत को पानी व हर हाथ को काम किया जाना हमारा लक्ष्य होगा।

पूँजी निवेश की सबसे अधिक कमी सार्वजनिक पूँजी निवेश में हुई है और इस मद में पूँजी निवेश का मुख्य विषय सिंचाई योजनाएँ जिनमें मझौली और बड़ी सिंचाई की योजनाएँ होती है। सूखे क्षेत्रों में राजस्थान मुख्य रूप से माना जा सकता है जहाँ की सबसे बड़ी सिंचाई योजना इंदिरा नहर ४२ वर्ष से न केवल अपूर्ण है अपितु ज्यों-ज्यों समय गुजर रहा है यह कहा जा रहा है कि इस योजना को पूर्ण करने के लिए कभी जल उपलब्ध नहीं होगा और अभी भी हर वर्ष जल की सप्लाई इस परियोजना में कम होती जा रही है। यह वर्ष गंभीर अकाल का वर्ष है लेकिन सबसे अधिक वित्तीय कटौती इंदिरा नहर के प्रावधानों में करके २५० करोड़ के प्रावधानों को १०० करोड़ से नीचे ला दिया गया है।

देश में ३२८० लाख हैक्टेयर कुल भौगोलिक देश में से ४०० लाख हैक्टेयर क्षेत्र बाढ़ों से प्रभावित है और सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र ब्रह्मपुत्र, गंगा नदियों के अंतर्गत है जिनके जल को सूखे क्षेत्रों में स्थानांतरित किए जाने की कोई ठोस योजनाएँ नहीं है, न कोई राष्ट्रीय संकल्प की घोषणा हुई है। कृषि के क्षेत्र में जो निजी पूँजी निवेश होता है वह या तो बड़ी कंपनियों द्वारा चाय के बागान चलाते हैं या दूसरे बड़े उद्यान चलाते हैं, द्वारा होता है, जिसका कोई लाभ भारत के औसत किसान को नहीं मिलता। निजी पूँजी निवेश का बड़ा मद बड़े कृषि उपकरण की खरीद होती है जैसे हारवेस्टर कम्बाईन, पावर पिलर्स या ट्रेक्टर्स आदि। छोटे व सीमांत किसान इस श्रेणी की पूंजी से भी लाभान्वित नहीं हो सकते। सार्वजनिक पूँजी निवेश का मुख्य मद बाँधों व नहरों का निर्माण होता है जिसको पूर्ण करने में ५-६ साल से लेकर १०-१२ साल तक का समय लग जाता है। कोई राजनीतिक दल दीर्घकालीन योजनाओं में रूचि नहीं लेता और नदियों का जल उनकी घाटियों से बाहर सूखे क्षेत्रों तक लाने के लिए इस तरह की बड़ी परियोजनाएँ प्राथमिकता से लेना अत्यंत आवश्यक होता है। दुःख का विषय है कि पहली पंचवर्षीय योजना १९५१-५६ में जितनी योजनाएँ ली गयी थी कि उनमें से भी कुछ अभी तक अपूर्ण हैं।

भारत की अधिकांश नदियाँ अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ हैं और नदियों को राज्यों का विषय बनाए जाने से अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद खड़े ही रहते हैं। नेताओं को इन विवादों के आधार पर जनता की भावनाओं को भड़काने का सबसे अच्छा अवसर मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम के अंतर्गत अभी तक पाँच आयोगों का गठन किया गया था –

१. गोदावरी जल विवाद आयोग,
२. कृष्णा जल विवाद आयोग,
३. नर्मदा जल विवाद आयोग,
४. कावेरी जल विवाद आयोग,
५. रावी व्यास जल विवाद आयोग।

इन आयोगों में से पहले तीन ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और अंतिम दो आयोगों की रिपोर्ट अभी तक आयोग के समक्ष विचारणीय पड़ी है। देश की नदियों द्वारा विशेष रूप से गंगा यमुना आदि के जल को सूखे क्षेत्रों में लाकर बाढ़ से बचाव और अकाल से राहत प्राप्त करनी है तो अंतरराष्ट्रीय नदियों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित की जानी चाहिए और इस विषय पर संविधान को शीघ्र से शीघ्र संशोधित किया जाना चाहिए। हर खेत को पानी और हर हाथ को काम के

Scanned with OKEN Scanner

देश के किसान के लिए खेत भूमि का टुकड़ा मात्र नहीं है। वह धरती के साथ इस तरह चिपटा हुआ है जैसे माता के पेट के साथ बच्चा लिपटा रहता है। किसान का खेत छोटा होते होते एक हैक्टेयर से छोटा हो गया है और ३० प्रतिशत से अधिक किसान भूमिहीन मजदूर भी हो गए हैं। जिन नीतियों से ऐसा हो रहा है वे भारत के कृषक के विरोध में न होकर भारत की अस्मिता के विरोधी हैं।

सैद्धांतिक नारों के लिए विस्तारपूर्वक योजनाएँ तैयार की जाकर जनता में बहस के लिए उपलब्ध करवायी जानी चाहिए और जो राजनीति दल इन विषयों में रूचि नहीं रखते हो उन्हें केंद्रीय या राज्यों के स्तर पर सत्ता की महत्वाकांक्षाओं से अपने को दूर करना चाहिए।

भूमंडलीकरण के नारे की परिभाषा भी तमाम विकसित देशों में शक्तिशाली संगठन बनाकर बदलने की आवश्यकता है। पूरे विश्व के देशों के साधन मानवता के विकास के लिए उपलब्ध हो और अंतरदेशीय सहयोग के आधार पर गरीबों व वंचितों को किस प्रकार एक विश्व स्तर पर कम से कम स्तर पर उठाया जा सके यह भूमंडलीकरण की कार्य योजनाएँ होनी चाहिए न कि अमीर देशों द्वारा असमानताओं के आधार पर गरीब देशों का दोहन या शोषण। जब कभी भी विश्व में खुले व्यापार की चर्चा हुई होगी तो चर्चा का मूल आधार विश्व के देशों में समानता के आधार पर परस्पर सहयोग रहा होगा। अबाध प्रतियोगिता व परस्पर सहयोग का सहअस्तित्व संभव ही नहीं है। अत: ऐसा कोई सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाना नैतिक रूप से एक भूल होगी।

कृषि के क्षेत्र में विभिन्न फसलों की काश्त में विकास दर की स्थिति निम्न प्रकार रही है। खाद्यान्न की फसलों के उत्पादन में प्रति वर्ष विकास दर निम्न रही है –

प्रति वर्ष विकास दर ८०-८१ से ९१-९२ तक	
१. खाद्यान्न	२.९ प्रतिशत
२. अनाज	३.१ प्रतिशत
३. चावल	३.९ प्रतिशत
४. मोटा अनाज	०.० प्रतिशत

१९९०-९१ से १९९८-९९ तक की विकास दर	
१. खाद्यान्न	१.७ प्रतिशत प्रति वर्ष
२. मोटा अनाज	-१.६ प्रतिशत "
३. दालें	१.३ प्रतिशत "
४. गन्ना	२.९ प्रतिशत "
५. कुल कृषि उत्पादन	२.३ प्रतिशत "

इस प्रकार कृषि फसलों की उत्पादन विकास दर हमारी जनसंख्या प्रति वर्ष वृद्धि दर २.१३ प्रति वर्ष से खाद्यान्न में कम है, मोटे अनाज में नकारात्मक ही है।

स्थिति यह है कि अन्य फसलों में अब यंत्रीकरण बुआई, कटाई होने लगी है। अत: छोटे व सीमांत किसानों को साधारण फसलों की खेती तो करनी पड़ती है लेकिन यह खेती उनके लिए अधिक आर्थिक नहीं हो सकती है। खेती में अब विविधीकरण तकनीक का प्रयोग करने से ही छोटी जोतों के कि
लाभ प्राप्त हो सकता है। डेयरी
फल व सब्जियाँ व फूल उत्पा
धंधा छोटे किसानों के लिए
लाभप्रद व रोजगार प्रदान करने
है। इसी तरह से मछली पालन
से गरीब किसान निर्वाह कर रहे
तमाम धंधों में मुख्य सुविधाओं
सार्वजनिक पूँजी निवेश ही सं
सकता है लेकिन सार्वजनिक पूँजी
कृषि के क्षेत्र में पंचवर्षीय योजना
निरंतर कम हो रहा है और निजी
निवेश किसानों के लाभ का
सकता है।

सरकार के गोदाम गेहूँ व चा
भरे हुए हैं लेकिन ७ प्रतिशत जनता
सोती है इसका कारण स्पष्ट है कि
में ७ करोड़ लोगों के पास अनाज ख
की क्रयशक्ति ही नहीं है।

आर्थिक सुधारों के बाद कृ
सार्वजनिक पूँजी निवेश का प्रतिशत
से गिरता जा रहा है। १९९३-९४
कृषि में सार्वजनिक पूँजी निवेश
कृषि के पूँजी निवेश का ३३ प्रतिश
जो १९९८-९९ में केवल २३.६ प्र
रह गया है। इस देश के किसान के
खेत भूमि का टुकड़ा मात्र नहीं है।
धरती के साथ इस तरह चिपटा हु
जैसे माता के पेट के साथ बच्चा लि
रहता है। किसान का खेत छोटा हो
एक हैक्टेयर से छोटा हो गया है औ
प्रतिशत से अधिक किसान भूमि
मजदूर भी हो गए हैं। जिन नीतियों से
हो रहा है वे भारत के कृषक के वि
में न होकर भारत की अस्मिता के वि
हैं। जो लोग इन विदेशी कृषि
आयातों के हामी हैं उन्हें भविष्य के
चुनावों में गाँवों में मत माँगने के लिए
का कष्ट नहीं करना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner

यं सहायता बंद कीजिए

भरत झुनझुनवाला

वि]कास कार्यकर्ताओं में स्वयं सहायता समूह का बोलबाला है। हजारों करोड़ रुपए के
...न संगठनों के माध्यम से दिए जा
हमारे देश में इस प्रकार के अनेक
पहले भी हो चुके हैं। इन समूह
...ी वही हाल होना है। जनता की
समस्या यह है कि रोजगार के
...र नहीं है। महज ऋण तथा ट्रेनिंग
इन अवसरों को पैदा नहीं किया जा
...ा है। हाँ, लोगों को परावलंबित एवं
...मा अवश्य बनाया जा सकता है।

स्वयं सहायता समूह में १०-२०
...ों का समूह बनाकर उनकी सम्मिलित
...मेदारी पर ऋण दिया जाता है।
...सेवी संस्थाएँ उन्हें ट्रेनिंग देती हैं
... उनमें सामाजिक जागरुकता उत्पन्न
...ती है। अकसर ये समूह महिलाओं के
...ए जाते हैं। आशा की जाती है कि
...ने छोटे धंधे चलाकर महिलाओं का
...र्थिक सशक्तिकरण हो जाएगा। समूह
...ाने के लिए स्वयंसेवी संस्थाएँ आगे
...ती है। वे राष्ट्रीय महिला कोश,
...बार्ड अथवा बैंकों से स्वयं ऋण लेकर
...भार्थियों को देती हैं अथवा सीधे
...लवाती हैं।

इसमें कोई संशय नहीं है कि इस
...ार्य में लगे अधिकांश लोगों के मन में
...हित होता है। परंतु धर्म की व्याख्या
...कठिन होती है। अल्पबुद्धि लोग अनजाने में अधर्म कर बैठते है। इसलिए इस विषय की व्याख्या आवश्यक है। यह रणनीति इस मान्यता पर बनाई गई है कि गरीब लोगों के समक्ष कमाई के अवसर उपस्थित है। परंतु वे उनका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं चूँकि उनके पास पूँजी तथा ट्रेनिंग नहीं है। वास्तविकता इसके पूर्णतया विपरीत है।

हमारे गाँवों में प्रचुर मात्रा में पूँजी उपलब्ध है। ग्रामीण क्षेत्र के हर बैंक में यदि १०० रुपया जमा होता है तो केवल १५ रुपए का ऋण दिया जाता है। शेष ८५ रुपया शहर को भेज दिया जा रहा है। गाँव में पूँजी अधिक है। गाँव के समृद्ध वर्ग ७-८ प्रतिशत के ब्याज पर अपनी पूँजी को बैंकों में जमा कराते है। यदि उन्हें मिनी राइस मिल या अन्य धंधा लगाकर १५-२० प्रतिशत का लाभ मिल सकता हो तो वे उसे कर लेते। उनके पास पूँजी भी है और ट्रेनिंग लेने की क्षमता भी। परंतु वे राइस मिल नहीं लगाते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि छोटे धंधे लगाने में लाभ न्यून है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में धंधे के अवसर होते तो पूँजी शहर से गाँव की ओर क्यों भागती। जब अवसर ही नहीं है तो ऋण देने से क्या होगा?

नए अवसरों के सृजन की आवश्यकता है। पहले जहाँ केवल बाजरा होता था आज मिर्च और टमाटर

स्वयं सहायता समूह में १०-२० लोगों का समूह बनाकर उनकी सम्मिलित जिम्मेदारी पर ऋण दिया जाता है। स्वयंसेवी संस्थाएँ उन्हें ट्रेनिंग देती हैं तथा उनमें सामाजिक जागरुकता उत्पन्न करती है। अकसर ये समूह महिलाओं के बनाए जाते हैं। आशा की जाती है कि अपने छोटे धंधे चलाकर महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण हो जाएगा।

पैदा हो रहा है। जहाँ पहले लोग भेड़ चराते थे वहाँ आज गलीचे बुने जा रहे है। कई स्थानों पर अचार मुरब्बे का धंधा फैल रहा है। प्रतापगढ़ में आँवले का आचार बनाने के अनेक कारखाने लग चुके हैं। सोनीपत में पचरंगा अचार बनता है। यदि इस प्रकार के नए-नए उद्योगों का हर जगह सृजन हो तो लोग स्वयं उनमें लग जाएँगे। गलीचा बुनने के करधे लगाने के लिए लोगों को न बैंक की

Scanned with OKEN Scanner

जरूरत पड़ी थी, न स्वयं सहायता समूह की। यदि आय होती है तो बनिया उधार दे देता है। येन-केन प्रकारण आदमी करधा लगा ही लेता है बशर्ते गलीचा बिक जाए। प्रमुख बात रोजगार के अवसरों की है न कि ऋण अथवा ट्रेनिंग की।

अवसर उपलब्ध होने पर भी समृद्ध वर्ग का पलड़ा भारी पड़ता है। यदि जमींदार का बेटा राइस मिल लगाता है तो उसे पूँजी सस्ती मिलती है। वह अपनी फिक्स डिपाजिट तुड़वा सकता है जिस पर उसे केवल ८ प्रतिशत ब्याज मिल रहा था। इसकी तुलना में स्वयं सहायता समूह में ब्याज दर १२ से १८ प्रतिशत तक होती है। समूह के सदस्य के सामने जमींदार के बेटे का पलड़ा भारी पड़ता है। समूह द्वारा दिए गए ऋण इसलिए साधारणतः उत्पादक नहीं हो पाते है। उनका उपयोग उपभोग के लिए अधिक होता है। इसके अतिरिक्त समूह को इकट्ठा रखने में बहुत उर्जा लगती है। हर माह सब सदस्यों को एक साथ बैठाना पड़ता है। सबसे वसूली करनी पड़ती है। कोई कहती है कि भैंस मर गई इसलिए ऋण अदा नहीं कर सकूँगी। कोई कहता है कि भैंस ब्याही पर दूध नहीं हुआ। इस प्रकार के अनेक विवादों को हल करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति सक्षम है तो उसके लिए यही आसान होता है कि वह अपना व्यक्तिगत रास्ता खोज निकाले। यदि उसे धान खरीदना और चावल बेचना आता है और वह ऋण लेकर राइस मिल लगा सकता है तो वह व्यर्थ ही २० लोगों के समूह में अपनी शक्ति क्यों लगाए। वह अपनी अलग राह देखता है। समूह में मुख्यतः वही लोग बचते हैं जो सक्षम नहीं है। इसलिए समूह फेल हो जाता है। यदि व्यक्ति सक्षम है तो वह अपना व्यक्तिगत रास्ता खोज निकालता है और समूह फेल हो जाता है। यदि वह अक्षम है तो उन्हें चावल बेचना नहीं आता है इसलिए समूह फेल हो जाता है। स्वयं सहायता समूहों का फेल होना निश्चित है।

समूह द्वारा महिला सशक्तिकरण की बात भी गले नहीं उतरती है। मान्यता यह है कि समूह के माध्यम से भैंस बकरी खरीद लेने से महिलाओं को अपनी अलग कमाई मिल जाएगी। पति और परिवार पर उनका परावलंबन कम हो जाएगा। बात समझ में नहीं आती है। हम जानते हैं कि गाँव में अधिकतर काम महिलाएँ करती है जबकि आय पर नियंत्रण पुरुष का होता है। महिलाओं से और अधिक कार्य कराने से ... अतिरिक्त आय पर भी पुरुष ... वर्चस्व रहेगा। पहले पुरुष ... कापी खरीदने का पैसा देता था ... महिला देगी। पुरुष का पैसा बच ... वास्तव में महिला से अधिक कार्य ... की सोच उनका दोहरा शोषण करने ... है। उनका सशक्तिकरण तो कार्य ... कराकर तथा परिवार में उनका ... बढ़ाकर करना होगा। अनेक संस्थाएँ ... शर्त रखती है कि ऋण तब ही ... जाएगा जब महिलाओं का समूह ... जाएगा। मजबूरी ... गाँव वाले महिला... को आगे कर दें ... परंतु वास्तविक ... तो पुरुष के पास ... रहती है। मु... महिला का लग ... है। महिलाओं ... दोहरे शोषण ... उनके 'आर्थि... सशक्तिकरण' ... संज्ञा देना परि... दुष्चिंतन का परि... है जिसमें आ... सुख, प्रजन... परिवार, बड़े-... सबको आय की अग्नि में स्वाहा कि... जाता है।

इन समूह के माध्यम से सामूहि... चेतना का विकास भी छिछला दिख... है। यह सही है कि कई समूहों ने पंचा... में भ्रष्टाचार आदि के मामले उठाए हैं ... परंतु ये समूह स्वचालित नहीं हैं। इन... पीछे बाहरी धन से पोषित स्वयंसे... संस्थाएँ हैं। जब तक संस्थाओं का दब... रहेगा तब तक ही यह चेतना दिखें... जब इन समूह को बाहर से धन मिल... बंद हो जाएगा तो इनके स्वार्थ उन्हें ...

Scanned with OKEN Scanner

हमारी संस्कृति व्यक्तिवादी है। हर व्यक्ति को कहा जाता है कि वह स्वयं पुरुषार्थ करे और आगे बढ़े। बनिया धन कमाए, राजा अपने राज्य का विस्तार करे और संन्यासी आत्मचिंतन करे। समाज का अहित न करे परंतु स्वयं बढ़े।

नी जिनकी आज ये आलोचना । इसका प्रमाण उपलब्ध है। ह आज बंद पड़े हैं। उनके वह चेतना लुप्त हो चुकी है। में दस लाख स्वयं सहायता ने की सरकारी योजना है। ये ब फेल होंगे। अवसरों के ऋण केवल खपत के काम समूहों में अक्षम लोग ही बचेंगे फेल होंगे। महिलाओं पर कार्य बढ़ेगा। इस वस्तु स्थिति के ने में कुछ समय लग सकता है गा ऐसा ही। परंतु वर्तमान में समूह 'सफल' दिखते हैं। इसके ण हैं। एक यह कि कई स्वयंसेवी दूसरी सब्सिडी बाँटती रहती है। ज अथवा भेढ़बंदी पर सब्सिडी मिलती है जब व्यक्ति समूह का हो। हजार रुपए की सब्सिडी करने के लिए व्यक्ति २० रुपया ह जमा करा देता है। समूह चलने है। दूसरा कारण यह होता है कि से लगातार नए ऋण मिलते रहते तक नए ऋण मिलते रहते है तब समूह चलता रहता है। असलियत सामने आती है जब ऋण को अदा होता है। कर्नाटक की एक प्रख्यात सेवी संस्था का मूल्यांकन करने का अवसर मिला था। इस संस्था ने के दशक में तमाम समूह बनाए स वर्ष तक ये चलते रहे। नब्बे के में संस्था ने निर्णय लिया कि उन में अब अन्य सब्सिडी नहीं दी गी। उसी समय से हर वर्ष चौथाई बंद होने लगे। जब तक दूसरे ऋण मिलते रहते हैं तब तक ही समूह ते है।

बंगला देश तथा चीन में यही समूह ल बनाए जाते हैं। इसके दो कारण दिखते है। एक यह कि इन देशों में गाँव-गाँव में बनियों का फैलाव नहीं था। व्यक्तिगत ऋण उपलब्ध ही नहीं था। ऋण केवल समूह के माध्यम से उपलब्ध होने के कारण समूह में रूचि बनती थी। दूसरा कारण यह कि हमारी संस्कृति व्यक्तिवादी है। हर व्यक्ति को कहा जाता है कि वह स्वयं पुरुषार्थ करे और आगे बढ़े। बनिया धन कमाए, राजा अपने राज्य का विस्तार करे और संन्यासी आत्मचिंतन करे। समाज का अहित न करे परंतु स्वयं बढ़े। इसके विपरीत बंगला देश तथा चीन में सामूहिक प्रयास पर जोर है। चीन में राज्य को मसीहा माना गया है। व्यक्ति स्वयं अपना उद्धार नहीं करता है बल्कि राज्य उसका उद्धार करता है। उन देशों में सामूहिक कार्य आसान होता है। इन कारणों से वही समूह जो चीन में सफल है यहाँ विफल हो जाता है।

स्वयं सहायता समूहों का विफल होना तय है। इसके पर्याप्त संकेत भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय महिला कोष के महाप्रबंधक ने बताया कि २० करोड़ के ऋण पर ओवरड्यू पिछले वर्ष लगभग ३ करोड़ से बढ़कर इस वर्ष ५ करोड़ हो गए हैं। अनेक ऋणों पर ब्याज भी नहीं मिल रहा है। बकाया ब्याज में भी वृद्धि हो रही है। कुछ स्वयं सेवी संस्थाओं को भेजे गए पत्र भी वापस आ गए है। दूसरे सूत्रों ने बताया कि कुछ संस्थाएँ महिला कोष से ८ प्रतिशत पर ऋण लेकर बाजार में १२-१३ प्रतिशत पर लगा देती हैं। ईमानदार स्वयंसेवी संस्थाओं की तो और भी दुर्गति है। मान लीजिए उन्होंने भैंस के लिए ऋण दिया। भैंस मर गई और उस ऋण की वसूली न हो सकी। परंतु उन्हें महिला कोष को ऋण अदा करना ही होगा। कहाँ से ऋण अदा करेगी ऐसी संस्थाएँ? अनेक बैंकों द्वारा ऐसे समूहों को दिए गए ऋणों को भी वसूली नहीं हो पा रही है।

कष्ट इस बात का नहीं है कि हजार करोड़ रुपए की यह राशि डूब जाएगी। डूब भी गई तो गरीब को कुछ तो मिला। प्रमुख नुकसान यह है कि इस प्रकार के फड़के हमें सही दिशा से भटका देते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि श्रम-सघन रोजगारों का सृजन किया जाए। गलीचे के बाजार का विस्तार किया जाए। करधा लोग स्वयं लगा लेंगे। परंतु सरकार का ध्यान आम आदमी की रोजी पर नहीं है। हिंदुस्तान लीवर और पेप्सी आम आदमी की तेलधानी और रसवंती का स्वाहा कर रही हैं। आवश्यकता इसे रोकने की है। सरकार तथा गैर सरकारी संस्थाओं को नए रोजगारों के सृजन पर काम करना चाहिए। गाँव में पर्याप्त धन है और क्षमता है और अपनी महिलाओं के प्रति आदर भी है। बाकी काम वे स्वयं कर लेंगे। उन्हें हिन्दुस्तान लीवर तथा पेप्सी से बचाने की आवश्यकता है। स्वयं सहायता समूह हमें इस कार्य से भटका कर भ्रम पैदा कर रहे हैं। इन्हें तत्काल बंद कर देना चाहिए। ■

Scanned with OKEN Scanner

अतिलघु पनबिजली परियोजना से ग्रामीण आत्मनिर्भरता

■ धीप्रज्ञ द्विवेदी

हमारे देश में विद्युत का उत्पादन माँग से कम होता है। फिर वितरण में समस्या के कारण उत्पादित बिजली का भी काफी बड़ा भाग बेकार हो जाता है। क्योंकि देश के पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में समस्या केवल बिजली के कमी की ही नहीं है अपितु वितरण एवं रख रखाव की भी है. . .

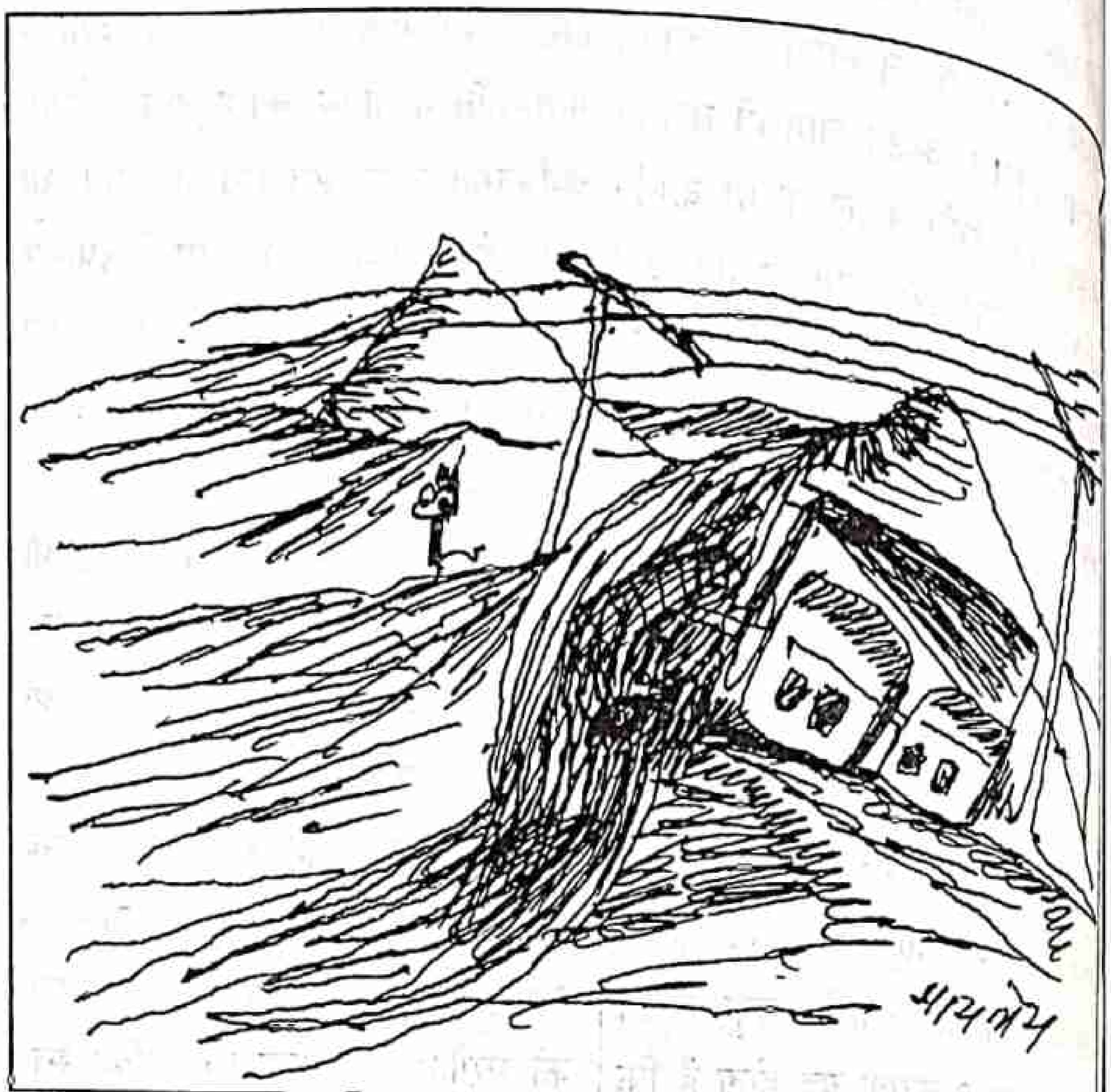

वर्तमान वैश्विक विकास का आधार ऊर्जा है। आज उन देशों का विकास सबसे ज्यादा हुआ है जिनकी प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत सबसे ज्यादा है। इस असमान विकास ने पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित समस्याएँ भी उत्पन्न की है। सबसे कम मूल्य का सबसे पर्याप्त पर्यावरण मित्र ऊर्जा स्रोत एक मात्र जल है। विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ आवागमन की सुविधा भी ठीक ढंग से उपलब्ध नहीं है वहाँ जल-ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। जल ऊर्जा के दोहन से एनरॉन जैसी कंपनियाँ एवं प्रदूषण फैलाने वाले पेट्रो पदार्थों पर ऊर्जा उत्पादन के लिए हमारी निर्भरता भी खत्म होगी।

हमारे देश में विद्युत का उत्पादन माँग से कम होता है। फिर वितरण में समस्या के कारण उत्पादित बिजली का भी काफी बड़ा भाग बेकार हो जाता है। क्योंकि देश के पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में समस्या केवल बिजली के कमी की ही नहीं है अपितु वितरण एवं रख रखाव की भी है; ये क्षेत्र अत्यंत दुर्गम है और मौसम भी वितरण व्यवस्था के प्रतिकूल रहता है। कुछ राज्यों ने तो अपने कुछ गाँवों को ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का अंग ही नहीं रखा है कारण यह है कि इन छोटी ग्रामीण बस्तीयों को ग्रिड (विद्युत वितरण केंद्र) से जोड़ना या इन तक बिजली पहुँचाना बहुत खर्चीला है और खपत कम होने के कारण निवेश पर पर्याप्त लाभ की कोई संभावना नहीं होती है। इन कारणों से हमारे देश जहाँ बिजली की भारी कमी है और पर्वतीय तथा जनजातीय क्षेत्रों में जहाँ गाँवों में ज्यादातर लोग गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले हैं, जिन्हें बिजली उपलब्ध नहीं है, वहाँ की ऊर्जा उपलब्धता को समुदाय-आधारित पनबिजली उत्पादन के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। विभिन्न राज्य सरकारें यह दावा करती है कि उनके राज्यों में सभी गाँवों का शत-प्रतिशत विद्युतिकरण कर दिया गया है जो वास्तविकता से कोसों दूर है। वास्तविकता यह है कि अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं घरेलू (कुटीर तथा लघु) उद्योग ऊर्जा की अनुपलब्धता के

बन्द होने के कगार पर है जिसका कारण बिजली के मूल्य में बढ़ोत्तरी अनियमित आपूर्ति है। भारत में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत केवल ३५० यूनिट है जबकि यह चीन में ६८७ यूनिट तथा अमरीका में ११,२९६ यूनिट है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के दिए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति बिजली उत्पादन १९००-०० में ५०७.० किलोवाट था जबकि प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता (घरेलू) ६७.९ किलोवाट थी। भारत में १९९९-०० में कुल ४४,८५६ करोड़ किलोवाट बिजली का उत्पादन हुआ जिससे जल ऊर्जा का हिस्सा ८,२८३ करोड़ किलोवाट था। भारत का ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है।

हिमालय क्षेत्र में किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार केवल ३० प्रतिशत घरों में बिजली का कनेक्शन है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार उत्तर-पूर्वी राज्यों में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत राष्ट्रीय औसत के १/३ से भी कम है। जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार एवं केरल में भी यह राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है, जबकि हिमाचल प्रदेश जो पनबिजली का प्रमुख स्रोत है, में भी प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग राष्ट्रीय औसत से कम है। अत: इन क्षेत्रों में बिजली की कमी को समाप्त करने एवं विशेषकर ग्रामीण जनता तक बिजली पहुँचाने के लिए अति लघु पनबिजली परियोजनाएँ बहुत लाभकारी होंगी। ऐसी परियोजनाओं में ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी होती है। ये ग्रामीणों के आपसी सहयोग से संचालित होती है एवं निर्मित होती है। इनको प्रोत्साहन देकर सरकार सुदूरस्थ पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में

> **प्रक्रियाओं के सरल होने, ऊपरी खर्चे कम होने एवं समुदाय द्वारा स्वसंचालित होने के कारण यह सरकारी इकाई से सस्ती बैठेंगी, स्थानीय कुटीर एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर उत्पादन मात्रा में भी समन्वय स्थापित किया जा सकेगा। अलग-थलग पड़े एवं निम्न आय वर्ग के लिए यह विद्युत प्राप्ति और क्षेत्रीय विकास का अद्‌भुत संसाधन साबित हो सकता है।**

विद्युतीकरण के कार्य को गति प्रदान कर सकती है तथा ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं के शहरों में पलायन को रोक सकती है क्योंकि ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ने के साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ग्रामीण पुनर्लाभ एवं विकास संघ द्वारा संचालित ऐसे प्रयोग जहाँ ऐसे पनबिजली घर ग्रामीणों द्वारा स्थापित किए गए हैं, इस दिशा में पथ प्रदर्शक का कार्य कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर इस क्षेत्र में पारंपरिक पनचक्कियों के अलावा गैर-सरकारी क्षेत्र में कुछ समुदायों ने सम्पूर्ण पनबिजली इकाईयाँ भी स्थापित की हैं जहाँ दिन में पिसाई एवं रात में बिजली उत्पादन किया जाता है।

भारतीय राष्ट्रीय विज्ञापन परिषद् के वैज्ञानिकों ने १९७५ में हिमाचल प्रदेश के काँगड़ा में फूलों की घाटी में ३५०० मीटर की ऊँचाई पर परिष्कृत चक्की एवं मोटर पार्ट्स के उपयोग से एक किलोवाट क्षमता का एक पनबिजली संयंत्र लगाया था। गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली एवं टेहरी क्षेत्रों में ७० के दशक के उत्तरार्ध में गाँवों में बड़ी पनचक्की सह-बिजली इकाईयाँ स्थापित की। इन क्षेत्रों में कुछ व्यक्तियों ने अपनी पनचक्कियों के आधुनिकीकरण के जरिए ५ किलोवाट तक बिजली का उत्पादन किया जिससे आसपास के गाँव भी लाभान्वित हुये। इनमें से कई इकाईयाँ अब व्यावसायिकरण एवं प्रबंधकीय कौशल के अभाव में वर्षों से बंद पड़ी है। इनकी अतिरिक्त ऊर्जा के वितरण एवं व्यवसाय के द्वारा इन्हें लाभकारी उपक्रमों में बदला जा सकता है। इनके बंद होने में सरकार की अदूरदर्शी नीतियों का भी महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार ने पर्यावरण के लिए हानिकारक पेट्रो उत्पाद आधारित चक्कियों के स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जिनसे विदशो पर हमारी निर्भरता भी बढ़ गयी। ये चक्कियाँ घरों के नजदीक स्थापित किए जा सकने के कारण ज्यादा लोकप्रिय हुईं क्योंकि पनचक्कियों की स्थापना नदीयों, नालों या नहरों के पास ही स्थापित की जा सकती थीं।

पनबिजली उत्पादन के इन व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासों को सरकारी असहयोग एवं अदूरदर्शिता के कारण असफलता का मुँह देखना पड़ा। कई स्थानों पर सरकारी क्षेत्र में भी अति लघु पनबिजली परियोजनाएँ स्थापित की गई थी। इनमें से कई बहुत सफल रहीं और लम्बे समय तक कार्यरत रहीं जबकि कुछ मोटर पार्ट्स की अनुपलब्धता और संबंधित विद्युत बोर्डों की बदहाल आर्थिक स्थिति के कारण बंद हो गयीं। स्थानीय लोगों के लिए लाभकारी होने के बाद भी ये पनबिजली परियोजनाएँ कुशल प्रबंधन के अभाव में राज्य सरकारों के लिए घाटे का सौदा रही हैं। इनके बिजली का उपयोग घरों में रोशनी

Scanned with OKEN Scanner

देने के लिए किया जाता है। जिससे प्राप्त मूल्य से बिजली घरों का रखरखाव भी नहीं हो पाता है। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार को अपनी वर्त्तमान ऋणं कृत्वा धृतं पीवेत् वाले चार्वाक दर्शन से मुक्ति पानी होगी और ग्रामीण क्षेत्रों के लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर इन परियोजनाओं से हो रही हानि हो खत्म करना होगा। इन क्षेत्रों में स्थापित पनबिजली परियोजनाओं से उत्पादित बिजली का उपयोग वहाँ के लघु एवं कुटीर उद्योगों में कर रोजगार की संभावनाओं को भी बढ़ाया जा सकता है। इन उद्योगों से होने वाले उत्पादन पूर्णत: स्वदेशी होंगे और राष्ट्र को स्वावलंबी बनाने में सहयोगी होंगे। इन उद्योगों में बिजली के उपयोग से राज्य बिजली बोर्डों को इन लघु पनबिजली परियोजनाओं से हो रहे हानि को समाप्त करने में सहायता मिलेगी और ये परियोजनाएँ राज्य सरकारों के लिए सफेद हाथी नहीं रह जाएंगे। देश में पनचक्कियों की कुल संख्या लगभग २,५०,००० है। पारंपरिक पनचक्कियाँ २ से ५ मीटर की ऊँचाई वाले दाब से कार्य करती हैं और प्रति सेकेण्ड २० से २०० लीटर पानी का उपयोग करती है। अत: इनका उत्पादन पानी की उपलब्धता पर निर्भर करता है। जो हर मौसम में जल की उपलब्धता के अनुसार बदलता रहता है।

ये परियोजनाएँ पर्यावरण संगत हैं एवं पर्वतीय क्षेत्रों के लिए उपयुक्त भी। इनमें पुनर्स्थापना आदि की समस्याएँ भी नहीं हैं जो कुण्ड एवं बाँध बनाते समय आती है। अति लघु पनबिजली परियोजनाएँ केवल छोटे क्षेत्रों (विशेषकर छोटे-गाँवों) के लिए हैं और जमीन तथा पानी की उपलब्धता की समस्या से सभी ग्रामीण मिलकर निबट सकते हैं। १५ से २० वर्ष के जीवनकाल वाले एवं एक ५००० के आसपास आबादी वाले गाँव की विद्युत आवश्यकता को पूरा करने के लिए विद्युत उत्पादन गृह के निर्माण की लागत ६० हजार रुपए प्रति किलोवाट के लगभग होगी। प्रक्रियाओं के सरल होने, ऊपरी खर्चे कम होने एवं समुदाय द्वारा स्वसंचालित होने के कारण यह सरकारी इकाई से सस्ती बैठेंगी, स्थानीय कुटीर एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर उत्पादन मात्रा में भी समन्वय स्थापित किया जा सकेगा। अलग-थलग पड़े एवं निम्न आय वर्ग के लिए यह विद्युत प्राप्ति और क्षेत्रीय विकास का अद्भुत संसाधन साबित हो सकता है।

संयंत्र की स्थापना के बाद घरों में बिजली की खपत को प्रोत्साहित करके एवं ग्रामस्तरीय उद्योगों की स्थापना द्वारा प्लांट फैक्टर को बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले सभी घरों में विद्युतीकरण किया जाए, फिर संचार माध्यमों, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों एवं अन्य ग्रामीण कुटीर एवं लघु उद्योगों को बिजली उपलब्ध कराई जाए। बिजली शुल्क एवं संयंत्र के रखरखाव, विकास गतिविधि विस्तार आदि को ध्यान में रखते हुए तय किया जाए। इस प्रकार की योजनाओं में स्थानीय जन की भागीदारी बहुत बड़ी मात्रा में होगी क्योंकि यह उनके अपने प्रयासों से स्थापित होगी और इनमें कोई बाहरी दखल भी नहीं होगा।

इस प्रकार के बिजली घरों की सफलता में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होगा सामुदायिक भागीदारी एवं स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे जारी रखने की दृढ़ इच्छाशक्ति का। राज्यों के विद्युत अधिनियमों में परिवर्तन कर इन विद्युत गृहों से उत्पादित अतिरिक्त बिजली को राष्ट्रीय ग्रिड के भी उपलब्ध कराया जा सकता... हिमालय क्षेत्र में ५० किलोवाट से कि... क्षमता वाली सूक्ष्म पनबिजली इकाई... की स्थापना की पर्याप्त संभावनाएं हैं... इन बिजलीघरों का रखरखाव भी आ... है। प्रशिक्षण देकर ऐसी इकाईयों... ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोत्साहन दिया... सकता है। ऐसी इकाईयों के लिए मशी... का निर्माण सरल है और इस तकनी... का हस्तांतरण भी अपेक्षाकृत आसान है।

दूरदराज के क्षेत्रों में बिजली... रोजगार बढ़ाकर ये संयंत्र वहाँ के लो... के जीवनस्तर में परिवर्त्तन ला सकते हैं... सबसे बढ़कर तो यह कि इन बिज... घरों की बिजली हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को... आत्मनिर्भर बनाएगी जिसका प्रभा... सम्पूर्ण राष्ट्र पर पड़ेगा और दे... आत्मनिर्भर होगा। इसके लिए आवश्यक... यह है कि चार्वाक दर्शन को मानने वाले... कर्ज (जो हमें आर्थिक गुलाम बनाता है) की तरफ देश के विकास के लि... दिन-रात देखने वाली सरकार अपने दे... के संसाधनों पर भी ध्यान दे तो देश का विकास ज्यादा बेहतर और ज्यादा ते... गति से हो सकता है। हर परियोजना के लिए विदेशी संगठनों एवं विकसित राष्ट्रों के आगे पैसे के लिए भिक्षां देही! की मुद्रा में खड़ी सरकार को यह देखना होगा कि बिना किसी बाहरी आर्थिक सहायता के अमरीका, जर्मनी, रूस, जापान जैसे राष्ट्रों ने अपना विकास कैसे किया? आवश्यकता राष्ट्रीय नीतियों में बदलाव की है ताकि ग्राम स्वराज की राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी की अवधारणा को पूरा किया जा सके। इसे पूरा करने के लिए गाँवों का विकास आवश्यक है और ग्रामीण विकास में अतिलघु पनबिजली परियोजनाओं का बेहद महत्वपूर्ण योगदान होगा। ■

Scanned with OKEN Scanner

आगरा शिखर वार्ता के अवसर पर विशेष

...श्मन की बेटी और नूर मियाँ के बीच से

...। प्रमोद कुमार दुबे

...ी परंपरा केवल अभेद और निर्द्वन्द्व होने का ... नहीं पढ़ाती, यह मात्र भेद और द्वंद्व की ...ा नहीं देती, यह राज्य और अर्थ की व्यवस्था ...ूर रहने वाले वैरागियों का कुनबा नहीं है। ...परंपरा परस्पर भिन्न और प्रतिस्पर्धी प्रवृत्तियों ... लोकमंगल की मथनी से मथती है, ...व-संकल्प के ताप से तपाती है और.........

दिनांक २९-१-९५, रविवार के नवभारत टाइम्स में साहित्य- संस्कृति के पन्ने पर मैंने सुहेल वहीद का एक लेख 'औरत के पक्ष में तेज तर्रार शायरी' पढ़ा था। यह ...ड पाकिस्तानी शायरा परवीन शाकिर पर लिखा गया था। लेख में ...यरा परवीन की एक शायरी उधृत थी। उसका शीर्षक था – ...शतरफा (साझा) दुश्मन की बेटी'। शायरी देखिए –

> रेस्तूरां के नरोज में जैसे
> हाईब्लड प्रेशर इंसान के जिस्म की जैसी झल्लाहट
> दर आई थी,
> यह कैफियत कुछ लम्हें रहती
> तो हमारे जहनों की शिरयाने फट जाती
> लेकिन उस पल, आर्केस्ट्रा खामोश हुआ
> और लता की रस टपकाती शहद आगी आवाज
> कुछ ऐसी उभरी-
> जैसे हब्स जदा कमरे में
> दरिया के रूखवाली खिडकी खुलने लगी हो
> अनदेखे हाथों की ठंडक
> प्यार की शबनम छिड़क रही थी।

सुहेल वहीद के विवरण से जानकारी मिली थी कि परवीन ...शाकिर चीन के एक रेस्तरां में आर्केस्ट्रा की आवाज के चपेट में आ ...गयी थी। यदि उच्च रक्तचाप की झल्लाहट तक पहुँचा देने वाला ...वह खामोश नहीं हो जाता तो संभव था, शायरा की शिराएँ फट ...जातीं। आर्केस्टा के बन्द होने के बाद शायरा को भारत की सुप्रसिद्ध ...गायिका लता मंगेस्कर के गाए गीत सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ...बकौल शायरा, लता की आवाज शहद-सी मीठी, रस से भरी ऐसी अनुभूत हो रही थी जैसे दरिया की ठंड हवा को घुटन भरे कमरे में भर देने वाली कोई खिड़की खुल गयी हो, प्यार की ठंडी ओस अनदेखे हाथों से फुहर बन झर रही हो। ऐसा प्रमिल स्पर्श – ऐसी प्राणवान अनुभूति पाने के बाद परवीन के दिल में लता पराई नहीं, अपनी लगीं। बिल्कुल पराए दमघोंटू वातावरण में अपनापन देनेवाली लता की आवाज से वह एकाकर भी हुई। तभी तो परवीन को लता में एक भीतरी साझापन का अनुभव हुआ। लेकिन इस शायरा का पाकिस्तानीपन सारी रेशमी अनुभूतियों को कुचल कर आगे बढ़ा और शायरा ने लता को दुश्मन की बेटी कह दिया। अपने जन्म से लेकर आज तक भारत से दुश्मनी का ऐलान करनेवाले पाकिस्तान की खूबी परवीन में न हो तो वह किस बात की पाकिस्तानी शायरा? पाकिस्तान की यह जन्मजात विशेषता छिपने वाली नहीं है। इस विशेषता को निभाए बिना पाकिस्तान की पहचान खतरे में पड़ सकती है।

हमने सुना है कि शायर बड़े ऊँचे ख्याल वाले सर्वव्यापी भावना के अतिसंवदेनशील प्राणी होते हैं। इसीलिए 'कवनो मकाँ' यानि कायनात – जिसे विश्व व्यापक छन्दोधारा या समष्टिचित्त कहा जाता है, में होने वाले किसी हादसे का असर सबसे पहले शायर के दिल पर ही होता है –

> जब कोई हादसा-ए-कवनो मकाँ होता है,
> सबसे पहले शायर के दिल पे अयाँ होता है।

इतने बड़े दिल के शायर को सियासत का दायरा कितना बौना

Scanned with OKEN Scanner

पूरी दुनिया ने गिनती-पहाड़ा भारत से सीखी थी, अरब और यूनान में हमारे देश से गणित गया – हिन्दसाँ की यादें जरूरी है, न कि मदरसों – इमाम बड़ों की। क्यों? पहला कारण यह कि पराधीन भारत के आत्मगौरव और स्वातंत्र्य चेतना की वैश्विक हुँकार स्वामी विवेकानंद के स्वर में वैदिक गणित के शून्य को माध्यम बना गूँज उठी थी।

बना देता है, इसका उदाहरण परवीन जैसी शायरा की मानसिकता में साफ देखा जा सकता है। हालाँकि वह चीन के रेस्तरां में बैठकर सियासत के दबाव से बच नहीं सकती थी। पाकिस्तान से चीन पहुँचकर वहाँ से भारत के बारे में कैसी राय रखी जा सकती है, परिस्थिति के अनुसार उसने ठीक ही राय जाहिर की होगी।

ठीक इससे उलट हिन्दी के एक कवि केदारनाथ सिंह को सुर्मेवाले नूरमियाँ के पाकिस्तान चले जाने से उत्पन्न अभाव की पूर्ति का कोई रास्ता नहीं दिखता। केदारनाथ सिंह के भीतर का कवि उनसे सवाल करता है –

> तुम्हें नूरमियाँ की याद है केदारनाथ सिंह –
> गेहुए नूरमियाँ,
> ठिगने नूरमियाँ
> रामगढ़ बाजार में सुर्मा बेंचकर
> सबसे अन्त में लौटने वाले नूरमियाँ,
> क्या तुम्हें कुछ भी याद है केदारनाथ सिंह?
> तुम्हें याद है मदरसा,
> इमली का पेड़,
> इमाम बाड़ा?
> तुम्हें याद है शुरू से आखिर तक
> उन्नीस का पहाड़ा?
> क्या तुम अपनी भूली हुई स्लेट पर
> जोड़-घटाकर
> यह निकाल सकते हो
> कि एक दिन अचानक तुम्हारी बस्ती को छोड़कर
> क्यों चले गए थे नूरमियाँ........?

सूर्मा की शीशी और सींक लेकर केदारनाथ सिंह की बस्ती छोड़ अचानक नहीं चले गए थे नूरमियाँ, वह देश के विभाजन के लम्बे जद्दोजहद में शामिल थे। उन्होंने पाकिस्तान बनवाने के स्वीकृति-पत्र खुद पेश किया था। बड़ी ईमानदारी से वे पाक-जमीन पर कब्र में सोकर कयामत का इंतजार करने चले गए। केदारनाथ सिंह की स्मृति समाज में भ्रम न फैलावे इसलिए कहना जरूरी है कि पूरी दुनिया ने गिनती-पहाड़ा भारत से सीखी थी, अरब और यूनान में हमारे देश से गणित गया – हिन्दसाँ की यादें जरूरी है, न कि मदरसों – इमाम बड़ों की। क्यों? पहला कारण यह कि पराधीन भारत के आत्‍ और स्वातंत्र्य चेतना की वैश्विक हुँकार स्वामी विवेकानंद के में वैदिक गणित के शून्य को माध्यम बना गूँज उठी थी। हमारे के उच्चतम ज्ञान का ऋण दुनिया पर है, किसी दूसरे का नहीं। कारण यह कि इन दिनों के मदरसे देश की सीमा-क्षेत्र में बड़े पर खुल रहे हैं। इनमें कौन-सी तालिम दी जा रही है, कौन-सा रटाया जा रहा है, इससे लोगों को बेखबर करना देश के साथ होगी।

आज पूरे देश को जानना जरूरी है कि दारूल इस्लाम को से जेहादी मानसिकता लामबंद होने लगी है। इसकी संचालक को वास्तव में किसी आसमानी सत्ता से कुछ लेना देना नहीं। सियासत चाहिए। लेकिन यह भी अकाट्य सत्य है कि हम हो वे लोग हो सकते हैं, क्योंकि हम किसी के अस्तित्त्व को नहीं न जब वे लोग होंगे, तो हम नहीं होंगे, क्योंकि वे लोग किसी अस्तित्त्व नहीं स्वीकारते। दुनिया का रखवाला ऐसे लोगों को ही चाहेगा जो सबके रहने से खुश हों, जो किसी के भी विछ से छटपटा उठें। संभव है, इसी सनातन सहिष्णुता के संस्कारों से केदारनाथ सिंह को पाकिस्तान गए नूरमियाँ सूर्मेवाले को याद की विवशता पैदा हुई हो। संभावनात्मक ढंग से कहने का कारण है कि 'सनातन सहिष्णु संस्कार' के साथ चाहे जितनी आत्मी हम किसी प्रगतिशील कवि को जोड़ें, वह उसे केसरिया आं दूर भागना चाहेगा।

मुझे जिस यथार्थ से परिचय हुआ, वह नूरमियाँ के मानि था। वह ताहिर 'मोली साहेब' के शक्ल में था। मौलवी साहब हाई स्कूल के एक प्रतिष्ठित शिक्षक थे। बड़े अलमस्त शेरो सुनाकर वाहवाही लूट लेने वाले। मगर वह बड़े जागरूक भी थे दिन की खबरें पढ़ना उनकी आदत थी। वह मेरे बाबा के पास आते और इस्लामी देशों की दशा पर अखबारी खबरों के मुता

Scanned with OKEN Scanner

तो। उनके विषय में सब जानते थे कि वह देश के विभाजन पाकिस्तान बसने चले गए थे। मगर वहाँ की हकीकत देख न्मभूमि पर लौट आए। हम उनसे पूछते, 'मोली साहेब' आप ना से क्यों भाग आए? मौलवी साहब बिगड़ते, धकियानूसी पुष रहो। धकियानूस क्या होता है, हम ठीक-ठीक नहीं पर इतना जरूर लग जाता कि ओछा, संकुचित, संकीर्ण के वह इस शब्द का प्रयोग करते हैं। वे कौन लोग थे, जिन्होंने साहब के मन में एक सदमे की तरह पाकिस्तान के प्रसंग यानूस शब्द को बैठा दिया था? शायद वे लोग थे, जिन्होंने जज्बात को सियासत के लिए इस्तेमाल किया था। पाकिस्तान ना दिखाने वाले लोग उन लोगों के लिए गैरत रखते थे, जो ल छोड़कर वहाँ रहना बसने जा रहे थे। उन शरणार्थियों की में रहना मौलवी साहब को मंजूर नहीं था। वह पढ़े-लिखे सैयद ने बनारस में रहकर अरबी-फारसी की पढ़ाई की थी। उन्हें और परंपरा की जानकारी थी। उन्होंने बनारस में रहते हुए संगति पाई थी। उन्हें वैदिक विद्वानों से भी परिचय था। वह क कार्यक्रमों में वेदपाठी ब्राह्मणों की नकल उतार कर सबको कर देते थे। इससे किसी हिन्दू को चिढ़ते हुए मैंने नहीं देखा कि मेरा गाँव जूझारू विद्वानों से रहित नहीं था और न उस ल का प्रांगण कहीं से भी सुस्त था। ऐसे खुले माहौल से बनी भूमि में किसी नूरमियाँ की यादें महत्त्व नहीं रखतीं, वह न छोड़कर पाकिस्तान अपनी मर्जी से गए। उन्हें याद करना लता के नाम पर सिर्फ एक दिखावा है – खोखला दिखावा। र्थ नहीं हो सकता, जिसमें साफ-साफ बातें न हो। बिना किसी के हम यही चाहते हैं और चाहते रहेंगे कि हमारी भारत माता स्मिता सम्पूर्ण विश्व में शीर्ष पर हो, इसके विरुद्ध स्वप्न में चने वाला कोई शत्रु पृथ्वी पर न रहे।

हम देव परंपरा के वंशधर विश्व में पारस्परिकता मैत्री और के भाव रखते हैं। हम इसी भावना की अपेक्षा दूसरों से भी हैं। लेकिन सभी व्यक्ति इसी मानसिकता के नहीं है और न सुरों-दस्युओं की परंपरा भी रही है। अपने अहंकार के आगे का अस्तित्व नहीं मानने वाले लोग भी हैं। वे सहयोगी को मित्र अपना अस्तित्त्व रखने वाले व्यक्ति को शत्रु घोषित करके चलते शासक और शासित का भौतिक महत्व समझते हैं। वे दुनिया कूमत करना बहुत बड़ी बात समझते हैं। यह काम उनके लिए का विषय है, आक्रमण और विस्तार उनका उत्तम कर्म है। जीत में जीवन की सक्रियता अनुभव करने वाले ऐसे लोग प्रकृति ल शासन-सत्ता को सजीव नहीं मानते, धर्म के स्वतः अस्तित्त्व स्वीकार नहीं करते, उनकी हर धारणा किसी काल में किसी के बनाई हुई होती है। उनमें शाश्वत तत्वों का अभाव होता है। त सत्ता के शासन को नहीं मानने वाला जन-समूह धनाश्रित होता और उसका सबसे बड़ा लक्ष्य राज्य-भोगना होता है।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के सहस्रों विद्यार्थियों की भांति मैं जिस परिचय-पत्र को अपनी जेब में रखता रहा, उसमें एक विख्यात श्लोक लिखा हुआ था –

न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं नाऽपुनर्भवम्।
कामये दुःख तप्तानां प्राणिनामार्ति नाशनम्।।

मुझे राज्य की कामना नहीं है, न स्वर्ग पाने की लालसा, न ही मोक्ष की। मैं दुःख की आँच में झुलस रहे प्राणियों के कष्ट दूर करूँ – यही मेरी कामना है – उस गुरुकुल के संस्थापक ने अपने स्नातकों के मन में ऐसी कामना रोपने का प्रयास क्यों किया, जिसमें राज्य, स्वर्ग या मोक्ष का कोई स्थान नहीं? जिस राज्य के लिए दुनिया में संहार का ताण्डव होता रहा है, जिस स्वर्ग के लिए देवासुर संग्राम होता है, जिस मोक्ष के लिए लोग सर्वस्व त्याग कर कठोर तप करते हैं – ऐसी कामनाओं से हमें गुरु ने वंचित रहने का पाठ क्यों पढ़ाया? मुझे पूरा विश्वास है कि प्रातः स्मरणीय पूज्य पं. मदनमोहन मालवीय जिस भावी पीढ़ी के निर्माण से भारत के अभ्युदय का स्वप्न देखते थे वे उन अपनी मानस-संततियों को सबसे श्रेष्ठ मार्ग पर प्रवृत करना चाहते होंगे। फिर भी मैं संसार के ढाँचे को देख विचलित हूँ कि वही महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसे राज्य चाहिए, जिसे स्वर्ग और मोक्ष चाहिए। इन्हीं पदों की प्राप्ति के लिए संसार में भीषण द्वंद्व चल रहा है। धनार्जन का द्वंद्व भी इन सभी द्वंद्वों में आज पीछे नहीं है। जिसने विपुल धन-साधन पर अधिकार कर लिया है वह राज्य कामना के लोगों को मुहरों की तरह राजनीति की बिसात पर रखता-उठता है। मैं संशय ग्रस्त हो जाऊँ तो कोई आश्चर्य नहीं कि हमें केवल दुःख की आँच में झुलसते प्राणियों की पीड़ा को दूर करने का काम ही हाथ में क्यों लेना चाहिए? लेकिन जब हम ईश्वर के अवतार श्रीराम और श्रीकृष्ण जैसे विभुओं के आदर्शों को देखते हैं उनके वाक्यों को पढ़ते-सुनते हैं, तब संशय का अंधकार दूर होने लगता है – 'मैं दुष्टों के नाश और सज्जनों के परित्राण के लिए – प्रत्येक युग में धर्म की संस्थापना के लिए आविर्भूत होता हूँ' – अवतरण का यही संकल्प है। राज्य के लिए, स्वर्ग और मोक्ष के लिए अवतार नहीं होता। दुःख तप्त प्राणियों को आर्त दशा से मुक्ति दिलाने के लिए अवतार होता है। यही शिव-संकल्प मनुष्य की छोटी क्षमताओं में भी चरितार्थ हो, तभी विश्व में परस्पर बंधुत्व जागृत रहेगा।

इसी कल्याणप्रद संकल्प को केंद्र बनाकर राज्य की या धनार्जन की व्यवस्थाएँ बनती हैं। यदि इस केंद्र से विचलित होकर ये व्यवस्थाएँ खड़ी होती है तब इनसे लोक में पीड़ा प्रारंभ हो जाती है। यह पीड़ा जगत-नियंता के लिए असह्य हो जाती है। विश्व के श्रेष्ठ मानसिकता वाले प्राणियों में इस पीड़ा की प्रतिक्रिया होने लगती है। जन-जन के मन की एकत्रित असहमतियाँ आंदोलन का रूप ले लेती है और तब जनविरोधी व्यवस्थाएँ समाप्त होती हैं और जनहितकारी व्यवस्थाएँ बनती हैं। अर्थात् 'दुःख तप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्' की कामना में ही युगानुरूप नई व्यवस्थाओं को निर्मित करने का अंतर्भूत संकल्प भी है। इसी में परिवर्तन और सृजन दोनों की भूमिका है। इसी में हमारे पूज्य अवतारों द्वारा आद्योपांत दिखाया हुआ मार्ग अर्थात् आदर्श भी निहित है। इस वास्तविकता को देखा – ऐसा नहीं लगता कि हमारे

Scanned with OKEN Scanner

गुरुकुल के संस्थापक ने अपनी मानस संततियों से लोक और लोकोत्तर भूमिकाओं दूर रहने की अपेक्षा की है, उन्होंने समस्त व्यवस्था को लोक मंगल लक्ष्य के संधान का साधन मान इनके परिवर्तन और सृजन की ओर प्रेरित किया है।

जिस समाज से नवीन व्यवस्था-निर्माण की शक्ति समाप्त हो जाती है उस समाज के लोग प्रचलित राज्य व्यवस्था में स्थान के लिए प्रयास करते हैं। राज्य उनका मुख्य केंद्र हो जाता हैं और तब वे लोग सियासत के मातहत ही सोंचते हैं। उनकी चेतना सिर्फ सत्ता सिंहासन के कदमों के नीचे मचलती हैं। यदि वह ऐसा नहीं करे तो उन्हें आगे आने का प्रश्रय नहीं मिलता। समाज की ऐसी व्यवस्थाएँ जब अपने अन्तर्द्वन्द्वों से टूटती हैं, तब व्यापक समाज को भी पद दलित कर देती हैं। इनमें शाश्वत तत्वों का आधार नहीं होता। यह अपने पोषण के लिए दूसरों को लूटने में विश्वास रखती हैं। इनके दुराचार से दूसरों में भी आक्रामकता बढ़ती है।

भारत में राज्य और व्यवसाय की सबल व्यवस्थाएँ होने के बावजूद ये धर्म का अतिक्रमण नहीं करती थीं। गाँवों में रहने वाला व्यापक जनजीवन अपने उद्यमों से स्वालम्बी था। अर्थ और न्याय की ग्रामीण व्यवस्थाएँ को अधिकतम स्वतंत्रता प्राप्त थी। व्यक्ति-व्यक्ति उत्पादन कौशल से सम्पन्न था। उनका जीवन कई भाव-पोषक आचारों से बंधा हुआ था। उत्सवों-पर्वों और ऋतुओं के उल्लास से उनकी जीवनचर्या संचलित होती थी। मैं इसे छंदित जीवन की संस्कृति कहना चाहता हूँ। इस सामाजिक संरचना में चौबीस घंटे की दिनचर्या के हर पड़ाव पर किसी न किसी गीत की उपस्थिति होती थी। श्रम के साथ गीत, ऋतुओं पर्वों के साथ गीत, जन्म से विवाह तक गीतों की सहचर्या बनी रहती। ये गीत जिस मानसिकता का निर्माण करते हैं उसमें किसका शासन होता हैं? किसी भी बनावटी राज्य का शासन नहीं, बल्कि इनमें समुचित आत्मभाव के शासन की स्वीकृति होती है। इसीलिए नातों-रिश्तों में बँधा भारत का ग्रामीण जनजीवन एक बहुत बड़ी स्वतंत्र-शक्ति था, जिसकी आस्था का केन्द्र कोई सर्वत्यागी महात्मा हो सकता था जिसे प्रभु की परम सत्ता और उसके जगत के अतिरिक्त कुछ भी याद रखना आवश्यक नहीं होता। इसी महात्मा में दुख-तप्त प्राणियों के कष्ट दूर करने का संकल्प निहित होकर समाज का प्रधान आचरण बन जाता था। लोकजीवन की यह छंदस् व्यवस्था पराधीन हुए भारत में टूटने लगी। इस ध्वंस का क्रम आज भी गतिशील है, जिसके कारण हम दिन-दिन उदासी की ओर बढ़ते जा रहें हैं। हम शास्त्रों में यह तो देखते हैं कि हमारी धर्म-संस्कृति कितना समरस कितना उज्ज्वल रही है। लेकिन, वह व्यवहार को भूमि पर चरितार्थ नहीं होती-तो क्यों? इसलिए कि बीच की कड़ी टूट गई। किसने तोड़ा इस कड़ी को? आक्रांताओं ने कैसे? शोपण और यातना देकर, हमारी व्यवस्था में विजातीय आसुरी प्रवृत्तियों को प्रवेश दिलाकर। आज भी आक्रांता प्रवृत्तियों का फैलाव रुका नहीं है। वह हमारे समाज को धन, प्रचार और सत्ता के जोर पर वास्तविक धर्म से विमुख कर पतन की ओर ले जाने में लगी हैं। परिवार, समाज और देश की सारी बुनावटों को तोड़ कर किसी व्यक्ति को कैसे भक्षण किया जा सकता है इसके लिए उनके द्वारा औजार विकसित किये जा चुके हैं। इस लाभकारी हिंसक धंधे में विज्ञापन और फिल्मवालों सहित राजनीति और तथाकथित धर्म के प्रचार में लगे लोग भी शामिल हैं।

प्रकृति से प्राणी के जीवन का लयात्मक संबन्ध ही वह छंद है जिससे शक्ति मिलती है, जीजिविषा बढ़ती है, हर्ष-उल्लास मिलता है। यह छंद हमारे राष्ट्रीय जीवन को घोर विपत्तियों में भी बचा रखा है। जो कोई तथाकथित धर्म प्रचार, राजनीतिक या व्यवसायिक प्रपंच हमारे इस छंद को तोड़ता है, वह हमारा कल्याण नहीं करना चाहता, हमें जड़ से काटकर समाप्त कर देना चाहता है। इसी जीवन-छंद ने हमें अपना गौरवशाली इतिहास और सतत् प्रवाहमान परंपरा दिया है। हमने इसके बल पर आक्रांताओं की यातना झेलकर अपनी अस्मिता बचा रखी है।

जिस प्रकृति में प्राणी का जन्म हुआ है, वहाँ की मिट्टी-हवा-पानी-वनस्पति, नदी, पहाड़, झरने और ऋतुएँ उस प्राणी की चेतना का आधार होती हैं। यही पंचतत्व देह को साकार करते हैं इन्हीं से जीवन का छंद, लय, राग और गीत बनता है। प्राणी की जीवन सम्बन्धी आवश्यकताएँ पूरी होते ही वह प्रकृति की उल्लास में एकाकर होकर प्रसन्नचित्त झूम उठता है। यदि उसके जीवन में समाज या राज्य व्यवस्था से अभाव और संत्रास आरोपित नहीं हो तो इस छंद से वह प्राणी वंचित नहीं हो सकता। स्वामी रामकृष्णदेव के बचपन की एक घटना है, वर्षा की ऋतु थी, आकाश में घनाघोर काली घटाएँ छाई हुई थी। वह मूरी खाते हुए धानखेतों की मेड़ से जा रहे थे। उन्होंने आकाश में छाए मेघों को देखा। उस समय सफेद बगुले पँक्तिबद्ध उड़े जा रहें थे। उस दृश्य ने उन्हें विभोर कर दिया। उन्हें देह की सुधि नहीं रही। वह मेड़ से गिर गये। इस प्राकृतिक दृश्य के विषय में विचार करने पर ऐसा लगता है कि स्वामी रामकृष्णदेव ने उस समय प्राकृतिक दृश्य में आत्मविभोर कर देने वाली माँ श्यामा के रूप को देखा होगा। पवन वेग से गतिमान काली घटाओं पर श्वेत बक-पक्तियाँ उन्हें मुण्डहार की भाँति लग रही होगी। इस दृश्य में तदाकार की स्वाभाविक स्थिति के कारण उनकी देह की सुधि खो गई। इस प्रकार के अनुभव अपनी-अपनी प्रवृतियों के अनुसार प्रत्येक प्राणी प्रकृति के साथ जुड़कर करता है। कोई एक क्षण, कोई कुछ घड़ी, कोई-कोई बहुधा, इन अनुभूतियों से रसान्वित होता है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन देवात्मा हिमालय को छोड़ कहीं और आत्मीयता अनुभव नही करते थे। ये प्रसंग सर्वविदित हैं, लेकिन लोक-जीवन में सर्वव्याप्त अनुभवों की गिनती संभव नहीं। मुझे तो इन प्रसंगों से

Scanned with OKEN Scanner

ही कहना है कि प्रकृति से प्राणी के जीवन का लयात्मक ी वह छंद है जिससे शक्ति मिलती है, जीजिविषा बढ़ती है, लास मिलता है। यह छंद हमारे राष्ट्रीय जीवन को घोर ों में भी बचा रखा है। जो कोई तथाकथित धर्म प्रचार, क या व्यवसायिक प्रपंच हमारे इस छंद को तोड़ता है, वह कल्याण नहीं करना चाहता, हमें जड़ से काटकर समाप्त कर हता है। इसी जीवन-छंद ने हमें अपना गौरवशाली इतिहास तत् प्रवाहमान परंपरा दिया है। हमने इसके बल पर आक्रांताओं तना झेलकर अपनी अस्मिता बचा रखी है।

गंगा के तट पर बसे एक भोजपुरिया गाँव है गहमर। इसके में समकालीन भोजपुरी साहित्य पढ़ते हुए मैं आंनद सन्धिदूत ु से जातीय इतिहास के कुछ अनमोल उदाहरण से परिचय इसी तरह के जातीय इतिहास में अनलिखे वास्तविक प्रसंग होते हैं, जिनसे मुगलकालीन आक्रांताओं से हमारे संघर्ष की सामने आती है। सन्धिदूत ने लिखा है कि जब गहमर (उत्तर) के चौधरी अवधूत राव के समय मुगल सेना में लगान ने आई, अवधूत राव ने लगान देने से साफ मना कर दिया। त राव को नाना प्रकार की यातनाएँ दी गई। उनके नखों में ठोकी गई, काँटों पर सुलाया गया, खौलते पानी से नहलाया मुगलों की लाख यातनाएँ सहने के बाद भी जब वह नहीं झुके, ुगल लौटने लगे। उन्हें रास्ते में करकट डोम मिला। उसे पकड़ उन्होंने तलाशी ली। उसके पास दो मुगलिया सिक्के मिले। ों ने उसका पैसा छीना और गमहर गाँव का पट्टा थमा दिया। घटना बगीचे में पत्ते बटोर रहे एक कानू (भड़भूजा) ने देखा। ने हाथ उठाकर गाँव की देवी कमच्छा माई से कहा, अब तुम्हारी पा ही आधार है। इतना कहते कई हजार वर्ष पुरानी देवी की मा टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गई। धन की लालच में आकर त सेना देवी माई का टीला खोदने गये। तभी टीले से हजारों े-काले भँवरे निकलकर मुगल सेना पर टूट पड़े। वह भाग खड़ी । यह मुगलकालीन आक्रांताओं द्वारा एक भारतीय गाँव को लूटने ऐतिहासिक घटना है। इस घटना में अवधूत राव का अदम्य स और देवी माई कमच्छा की प्रतिमा के खंडित होने की चर्चा ी है। इसमें देवी माई कमच्छा की प्रतिमा के टूटने की घटना को स्पष्ट ढंग से कहा गया है। क्योंकि यह प्रतिमा आस्था से न्धित है। वह कभी तोड़ी नहीं जा सकती। वह स्वयं ही टूट कती है, स्वयं निर्मित या प्रकट हो सकती है। यह मनोजगत का त है। यही आस्था हमारे जीवन के सतत प्रवाह का छंद बनाती । गंगा के कछार की प्रकृति से निर्मित लोक-मन की शक्ति कैसे दमित होगी भला, वह स्वयं शिव के शिरोभाग से प्रसूत है। स महाछंद की समझ जब तक लोक-स्मृतियों से लुप्त नहीं हो ती, लोक चित्त अपने मूल से कट नहीं जाता, तब तक उसके अस्तित्व को मिटाना संभव नहीं। एक लाख कफिरों का सिर कलम कर गाजी के खिताब से नवाजे जाने वाले आततायी मुगल-तुर्क रहे हों या क्रूर फिरंगी, ये राज्य और व्यवसाय व्यवस्था के दमन तक सीमित नहीं रहे, ये शैक्षिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आधारों का भी ध्वंस करते रहे। हमारे जीवन-छंद की संरचना को तोड़ते रहे और रेगिस्तानी और बर्फनी निसठ प्रकृति में विकसित हुई दस्यु प्रवृत्तियों को आरोपित करते रहे।

जिन देशों में सुगंध से भरीपूरी बेली के फूल नहीं होंगे, उनके यहाँ गजरा कहाँ से प्रचलित होगा। भारत में सभ्यता संस्कृति के विकास के प्रारंभिक समय से ही स्त्रियाँ वेणी में फूलों का गजरा लगाती हैं। यह प्रकृति से प्राणियों के अभिन्न भाव का द्योतक है। यह कोई धर्म शास्त्रों और धर्माचारों द्वारा लागू किया हुआ नियम नहीं, लोक प्रचलन है। आज हो रहा अत्याचार देखिए,पादरियों ने ईसाई बनी हुई महिलाओं को गजरा लगाने से मना कर रखा है। अभी अफगानिस्तान में ज्यों-ज्यों तालिबान का लगाम कस रहा है, वहाँ की लोक रूचियों और प्रकृति प्रदत्त परंपराओं पर प्रतिबंध का दौर शुरू को गया है। पाकिस्तान के इस्लामी शासन ने भी वहाँ की परंपराओं को मिटाने का प्रयास किया। वहाँ पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध है, शास्त्रीय संगीत गायकी के घराने समाप्त हो गए। जब प्रकृति के साथ जुड़ने का सारा रास्ता बंद हो जाएगा, लोकजीवन की व्याकुलता बढ़ जाएगी। दुनिया की कोई ईश्वरीय-धारणा और तथाकथित धर्माचार किसी भी उपाय से उस व्याकुलता को दूर नहीं कर सकते। प्राणियों की चेतना को विस्तृत करने का काम प्रकृति ही करती है। वही इसमें उल्लास भरती है। चूँकि प्रकृति ईश्वरीय सत्ता की अभिव्यक्ति है, हमें प्रकृति के मार्ग से ही वह परमसत्ता ज्ञात होती है। कोई भीतर की प्रकृति से वहाँ तक जाए या बाहर की प्रकृति से – मार्ग तो प्रकृति ही है। प्रकृति विरोधी व्यक्ति अथवा प्रकृति से जुड़ने के छंद से अनभिज्ञ भावविहीन व्यक्ति अध्यात्म की बात करता है तो समझना चाहिए कि वह भ्रम फैलाकर लोक आस्था का शोषण करना चाहता है। प्रकृति के वशीभूत होकर अर्धामुख विकृतियों तक जाना उचित है और न प्रकृति द्रोह से सर्वनाश की ओर जाना। इन दोनों के बीच से जाने वाले संस्कृति का पथ ही सर्वोत्तम है। इस कसौटी पर किसी भी धर्माधीश की परख की जा सकती है। संसार के वे सभी अस्तित्व लुप्त हो जाएँगे जो शिवा-प्रकृति अर्थात् संस्कृति का विरोध करते हैं।

चीन के रेस्तराँ में बैठी पाकिस्तान की शायरा परवीन शाकिर आर्केस्ट्रा की धुन से क्यों मनोरंजित नहीं हो पायी? ऐसा कोई भी प्राणी जो अपने मूल से मुकर गया हो और दुनिया के बनावटी धूमधड़ाके से आत्मोल्लास, शांति, सुख की अपेक्षा कर रहा हो, वह अशांत रहेगा ही। जीवन का सुख, और जीवन की शक्ति दैशिक प्रकृति में है, वैश्विक उड़ान में नहीं। वन का प्राणी सर्कश के पिंजड़े में सुखी नहीं रह सकता, चाहे उसे जितना सजा सवाँर कर क्यों न रखा जाए, पिंजड़ा तो पिंजड़ा ही है, वन नहीं।

स्वतंत्र भारत के शासकों ने आवश्यक नहीं माना कि अपने खंड़हर हुए लोक जीवन की संरचना को गहराई से समझा जाए। इसकी अच्छाइयों को नई व्यवस्था दी जाए, इसकी बुराईयाँ दूर की जाए। जनतंत्र को स्वीकृति मिली, धर्म निरपेक्षता लागू हुई।

Scanned with OKEN Scanner

पं० दीनदयाल उपाध्याय ने यह मार्ग सुझाया था। यही राज्यव्यवस्था भारत की अपनी स्वानुभूत और शाश्वत रही है। इस व्यवस्था में राज्य प्रमुख भूमिका निभाते हुए भी निरंकुश और भ्रष्ट नहीं होता और न यह लोगों का एक सर्वोपरि लक्ष्य बना होता जिसके लिए आज लोग कुछ भी करने पर तुले हुए हैं....

दायित्व पूरा हुआ। जनतंत्र लोक जीवन को स्पर्श नहीं कर सका। वह लोक जीवन में कैसे फलित हो, इसकी समुचित व्यवस्था नहीं दी गई। राज्य व्यवस्था प्रधान शक्ति-केन्द्र बनकर अकड़ती रही। आज जनजीवन में राज्य व्यवस्था के प्रति उदासीनता छा गई हैं-यह उदासीनता कांग्रेस द्वारा दिए गए समाजवाद के नारे के खोखलेपन की प्रतीति से ही बढ़ने लगी थी– 'हेले हेले बबुआ कुरूई में ढेबुआ, आ गइल समाजवाद चाट ऽ नून-नेबुआ' – भोजपुरी की इस व्यंग्य-पँक्ति में बच्चे को गोद में लेकर उसे हलराने-दुलराने, रोने से चुप कराने के एक तरीके को माध्यम बनाया गया है, बच्चे को सम्बोधित करते हुए कहा गया है कि चुप रहो लाडले बाबू गोद में ढेबुआ यानी पैसा है, खेलो। समाजवाद आ गया है, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा-नमक और नीबू चाटने के लिए मिल जाएगा। यह व्यंग्य खोखले समाजवाद के नारे की बखिया उधेड़ने के लिए काफी है। अर्थ की जन तांत्रिक व्यवस्था के बिना, केवल मतदान के जनतंत्र का क्या मतलब। आज सामान्य आवश्यकताओं के लिए भी व्यक्ति राज्य व्यवस्था का मुँह देखता है। इसके लिए राज्य व्यवस्था भी उत्तरदायी बनकर भारी आर्थिक व्यय के बोझ से दबती जा रही है, और भ्रष्टाचार के रोग से ग्रस्त हो चुकी है। यह क्लेश सत्ता के विकेन्द्रीकरण और आर्थिक लोकतंत्र से कट गया होता, और जनतंत्र सचमुच साकार हो गया होता।

पं० दीनदयाल उपाध्याय ने यह मार्ग सुझाया था। यही राज्यव्यवस्था भारत की अपनी स्वानुभूत और शाश्वत रही है। इस व्यवस्था में राज्य प्रमुख भूमिका निभाते हुए भी निरंकुश और भ्रष्ट नहीं होता और न यह लोगों का एक सर्वोपरि लक्ष्य बना होता जिसके लिए आज लोग कुछ भी करने पर तुले हुए हैं। आसुरों दस्युओं की परम्परा में राज्य सबसे बड़ी उपलब्धि रही है इसके लिए वे अपने पिता की हत्या करने या कैद कर लेने में भी संकोच नहीं करते। भारत के इतिहास में भी इस तरह की घटनाएँ हुई, पुष्प मित्र ने अपने राजा का वध किया और राजा बन बैठा-इस दुष्कार्य की निंदा महाकवि वाण भट्ट ने पुष्पमित्र को अनार्य कह कर की थी। हालाँकि पुष्पमित्र ने यह हत्या निजी राज सुख के लिए नहीं की थी, उसने वैदिक परम्परा की रक्षा के लिए की थी। फिर भी यह कार्य उचित नहीं माना गया था। हमारी मूल सांस्कृतिक धारा में श्री रामचन्द्र और भरत सरीखें भाई का आर्दश ही सदसे ऊपर रहा है। यही देव परंपरा कही गई। लेकिन असुर या अनार्य राज सुख को ही सर्वोपरि मानकर चलते रहें। इनके यहाँ की शिक्षा संस्कृति, कला-साहित्य लोक जीवन का प्रतिनिधित्व नहीं कर दरबारी राग अलापते रहे राज्य के ध्वस्त होते, ये दरबारी परंपरा भी काल कलवित होती इनमें शाश्वत गति नहीं होती। इस समय हमारा राष्ट्र संक्रमित में है अभी हम पूर्व आदर्शों का मौखिक पाठ करने में लगे है आसुरी परंपरा के परिपालन की विवशता सिर चढ़ी हुई है। अधि यह कि राज्य सत्ता को सर्वोच्च केंद्र मानकर आसुरी परंपरा निर्वाह किया जा रहा है, इसके अनेक दोष उत्पन्न होने लगे हैं। प्रपंच के बड़े-बड़े देशी-विदेशी बणिक खेलाड़ी अनुत्पादक सुखवा राजा-छाप राज्य संचालकों की नाड़ी पर अँगुली रख चुके व्यापक जनाकांक्षा उपेक्षित हो गई है।

आज हम जिस भूमंड़लीकृत व्यवस्था का हिस्सा बनते जा उसकी विषैली गैस के फैलाव से हमारी बची खुची स्मृतियों आचारों के विनष्ट होने का खतरा अधिक है। क्योंकि विश्व अन्य सभ्यताएँ भले ही चाँद पर चढ़-उतर रही हों, पर, उन्हें जी और प्रकृति को जोड़ने वाले उस छंद का ज्ञान नहीं है जिससे वि व्यवस्था श्रेष्ठ बन सकती है। उन आक्रांता असुरों के सर्वनाशी पर भागना हमारे लिए दुखद होगा। हमारी स्मृतियाँ हमारे आच को टोकेंगी और हमें कुंठित कर देंगी। हम उन क्षणजीवी किलकारि को भरभराकर गिरते हुए देख भी रहे हैं। उनकी व्यवस्था में सु नहीं हो सकते।

जिस सभ्यता के व्यापक जनजीवन में निजी आत्मोल्लास छंद नहीं है, जिसमें व्यक्तिश: स्वतंत्रता और सृजन का एका लक्ष्य नहीं है वही लोग राज्य व्यवस्था को सर्वोपरि मान सियास मानसिकता से ग्रस्त होकर उचित की अवहेलना करतें हैं। पाकिस्ता शायरा परवीन शकिर की शायरी इसका अपवाद नहीं है। यह स है कि इस शायरा की चेतना उसी छंद की है जिसे संगीत के ल में लता की आवाज व्यक्त करती है, इसीलिए उस संगीत से शाय को राहत मिलती है। लेकिन वह अपने मूलरूप में नहीं है वह दो बेठनों में बंधी हुई है। सियासत उसके सिर पर सवार है, वह विभे में है। वह अभेद नहीं हो सकती। अभेद नहीं होने पर क्लेश तो छा ही रहेगा। वास्तव में द्वन्द्व का क्लेश भी एक चटपटा स्वाद है आसुरी स्वाद, जिसे हमारी देव परंपरा भी विषम संगति से प्राप्त क चखती है और अभेद-विभेद, निर्द्वन्द्व-द्वन्द्व दोनों को साधकर व्यवस बनाती हैं। हमारी परंपरा केवल अभेद और निर्द्वन्द्व होने का पाठ न पढ़ाती, यह मात्र भेद और द्वंद्व की शिक्षा नहीं देती, यह राज्य अ अर्थ की व्यवस्था से दूर रहने वाले वैरागियों का कुनबा नहीं है। य परंपरा परस्पर भिन्न और प्रतिस्पर्धी प्रवृत्तियों को लोकमंगल क मथनी से मथती है, शिव-संकल्प के ताप से तपाती है और स रूपी धृत को प्राप्त प्राण-प्राण की तृप्ति का यज्ञ करती है और त लोक और लोकोत्तर उल्लास में झूम उठते हैं। यहाँ इदं मम क आहुति इदं न मम की अग्नि में होती रहती है, व्यष्टि समष्टि जुड़कर विराट होती रहती है और समष्टि बार-बार व्यष्टि बिन्दुअ में टूट-टूट कर अक्षर जीवन की वर्षा करती रहती है। यही हमा अमृत पथ है – यही हमारी संस्कृति। ▌

Scanned with OKEN Scanner

[ज]नमानस की कसौटी पर चूकते [र]ही हैं सम्प्रेषक माध्यम

[गुज]रात में आए भूकम्प के [दृश्]यों को बटोरते हुए कई [बा]र टीवी कैमरे अधिक [पेशे]वर होकर दर्शकों की [सह]ानुभूति खो बैठते थे। [इन] खबर बेचने वालों और [भू]कम्प पीड़ितों की सम्पत्ति [लू]टने वाले चोर उचक्कों में [भे]द पट जाता था.......

देश के जनमानस और समाचार बनने योग्य घटनाओं के बीच खड़े अखबार, रेडियो और टीवी [चै]नलों की भूमिका जनमानस में होने [वा]ली प्रतिक्रियाओं के प्रति जागरुक रहे [बि]ना सार्थक नहीं हो सकती। इस क्षेत्र [क]ा निजी उत्तरदायित्व भी है कि वह [ज]नमानस को एक सजीव, अस्तित्ववान [स]त्ता की भाँति मानकर सम्प्रेषण करे। [प्र]योजगत का विषय कोई सामान्य नहीं [हो]ती। मन के हारे हार और मन के जीते [जी]त की उक्ति से भी परिचित हैं कोई [स]ूचना हार का और कोई सूचना जीत [क]ा कारण हो सकती है।

यह दुखद प्रसंग है कि व्यवसायिकता [प]र अधिक केंद्रित होने के कारण कई बार [ये] माध्यम जनमानस में पीड़ा उत्पन्न करने [ल]गते हैं इससे इनकी व्यवसायिकता को [ला]भ के बदले हानि होने लगती है गुजरात [में] आए भूकम्प के दृश्यों को बटोरते हुए कई बार टीवी कैमरे अधिक पेशेवर होकर दर्शकों की सहानुभूति खो बैठते थे। इन खबर बेचने वालों और भूकम्प पीड़ितों की सम्पत्ति लूटने वाले चोर उचक्कों में भेद पट जाता था ऐसा लगता था कि ये खबर बेचने वाले भी संवेदनशीलता का अतिक्रमण करने पर तुले हुए हैं। इसी प्रकार कई ऐसी दुर्घटनाएँ जिससे जनमानस पीड़ित हो उठता है ठीक उस समय खबरों के चैनल विशेषज्ञों को टीवी के पर्दे पर बैठाकर विश्लेषण का अवसर देता है, विश्लेषक कई बार कामेन्ट्री करने वाले संवेदना शून्य पेशेवर की तरह लगते है इनकी बातों में संवेदना के बदले ऐसी बातें भी होते है जो अनावश्यक लगती हैं। जरूरी यह है कि इन टीवी चैनलों के धंधे में शामिल लोग जनमानस की भावनाओं को भी समझे तभी इनकी भूमिका अधिक विश्वसनीय और लोकप्रिय हो सकती है। १६ जुलाई को आगरा शिखर वार्त्ता के लिए पाकिस्तानी जनरल और स्वयंभू राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ भारत पहुँचे। उनकी अकड़ में कोई कमी नहीं थी और सरकार की ओर से उनके सत्कार में भी कोई कमी नहीं थी। मुशर्रफ और उनके दल के लोगों में आए पाकिस्तानी टीवी व अखबार के पत्रकार भी बड़े जंगी तेवर में थे। वार्ता के आखिरी दिन तो ये पाकिस्तानी पत्रकार जूझने पर भी उतारू हो गए। कहने लगे, 'इस मुल्क में कैसा जम्हुरियत है कि मेहमान राष्ट्रपति मुशर्रफ को पत्रकार सम्मेलन नहीं करने दिया जा रहा।' भारत के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता निरूपमा राव के साथ इनकी उग्रता की खबरें भी आईं। जैसे कि मुशर्रफ जोर जबर्दस्ती से काश्मीर को सिर पर उठा ले जाने वाले हैं और पाकिस्तानी मीडिया वाले इस जीत में सहयोग देने आए हैं। हुर्रियत नेताओं से भारत सरकार की असहमति के बावजूद मुशर्रफ का बात कर लेना – यह

Scanned with OKEN Scanner

अशोभनीय घटना थी। वार्त्ता की विफलता का प्रारंभिक चरण इसी को मान कर पाकिस्तानी जनरल को कच्चे आलू का चप्प खिलाकर विदाकर देना चाहिए। अभद्र के साथ भद्रता दिखने की विवशता क्यों होनी चाहिए। सूचना प्रसारण मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने मुशर्रफ की अगुआनी करते हुए जिस तरह सलाम बजाया, उसे देखकर स्वाभिमानी भारतवासियों का मन वितृष्णा से भर गया। इस आयोजन में मेजबानी का तामझाम सिर्फ इस एक नीति से थोड़ा सहनीय लग सकता था कि दुश्मन को ऊँचा आसन देना चाहिए, इससे भी शत्रुता की पहचान बनी रहती है।

भारतीय जनमानस में इस शिखर वार्त्ता को परसने वाली मीडिया रोचकता को अधिक महत्त्व देती अनुभव हुई। ऐसा लगा कि उनका उद्देश्य समाचार चैनलों के दर्शकों को अधिक से अधिक बाँधे रहना ही है। इस काम में मुशर्रफ मियाँ का आकार और पोशाक कहाँ तक सहयोगी हो सकता है इसकी परीक्षा भी हुई। धारावाहिक की तर्ज पर देशहित में हो रही अत्यंत महत्वपूर्ण वार्त्ता को दिखाने की मानसिकता से जनमानस में किस तरह की प्रतिक्रिया हो रही है, इस ओर न तो सरकार का ध्यान था और न इन खबरफरोशों का।

पाकिस्तानी पत्रकारों के जूझारूपन की प्रतिक्रिया में जहाँ कहीं भारतीय मीडिया अपना कर्त्तव्य पालन करती नजर आती वह भारतीय जनमानस के साथ उतना ही करीब होती जाती और दर्शकों को बाँध भी सकती। केवल प्रकरण की जिज्ञासा और खुशगवारी दिखाकर यह करीबी नहीं पायी जा सकती। इसका मतलब यह हुआ कि यदि समाचार माध्यम जनमानस सजीव और जागरुक समझता है अपने दर्शकों की मानसिकता को करके दूसरे तीसरे तरीकों से करीब होने की आशा विल्कुल कर सकता, ठीक उसी प्रकार जैसे राजनीतिक दल जनता की इच्छा ठोकरें लगाकर चुनाव नहीं जीत स

यदि समाचार माध्यम अपनी भूमिका को पैसों में बेंच देता है इस विषय की समझ ही नहीं रख उसकी विश्वसनीयता चूक जाएगी। नहीं है कि जनमानस में निजी पैमा खबरों को परखने की क्षमता नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि जनम की कसौटी पर हर तरह की खबरें प जाती रहती हैं। यही है कि यह धीरे-धीरे होती है और इसके परिणाम देर से मिलते है।

(पृष्ठ २० का शेष....)

स्वदेशी अपनाए बिना........

तो आम नागरिक से क्यों उम्मीद की जाए।

वाजपेयी सरकार पूरी तरह चाटुकारों से घिरी है। उसे अभी होश नहीं कि उदारीकरण के इस अंधे दौर में धीरे–धीरे राष्ट्र स्वाभिमान खत्म होता जा रहा है। हमारी थाती का क्षय होता जा रहा है। किसान परेशान होकर आत्महत्या के लिए मजबूर हो रहे हैं। धीरे–धीरे फैक्ट्रियाँ, कल–कारखाने बंद हो रहे हैं फिर भी डब्ल्यू.टी.ओ. का राग अलापा जा रहा है। उदारीकरण के दस साल के बाद भी कृषि क्षेत्र पूँजी निवेश से पूरी तरह अछूता रहा है। न तो सरकार ने और न निजी क्षेत्र ने कभी असंगठित औद्योगिक क्षेत्र को प्रमुखता दी। अब डब्ल्यू.टी.ओ. के प्रावधानों से लड़ने के लिए कृषि क्षेत्र को असहाय खड़ा किया जा रहा है। भारत इससे बच भी नहीं सकता क्योंकि डब्ल्यू.टी.ओ. के गठन में भारत की भी भूमिका रही है। अब उसके समझौते से कैसे पीछे हट सकता है। यह काम तो वही कर सकता है जिसके अंदर राष्ट्र के प्रति स्वाभिमान का भाव हो। जो लड़ने का माद्दा रखता हो। जिसको अपने पर विश्वास हो। मुझे स्थिति बहुत निराशाजनक दिखती है। वाजपेयी सरकार से उम्मीद तो बिल्कुल नहीं। हमारे वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के पास न तो ज्ञान है और न निर्णय लेने की क्षमता। बाबूगिरी उनके नस–नस में रची–बसी है। अफसरों से घिरे और अफसरों के सुनने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते । २५ साल की अफसरी के बाद वित्तमंत्री जैसे ओहदे को संभालना उनके वश की बात नहीं। आडवानी से यह उम्मीद थी लेकिन वह भी निराश कर रहे है। हालत यहाँ तक हो गई है अपनी परियोजनाओं को अपने शर्तों पूरा करवाने के लिए विदेशी कंपनि धमकी दे रही है। विदेशी कंपनियों प्रतिनिधि प्रधानमंत्री के कमरे तक प रहे है। कई बार अहसास होता है भ्रष्टाचार की लौ भाजपा शासित सरक में भी पहुँच चुकी है।

स्वदेशी की भावना आत्मस्वाभि का राग और राष्ट्र प्रेम की उत्कंठा को बचा सकती है। लेकिन इस आजमाए कौन। जिनसे उम्मीद थी वे इसे बकवास करार दे रहे है। जिन इसे आजमाने का दायित्व था वे ही प झाड़ रहे हैं। फिर उम्मीद किससे जाए। भारत जीवित राष्ट्र है। बहुत दि तक अनैतिक और अत्याचार सहन न कर सकता। कहीं न कहीं से चिंग उठेगी, लेकिन आशंका सिर्फ इस ब की है कि तब तक बहुत देर न हो जा सरकार बचाने या सरकार बनाने के खे मे राष्ट्रहित कहीं पीछे न रह जाए।

Scanned with OKEN Scanner

...रत और अन्य स्मृति ग्रंथों ...सा जान पड़ता है। भारत के ...जन जीवन में भ्रूण हंता के ...को बड़ा पाप माना जाता ...तना बड़ा जिसका प्रायश्चित ... नहीं हो, और जिसका ...तिक दण्ड भी भयानक हो। ...स्थामा के शिर की मणि ...ल उसके ब्रह्मास्त्र की शक्ति ... कर उसे अनंत काल तक ...कने के अभिशाप से श्रीकृष्ण ...स्त कर दिया.........

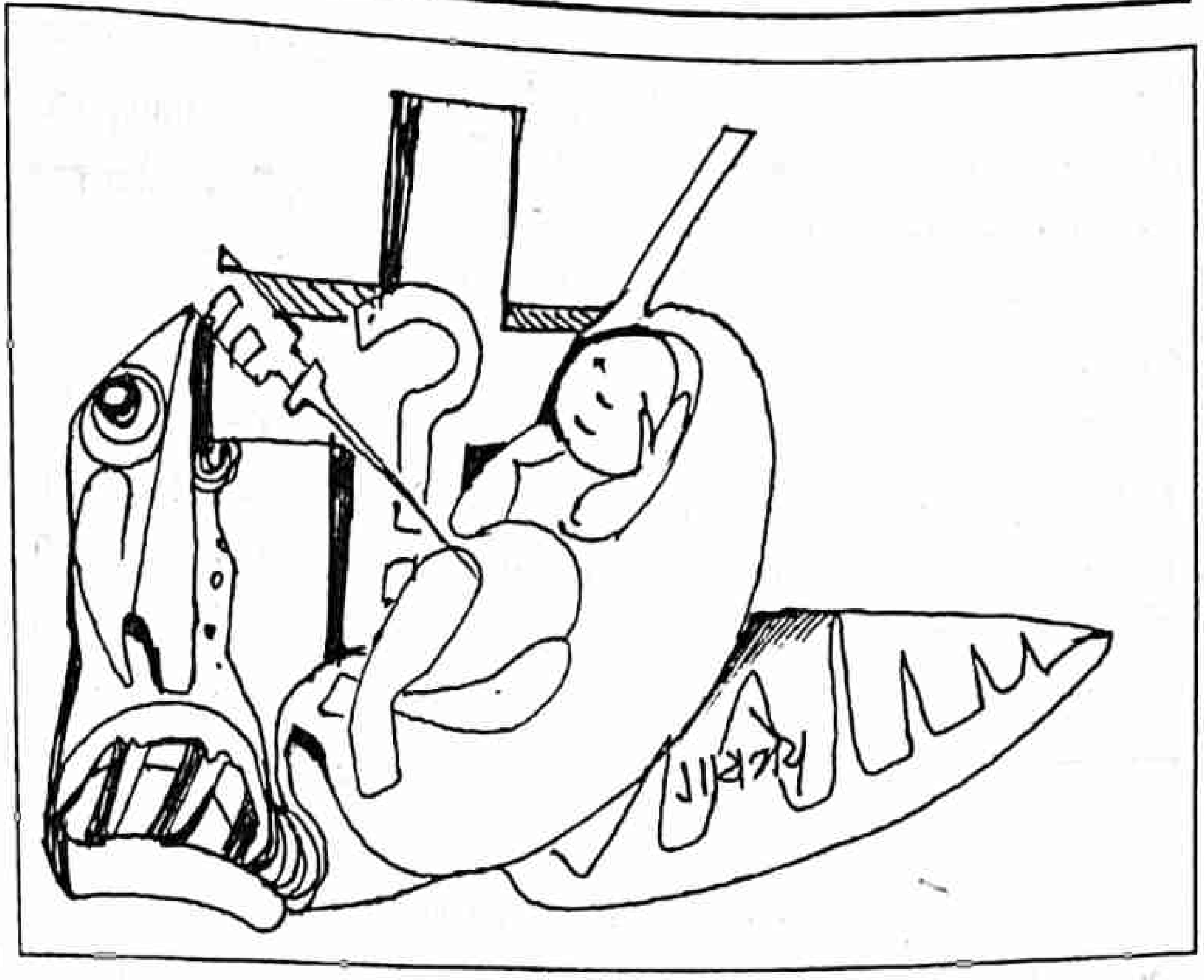

कैसे होगी कन्या-भ्रूण हत्या के पाप का अंत

भ्रूण हत्या को हमारे धर्म में ही नहीं विश्व के अन्य ईश्वरीयमतों में भी पाप माना गया है। महाभारत ...अन्य स्मृति ग्रंथों से ऐसा जान पड़ता है। ...के पूर्व जन जीवन में भ्रूण हंता के ...को बड़ा पाप माना जाता था इतना बड़ा ...का प्रायश्चित संभव नहीं हो, और जिसका ...तिक दण्ड भी भयानक हो। अश्वस्थामा ...शिर की मणि निकाल उसके ब्रह्मास्त्र की ...नष्ट कर उसे अनंत काल तक भटकने ...अभिशाप से श्रीकृष्ण ने ग्रस्त कर दिया ...इसीलिए कि उसने गर्भस्थ शिशु को नष्ट ...के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। ...र स्मृति (४-२०) में कहा गया है कि ...हत्या से जो पाप लगता है उससे दुगुना ...गर्भपात करने से लगता है। गर्भपात के ...पाप का कोई प्रायश्चित नहीं। गर्भपात के ...र उद्यत हुई स्त्री का परित्याग कर देना ...हिए।

भ्रूण हत्या अथवा गर्भपात को परिवार ...योजन के सरकारी उत्साहवर्द्धन से बल मिला इसकी एक वैधानिकता तैयार हुई। वस्तुतः जनसंख्या नियंत्रण के लिए गर्भपात को अपराध के दायरे से बाहर किया गया, अन्यथा यह एक ऐसा अमानवीय कुकृत्य है जिससे विश्व का भविष्य अन्धकार हो सकता है। दुर्मति और सामाजिक व्यवस्था के दोष के कारण गर्भस्थ शिशु की जाँच करा कर उसके कन्या होने पर गर्भपात की क्रूर विधियां प्रयोग में लाई जा रही हैं। विशेष रूप में कन्य भ्रूण की हत्या कर देने की प्रवृत्ति आज इतनी तेज गति से बढ़ गई है कि २००१ की जनगणना में स्त्री-पुरुष की जनसंख्या में चिन्ता जनक ढंग से असमानता बढ़ती दिखाई देती है। कन्या भ्रूण की हत्या मनुष्य जाति के सर्वनाश का कारण बन सकती है!

इस जघन्य पाप को समाज से सदा के लिए दूर कर दिया जाना चाहिए, इस उद्देश्य से इन दिनों सभी धर्माचार्य सक्रिय हो रहे हैं। जैन मतावलम्बियों ने इसके लिए वर्षों से सामाजिक जागरुकता लाने का कार्य प्रारंभ किया है। सिखों में भी कन्या भ्रूण के प्रति उपेक्षा दूर करने का प्रयत्न हो चुका है। सनाधन धर्म के महात्मा स्वामी राम सुखदास जी सरीखे लोग तीन दशकों से कार्यरत हैं अभी सम्मिलित प्रयासों का सूत्रपात साध्वी ऋतंभरा जी ने २४ जून २००१ को इंडियन मेडिकल एसोशिएशन, यूनिसेफ एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ मिलकर किया। इस कार्यक्रम में विशेषतः धमाचार्यों को एक मंच पर आमंत्रित किया गया था। जिसका शुभारंभ कांचिकाम कोटि के शंकाराचार्य स्वामी जयंत सरस्वती ने किया। इस आयोजन में इस्लाम और पारसी आदि मत के पीठाधीशों ने भी बड़े उत्साह से भाग लिया। यह एक सार्थक प्रयास है, जिससे हमारा समाज कन्या भ्रूण हत्या के पास से मुक्त हो सकता है।

कन्या भ्रूण की हत्या की मानसिकता को समझने के लिए अतीत के प्रसंगों में जाने की आवश्यकता नहीं है, भारतीय समाज में केरल आदि क्षेत्रों में जबकि कन्याओं के जन्म की दर कम नहीं है, फिर भी इसे

Scanned with OKEN Scanner

अच्छी सामाजिक स्वीकृति प्राप्त है। उत्तर पूर्व के प्रदेशों की कुछ जातियों में कन्याएं पैतृक सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होती है वहां मातृ प्रधान समाज प्रचलन में है। इस के ठीक विपरीत राजस्थान के कुछ इलाकों में कन्या को जन्म लेने ही मार देने का प्रचलन रहा है। मुगल आक्रांताओं के शासन और शोषण में रहे उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में भी कन्या को जन्म के बाद मारा जाता था। इसका कारण मध्यकाल में मुगलशासकों और उनकी सेनाओं आदि के द्वारा स्त्रियों को लूट लेने और उसकी रक्षा में खड़े होने वाले कुटुम्ब के सदस्यों को मौत के घाट उतार देना रहा है। अब इतिहास ने करवट लिया है तो स्थिति में बदलाव आ चुका है। लेकिन कन्या-जन्म को अभिशाप अथवा छोटा दर्जा दिलाने में कुछ दूसरी सामाजिक बुराइयां अभी भी प्रभावकारी है।

इस्लाम के उद्‌भव के पूर्व अरब देशों में लड़कियों को जन्म के कुछ दिनों बाद जमीन में जिन्दा दफना देने की कुरीति थी। पैगंबर मोहम्मद ने इस कुरीति को समाज से दूर किया था। पुराने समय में दस्युओं द्वारा स्त्रीयों को आक्रमण कर लूट ले जाने और उन्हें रूप-रंग के अनुसार पैसों में बेंच दिया जाता था। अभी भारत के दक्षिणी प्रदेशों-आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आदि में बड़े पैमाने पर युवतियों को अरब देशों में बेचे जाने की घटनाएं प्रकाश में आई। बंगला देश, नेपाल और अन्य पिछड़े क्षेत्रों से युवतियों को खरीदने-बेचने के धंधे हो रहे हैं। देश के कई क्षेत्रों में चलाए जा रहे आतंकवादी गतिविधियों में हजारों की संख्या में युवतियों का विभिन्न ढंग से उपयोग किया जा रहा है। उत्तरांचल के आतंकी हो या काश्मीर और दक्षिण-क्षेत्र के माओवादी हों, इस्लामी हों अथवा असम-नागालैंड के अलगाववादी आतंकी इनके संगठनों में ईंधन की तरह युवतियों का हर प्रकार का उपयोग किया जा रहा है। इस संदर्भ में दुनिया के धनशोषक कम्पनियों के बनाएं कुटिल जालों विभिन्न प्रकार से युवतियों के उपयोग होते हैं जिसे अक्सर पैसों के जोर और प्रचार से लोकप्रियता देकर सामाजिक महत्व का विषया बनाया जाता जबकि इस कारोबार का सीधा हमला मनुष्य के वास्तविक जीवन को धराशायी करता है।

यदि आर्थिक आक्रमणकारी युवतियों का उपयोग हथियार की तरह करते हुए उसके व्यक्तिगत जीवन को अस्तित्वहीन बनाते हैं तो इस दिशा में भी सौंदर्य प्रतियोगिता, माडलिंग, फिल्मी बेपर्द दृश्यों के उत्पादन, पॉप रॉक के भोंडे प्रदर्शन पर ध्यान देना होगा। इसे समाज के प्रमुख चरित्र के रूप में प्रतिष्ठित होने से रोकना होगा।

भारतीय जनजीवन में ऐसे धंधों से संबंधित लोगों को धर्म के मानदण्ड पर निम्न श्रेणी में रखकर उनके अर्जित धन और साधन के चकाचौंध को पतित घोषित कर दिया जाता था। त्याग, तप, चरित्र सदाचार, ज्ञान-विधा के उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त थी। इन श्रेष्ठ कर्मों में लगे लोगों को सामाजिक सम्मान दिया जाता था आज के समय का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि श्रेष्ठ कर्मों से संबंधित लोग धीरे-धीरे अल्पमत में आते जा रहे हैं, शासन और व्यवसाय ऐसे चरित्र का आदर्श समाज के समाने रख रहा है जिसका सबसे बड़ा आधार पैसा है केवल पैसा। पैसे के कारण हर चीज हासिल होती जान पड़ती है यही एक मात्र प्रतिष्ठित क्षेत्र बनता जा रहा है परिणाम यह है कि नैतिक पतन बड़ी तेज गति से हो रहा है पैसा हर कुकृत्य का संचालक बन गया है। बहुओं को दहेज के लिए मार डालना, कन्या भ्रूण की हत्या करना और क्षेत्रों में अनर्गल उपयोग के लिए मजबूर होने के पीछे धन-साधन की असमानता एक प्रमुख कारण है लेकिन इससे भी बड़ी चीजें हैं नैतिक चरित्र की सामाजिक आवश्यकता समझने वाली देश की व्यवस्था का होना जितना धन सरकार को परिवार नियोजन के क्षेत्र में करना पड़ता है। उसके अल्पांश से सुनियोजित समाज की रचना हो सकती है। स्वस्थ्य और नैतिक समाज बन सकता है। यह काम कुछ महान व्यक्ति अभी भी हमारे समाज में ... स्वरूप कर रहे हैं जिन्हें सरकारी ... क्या उसे स्वीकार करने की जरूरत ... समझी जाती। इसके पीछे कारण ... राजनीति करने वाले लोग सामाजिक ... के आधार पर छवि बनाते हैं, और ... वोट के अधिकारी बन जाते हैं। ... चाहते कि सामाजिक कार्यों को कोई ... करे। अन्यथा उनके पद की कमाई ... आयेगी। इसी तरह व्यवसायी भी ... मजबूर लोगों के शोषण से अपना ... चमत्कार पैदा करते हैं वह नहीं ... समाज नैतिक बने। समाज नैतिक ... उनका गैर जरूरी उत्पादन कौन ... ऐसी दशा को समझते हुए पुरानी ... व्यवस्था में धर्म की पद प्रतिष्ठा ... एक ऐसी समाजिक संस्था खड़ी की ... जो केवल समाज के चारित्रिक, ... शैक्षिक पोषण का कार्य करेगा। ... कालांतर में क्षीण होती चली गई और ... भूमिका विहीन होकर समाप्ति के ... पहुंच गई है इसके पुनर्निमाण का कार्य ... रहा है। यह संस्था थी पौर्हित्य की।

हमारे समाज द्रष्टा मनीषियों ने ... विभिन्न जाति वर्गों में विभाजित ... समाज के लिए सभी जातियों और ... पुरोहित बनाने के लिए प्रयत्न शुरू ... जिससे नयी व्यवस्था बनती जा रही है ... समाज संवरेगा। नैतिकता, धार्मिकता ... पतन रूकेगा। समाज मर्यादित होगा। ... व्यवस्था के खंडित हो जाने पर ... परिवर्तित हुए एक-एक समाज ... फिर से वर्ण व्यवस्था की पद्धति ... रही है। यह सुखद है। इससे ... उत्पन्न होने वाले दोषों का कारण ... निवारण के उपाय दोनों के विषय में ... बढ़ेगी। इससे राज्य और धन के ... बनने वाली व्यवस्थाओं की निरंकुशता ... रोक संभव होगी। धन का लोभ ... होगा, दहेज का रोग दूर होगा, कन्या ... की हत्या रूकेगी, नैतिक-धार्मिकता ... होगी।

Scanned with OKEN Scanner

रराष्ट्रीय श्रम संगठन में
ष्ट्र श्रमिकों का पक्ष

■ स्वदेशी संवाद

किसान बैलगाड़ियों में आते-जाते हैं वह मजदूरों सुविधायुक्त बसें कहाँ से लाएँगे। ग्रामीण क्षेत्रों के किसान खेतों में निवृत्त होने जाते हैं वहाँ मजदूरों शौचालय बनाना हास्यास्पद लगता है.....

रत के उद्यमियों की ओर से लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय प्रमुख डॉ० श्यामसुन्दर अग्रवाल से संबंधित अंतरराष्ट्रीय श्रम एवं अधिवेशन, जेनेवा में प्रतिनिधि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आई. में अक्सर होने वाले निर्णय पश्चिम विकसित देशों के अनुकूल लिए । इसमें भारत के प्रतिनिधियों की अपने देश के श्रमिकों के हित की है साथ ही विकासशील देशों के होती हैं। श्री अग्रवाल ने अधिवेशन और सहभागी प्रतिनिधियों को करते हुए कहा कि, "मैं इस में जिस देश का प्रतिनिधि बनकर उसका लिखित इतिहास पाँच हजार अधिक पुराना है। मैं आधुनिक चकाचौंध में अपना विवेक नहीं । हमें अपनी प्राचीन सभ्यता पर

अग्रवाल ने अधिवेशन में बताया छ समय से कृषि क्षेत्र के श्रमिकों य एवं सुविधाओं पर कार्य कर रहे देशों में अलग-अलग परिस्थितियाँ का के छोटे खेतों की श्रेणी में भी बड़े खेत नहीं आते। फिर श्रमिकों में पारित प्रस्ताव भारत के कृषि के अनुकूल कैसे होगा। श्री अग्रवाल सित देशों की खेती और मजदूरों की यों से अलग भारत की परिस्थितियों खींचते हुए दोनों के अंतर को स्पष्ट और अधिवेशन में लिए जाने वाले निर्णयों में भारत की अनुकूलता पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में श्रमिकों के लिए यातायात विशिष्ट मापदण्डों के मकान, कृषि भंडारण इत्यादि दक्षिण-पूर्वी देशों के लिए विभिन्न अर्थ रखते है। यही बात न्यूनतम आयु सीमा की है। ८९० पृष्ठों की तैयार रपट उद्देश्य के लिए है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन पर कुछ थोड़े देशों ने वर्चस्व बना रखा है यहाँ की कार्यवाही उन्हीं से प्रभावित होती हैं – जिससे वास्तविकता की अनदेखी होती है, पारित प्रस्ताव केवल कागज पर ही रह जाते हैं। प्रत्येक देश के राष्ट्रीय कानूनों एवं परंपराओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव पारित करने से इस आयोजन की सार्थकता सिद्ध हो सकती है।

श्री अग्रवाल ने कृषि क्षेत्र के श्रमिकों के लिए निम्नलिखित सुविधाओं की बात अधिवेशन में उठाई जिसे उपस्थित प्रतिनिधियों ने बहुमत से स्वीकार किया – (क) खेतों में काम करने वाले मजदूर स्त्री व पुरुषों के लिए अलग-अलग शौचालय बनाए जाएँ (ख) मजदूरों को ताजा गर्म भोजन दिया जाए, (ग) मजदूरों के लिए यातायात की उत्तम व्यवस्था की जाए (घ) मजदूरों के लिए निर्धारित स्तर के आवास बनाए जाएँ (ड़) १८ वर्ष से कम आयु के मजदूर खेतों में न लगाए जाएँ। श्री अग्रवाल ने जेनेवा से लौटने पर वहाँ की विस्तृत जानकारी देते भारतीय कृषि और विकसित देशों की कृषि की परिस्थितियों का अंतर स्पष्ट करते हुए बताया कि 'अधिकतम भूमि सीमा' कानून के अंतर्गत भारतीय किसान बहुत कम भूमि रख सकता है वह भी पीढ़ी-दर-पीढ़ी विभाजित होकर एक या दो एकड़ ही रह जाती है। इन छोटे खेतों पर किसान का अपना परिवार काम करता है। परिवार के सदस्य ही मालिक और स्वयं ही मजदूर हैं। भाड़े पर मजदूर कम ही लगाए जाते हैं, वह भी थोड़े समय के लिए। भारतीय खेती को 'निर्वाह' खेती कहा गया है। श्री अग्रवाल ने कहा कि जो किसान स्वयं कच्चे मकानों या झोपड़ी में रहते हैं वह अपने मजदूरों के लिए अच्छे स्तर के मकान कैसे बनवा सकते हैं और भारत के किसान बैलगाड़ियों में आते-जाते हैं वह मजदूरों के लिए सुविधायुक्त बसें कहाँ से लाएँगे। ग्रामीण क्षेत्रों के भारतीय किसान खेतों में निवृत्त होने जाते हैं वहाँ मजदूरों के लिए शौचालय बनाना हास्यास्पद लगता है। श्री अग्रवाल ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन में अधिकांश विकासशील देशों ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं उठाई। श्री अग्रवाल ने बताया कि अर्जेण्टीना ने एक प्रस्ताव द्वारा ध्यान दिलाया कि संयुक्त राष्ट्र अमरीका अपने किसानों को इतनी अधिक आर्थिक सहायता देता है कि जिससे वहाँ की उपज खाद्यान्न सस्ता होकर निर्यात हो रहा है। इससे विकासशील देशों के किसानों को प्रतिस्पर्धा में अपने उत्पाद पर कम दाम मिलते है और इससे मजदूरों को मिलने वाली सुविधाएँ कम हो जाती हैं। प्रस्ताव में अमेरिका व विकसित देशों द्वारा किसानों को दी जाने वाली आर्थिक अनुदान पर रोक लगाने हेतु कारगर कार्यवाही करने की अनुसंशा की गयी परंतु यह प्रस्ताव निरस्त कर दिया गया। डॉ० अग्रवाल ने कहा कि पहले विकासशील देशों की कृषि उद्योग को बचाना होगा। मजदूरों की सुविधाएँ कृषि उपज पर निर्भर है।

Scanned with OKEN Scanner

स्वदेशी जागरण मंच की एक और सफलता रक्षा क्षेत्र में विदेशी भागीदारी रुकी

स्व०जा०मं० की २५-२६-२७ जुलाई का प्रस्तावित धरना स्थागित

सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र का निजीकरण तथा उसमें २६ प्रतिशत विदेशी भागीदारी की अनुमति देने के विरोध में स्वदेशी जागरण मंच की प्रस्तावित २५, २६, २७ जुलाई को व्यापक प्रदर्शन के साथ संसद पर धरना देने की घोषणा तथा भारतीय मजदूर संघ और उनके अन्य सहयोगी मजदूर संगठनों की सम्मिलित रूप से प्रस्तावित २३ और २४ जुलाई को संसद पर धरना देने की घोषणा को देखते हुए भारत के रक्षा मंत्री श्री जसवंत सिंह ने १८ जुलाई को मजदूर संघों के प्रमुखों के साथ बैठक के बाद यह घोषणा की, कि सरकार रक्षा क्षेत्र का निजीकरण तथा इसमें विदेशी निवेश नहीं करेगी और आयुध कारखानों तथा रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनियों का नियंत्रण पूरी तरह सरकार के हाथों में रहेगी। इस घोषणा के फलस्वरूप स्वदेशी जागरण मंच ने अपना प्रस्तावित धरना वापस ले लिया। अगर सरकार भविष्य में ऐसा निर्णय लेती है तो स्वदेशी जागरण मंच इसका विरोध करेगा।

ज्ञातव्य है कि इसके पहले भी सरकार द्वारा सादे नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था, तब स्वदेशी जागरण मंच द्वारा इस निर्णय के विरोध में पद यात्रा तथा संसद पर धरना देने की घोषणा के फलस्वरूप सरकार को सादे नमक की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लेना पड़ा। यदि रक्षा क्षेत्र में विदेशी भागीदारी रुक जाती है तो स्वदेशी जागरण मंच एवं सहयोगी संगठनों के प्रयास को सार्थक माना जा सकता है। ■

ऊना हिमाचल प्रदेश में प्रांतीय परिषद स्व.जा.मं. की बैठक सम्पन्न

विगत १४–१५ जुलाई २००१ को ऊना में प्रांतीय परिषद स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सम्पर्क प्रमुख मा. लालजीभाई पटेल की उपस्थिति एवं मार्गदर्शन में हुई। बैठक में आगामी पूरे वर्ष के कार्यक्रमों पर विचार किया गया।

बैठक में २५, २६ व २७ जुलाई, २००१ को राष्ट्रीय स्तर पर संसद के सामने विदेशी निवेश की अनुमति तथा निजीकरण करने का केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के विरुद्ध धरना भी तय था जिसे सरकार द्वारा पीछे हटने के फलस्वरूप स्थगित कर दिया गया। अन्य निर्धारित कार्यक्रम निम्नलिखित है –

(१) स्वदेशी पत्रिका के लिए ग्राहक बनाना,
(२) अक्तूबर २००१ में धन संग्रह,
(३) २५ सितम्बर से २ अक्तूबर २००१ तक स्वदेशी सप्ताह मनाने,
(४) २५, २६ व २७ नवम्बर २००१ आगरा में होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन में १० कार्यकर्ताओं को भेजना,
(५) १२ सितम्बर को स्वदेशी दिवस मनाना,
(६) १२, १३ व १४ अक्तूबर को धर्मशाला में प्रांतीय विचार वर्ग करना और
(७) ११, १२ व १३ मई २००२ को मण्डी में प्रांतीय सम्मेलन आयोजित करना।

स्वदेशी जागरण मंच, दिल्ली प्रदेश की बैठक तय हुई आगामी योजना

दिल्ली प्रदेश स्वदेशी जागरण के सह-प्रांत संयोजक डॉ. महाजन ने बताया कि दिल्ली प्र प्रत्येक विभाग में विभागश: बैठकें और उसमें आगामी वर्षभर की यो बनायी गयी। जो निम्नलिखित है -

- दिनाँक ८ अगस्त को वि कम्पनी भारत छोड़ो रैली मूर्ति से राजघाट तक जाए
- सभी महाविद्यालय और विद्या में स्वदेशी जागरण को ले भाषण, परिसम्वाद वक्तृत्व स होगी। यह कार्यक्रम स्वदे सप्ताह से आगे-पीछे एक म तक चलेगा।
- स्वदेशी वस्तुओं की सूची ले घर-घर जाने का उपक्रम योजना है और ज्यादा से स्वदेशी कॉर्नर दुकानों की सं में वृद्धि की जाए।
- प्रदेश में स्वदेशी आजीवन सदस्य ३०० के क है और ५००-८०० सदस्य ब का निर्णय लिया गया है। अ वार्षिक सदस्य १२०० है औ २००० करने की योजना है।
- हर विद्यालय और महाविद्याल पुस्तकालय में स्वदेशी पत्रि का सदस्य बनाने की योजना है

Scanned with OKEN Scanner

ा हूँ कि मेरा लेख कर मेरे मित्र कुट्टी े हाथ में जाएगा, बाद वह विवाद रने से नहीं मानेंगी। रकूज़ा से जले रहते गिलो साहब भुने , वह उन्हें दागी कहते हैं......

ल पाणि

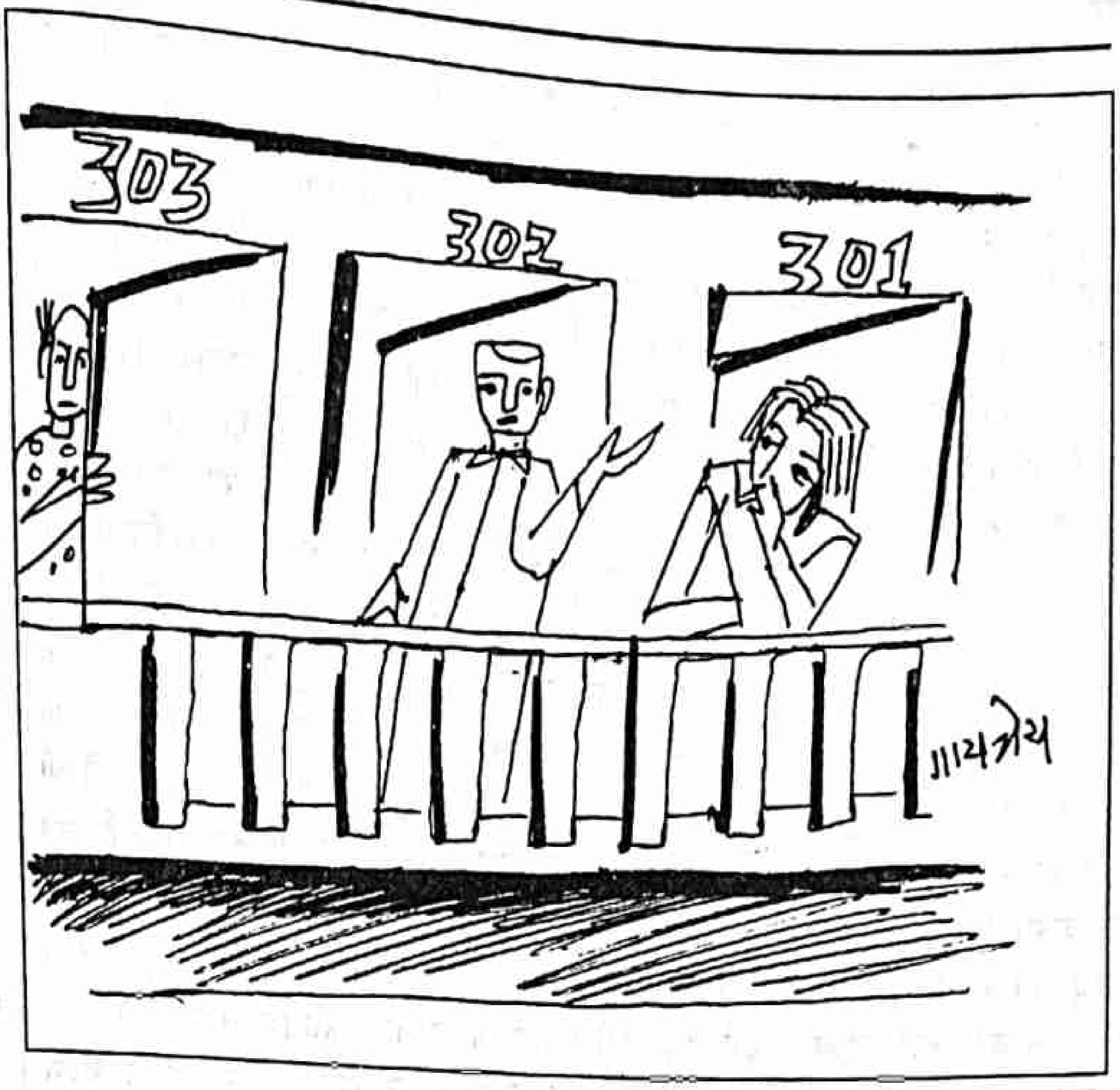

लेट मी चैट

बहुमंजिली इमारत के ३०२ नं. कमरे में रहता हूँ। मेरी अड़ोसी मैडम ३०१ में रहती है, मेरे पड़ोसी ज्जन ३०३ नं. कमरे में। एक नम्बर ने के कारण मैडम कारकूज़ा मेरा हैं एक नम्बर पीछे होने के कारण मिस्टर लो साहब पड़ोसी। सामने रेलिंग से मेरे क रस्सी की सीढ़ी भी लगी होती, जिस ते उतरते मुझे पर्वतारोहरण का श्रम करना तो भी मैं हमेशा प्रसन्न होता। मैं -पड़ोस से मुक्त रहकर कमरे में आता

मैं जानता हूँ कि मेरा लेख जब छपकर त्र कुट्टी स्वामी के हाथ में जाएगा, पढ़ने र वह विवाद उत्पन्न करने से नहीं मानेंगो। ारकूज़ा से जले रहते है, गिलगिलो साहब े रहते है, वह उन्हें दागी मनुष्य कहते हैं। दिन लिफ्ट में जब मैं अपने पड़ोसी से बात हा था कुट्टी स्वामी देखदेख कूढ़ रहे थे। कि मेरे पड़ोसी का दिमाग स्थाई तौर पर ा में और उनकी देह अस्थाई तौर पर देश हरी अर्थात् (दिल्ली) में रहती है वह ड़ हैं तो नाम के, उनके वस्त्र बड़े भड़किले चकिले होते हैं। वह विदेशी सेन्ट में तर ं के कारण कुट्टी स्वामी के लिए उलटी कारण भी बनते हैं, जैसा कि वह मुझे बताते कि एक तो उस व्यक्ति की नेकर में टाँग बनावट देख मैं पीड़ित होता हूँ, दूसरा उसके ड़े की गंध मेरे सिर दर्द का कारण बनती ास मैं परेशान होकर जाऊँ कहाँ? मेरे अड़ोसी और पड़ोसी तो यही दोनों है।

कल शाम जब मैं ७.३० बजे कमरे में पहुँचा, पसीने से तरबर भींगे कपड़े उतरकर पंखे के नीचे और कुर्सी के ऊपर अपने अनब्याहे हाथों फैला रहा था तभी बजली चली गई। दरवाजा खोल, कुर्सी को थोड़ा बाहर निकाल हवा की प्रतीक्षा में धैर्य से बैठ गया। तभी कमरा नं. ३०१ से मेरी अड़ोसिन मैडम निकली देखते बोली; हेलो पाणि हाऊ आर यूँ? मैं कैसे कहूँ – फाइन। विवश होकर बुदबुदाया फाइन . . . फाइन मैडम बहुत तेज दिमाग की हैं बोली तुम 'फाइन' इस तरह कह रहे हो जैसे कहीं पनिश हुए हो, तेरी कार किसी ट्रेफिक वाले ने पकड़ तो नहीं थी? मैंने दबते हुए पूछा, क्यों? वह बोली, फाइन और फाइन के उच्चारण में आने वाले फर्क मूड़ ठीक रहने और नहीं रहने पर निर्भर करता है और इसीके साथ उसका अर्थ भी बदल जाता है। मैंने कहा, आप ठीक हैं? आपके इंस्टीच्यूट के डॉ० सोढ़ी मिले थे। आई डॉण्ट लाइक डॉ. सोढ़ी, मेरा बेटा भी उससे हेट करता है – मैडम ने खींझ कर कहा। मैंने पूछा, क्यों? वह बोली, तुम्हें पता है, आईम ए यंग विडो, तीन फॉरन यूनिवर्सिटियों की डिग्री है मेरे पास, एक बड़े पद पर काम कर रही हूँ। लेकिन वह नहीं जानता, कैसे बात करनी चाहिए। एक दिन कहने लगा हम रिपोर्ट पर साईन नहीं कर सकते, हमें क्या मिलता है। मैंने उससे कहा, आप सीनियर हो, जरूरी नहीं है कि जूनियर फेलो से अधिक कमाओ। पर यह जरूरी है कि जूनियर सम्मान दे। वह मैं देती हूँ। इसके बाद भी साइन नहीं करने का क्या मतलब हुआ? उस समय मेरा बेटा मेरे पास खड़ा था, उसे होस्टल की फीस देनी थी, उसके सामने उसने साइन करने से इनकार किया। मैंने जब डीन से शिकायत करने की बात की, उसने साइन करके गला छुटाया।

मैडम ने सिगरेट का कश खींचकर धुँआ छोड़ा, कुछ देर उनके छोड़े हुए धुएँ की गंध हवा में तिरती रही। मैं उस अपनी नाक तक आने से रोकने में असमर्थ था। फिर भी मैं विरोध की चुप्पी को तोड़ने का साहस नहीं बटोर सका था। मेरे पड़ोसी का दरवाजा भी चें करते हुए खुला। मिस्टर गिलगिलो बाहर निकल आए। मेरे एक ओर रेलिंग पकड़ कर खड़ा हो गए। गिलगिलो साहब नेकर में थे। उनके तोंद को ढ़कती हुई चितकबरी गंजी शाम के धुधलके में और विकट दृश्य प्रसूत कर रही थी। पता नहीं, उनके गंजे सिर के डाई किए कुछ बचे-खुचे बालों से कारकूजा मैडम के मन को

Scanned with OKEN Scanner

क्यों खरोचं लगती है? मैडम कारकूजा मेरे कानों तक झुकी और फुसफुसाई चैट हिम। मैंने धीरे से पूछा, क्या? वह दुबारा नहीं बोली। अपने कमरे में भीतर चली गई। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। फिर गिलगिलो साहब भी अपने कमरे में चले गए। उनका दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। पर मैडम के घर में मोमबत्ती जली तो खुले दरवाजे से रोशनी निकलकर छा गई। कुछ देर बाद मैडम फिर दरवाजे से बाहर आईं। मैंने कहा मुझे अड़ोसी और पड़ोसी से एक साथ धिरने का मौका पहली बार मिलने वाला था, लेकिन आपने चैट हिम का मंत्र मेरे मन में क्या दिया कि में बच गया। वह मुस्काई, और बोली चैट हिम का अर्थ तुमने क्या समझा? कुछ नहीं – मैंने कहा। मैडम बोली – चैट शब्द का प्रचलन अभी अब बढ़ रहा है तुम्हें शायद मालूम नहीं, चैट हिम का मतलब हुआ – उसे छेड़ो, उसे उकसाओ, उसके भीतर के रहस्य जानो। जैसे उकसाना शब्द का प्रचलन बहुत पहले तब हुआ था जब घरों में दीये जला करते थे। उसमें बाती होती थी। जब दीये का प्रकाश तेज करना होता, बाती को उकसाया जाता था। यही से यह शब्द दूसरे क्षेत्रों में भी प्रचलित हो गया। यह किसी को प्रेरित करने के अर्थ में प्रयोग किया जाने लगा। ऐसे ही आज इन्टरनेट पर चैटिंग की जाती है। इन्टरनेट की तहों को खोल खोलकर देखने के अर्थ में प्रयोग हो रहे चैट शब्द को किसी व्यक्ति की बातों को सुनते हुए उसे इच्छानुसार घुमाते जाना और थका देने के तौर तरीके को 'चैट' कहा जाने लगा है। मैं मैडम के विकसित बातों को सुनकर विचार करने लगा, आने वाले समय में कोई किसी की बात सुनाते हुए हूँ-हूँ भी करेगा तो बोलने वाला सोच सकता है कि यह हमें चैट कर रहा है। सम्वादहीन दशा में समाज को पहुँचाने में इन्टरनेट की भूमिका हो सकती है। टीवी स्क्रीन का सामने घंटो बैठे रहने वाले बच्चों के निंदित करने वाला शब्द तो मैंने सुना था पर चैट शब्द का प्रयोगवादी अर्थ पहली बार सुन रहा था। मैडम मेरी चुप्पी को तोड़ने के पहले सिगरेट जला रही थी तभी गिलगिलो का दरवाजा चें करके फिर खुला, उसमें से गिलगिलो नहीं निकले तब तक मैडमकारकूज़ा कमरे में चली गई। उनके रसोईघर से बर्त्तनों की खनक सुनाई देने लगी, गिलगिलो का दरवाज़ा धड़ाम से बन्द हो गया, मैडम फिर बाहर आई और बोली साँभर बना रही हूँ तुम उसे टेस्ट करके देखना। मैंने कहा साँभर की चैटिंग जरूर करूँगा। ओ हाँ लेट मी चैट – मैडम ने हँसते हुए पूछा . . . . . भीतर क्या कर रहा होगा – अँधेरे और उसमें बैठा वह गिलगिलो? क्या मालूम? – मैंने कहा। वह हँसी नहीं मालूम तो कब जानोगे, दुनिया बहुत तेज भाग रही है। मुझे लगता है, पाणि, कि यह व्यक्ति मानव मांस खाता है। इसके कमरे से निकला हुआ एक प्लास्टिक पैकिंग कूड़े में पड़ा था। मैं उसे देखकर दंग रह गई। उस पर ताईवान लिखा हुआ था कुछ गुप्त कोड भी पड़े हुए थे। मैं जब उसकी जाँच करने पर तुली तो मुझे इन्टरनेट के मैन बीफ के पैकेज का ध्यान आया। इसका कूड़ा देखकर मैं बहुत पहले यह जान चुकी थी कि यह कौन-कौन सी गोलियाँ खाता है, उन गोलियों के आधार पर मैं यह भी समझ चुकी थी कि इसे कौन-कौन रोग हैं और यह कैसी दिनचर्या बीताता है। उस दिन मैं मानव माँस का प्लास्टिक पैकिंग भी पा गई। मुझे इसका चेहरा नरभक्षी की तरह दिखता भी है। हजारों डॉलर तक की कीमत में बिकने वाला मानव मांस कोई छोटी कमाई का व्यक्ति कैसे खरीद कर खा सकता है। इस व्यक्ति की बड़ी कमाई इन्हीं चीजों में जा रही है, यह इसलिए घर गृहस्थी में रुचि नहीं लेता अकेला रहता है। युगांडा का ईदी अमीन जवान औरतों का माँस खाने में अधिक रुचि रखता था, उसके मरने के बाद उसके फ्रीज से २४ नुरमंड मिले थे। औरतों के माँस में उसकी रुचि क्यों थीं, जानते हो? मांसाहार और वासना के एकाकार हो जाने के कारण। माँसाहार से मांस के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। माँस खाने-खाते व्यक्ति किस हद तक जा सकता है इसका उदाहरण ईदी अमीन था। ताईवान, चीन, थाईलैण्ड, म्यामार में इन दिनों शिशुओं के माँस और नरमांस खाने का प्रचलन बढ़ रहा है। तुम कभी डब्ल्यू. डब्ल्य. डब्ल्यू. मैन बीफ कॉम पर चैट करके देख सकते हो, क्या-क्या चल रहा है दुनिया में'। मैडम कारकूजा ने सिगरेट का भरपूर धुआँ खींचा और छोड़ा। तभी मिस्टर गिलगिलो का दरवाजा चें करता हुआ खुला। वह बाहर निकल रेंलिंग पकड़कर खड़े हुए और इधर कारकूजा के कूकर की सीटी बजी। वह अपने रसोईघर में गई। गिलगिलो साहब ने कहा, कमबख्त बिजली को आज क्या हो गया है? मैंने उनकी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा, जनाब इस कैम्पस में अपना जनरेटर भी है। लेकिन वह खराब पड़ा है। उसे तो कम से कम ठीक रखना चाहिए व्यवस्था के लोगों को। गिलगिलो बोल पड़े, ... तुम्हें उस मैडम से कहनी चाहिए थी, ... तो बड़ी जान-पहचान है। मैं चैट करने के मूड में आ गया, 'विदेश में भी बिजली ... बड़ा बुरा हाल है, क्यों गिलगिलो ... गिलगिलो ने ध्यान नहीं दिया। वह बोले, ... कुट्टी स्वामी भी कुछ कर सकता है, ... नेताओं के आगे पीछे करता है उससे बोलिए ... करे। मैंने फिर चैटिंग प्रयास किया, ... स्वामी बढ़े ठढ़े हैं। उन्हें बीफ ऑफ करना ... वश की बात नहीं। मिस्टर गिलगिलो हँसे। ... बोले कहो उससे, स्वामी बनकर कब तक ... बीफ लिया करे। सुबह उठकर ईश्वर का ... लेता है, उसकी किस्मत रोती रहेगी। मैंने ... आपकी शिक्षा का कुछ मतलब होगा, मेरी ... सुनेगा, आप ही क्यों नहीं कहते। फिर ... गिलगिलो ने कहा, वह तो मुझे देखकर ... फेरता है, मुझमें नफरत लायक उसे न जाने ... दिखता है।

जब गिलगिलो बोल रहे थे। ... कारकूजा मैडम की छाया ही रही होगी, ... दरवाजे पर फैले मोमबत्ती के प्रकाश पर ... थी। उस छाया पर गिलगिलो की नजर भी ... वह तेज स्वर में बोलने लगे, जिसे दुनिया के ... में सैर करना और मस्ती लेनी है वह घर में ... नहीं रह सकता। इंडिया की सड़ी हुई ... नहीं झेलेगा। वह मेरे जैसों के साथ आप ... जैसे लाखों में एक नहीं अरबों में है। सहसा ... से बिजली आ गयी, जैसे पुरी बहुमंजली ... में नए जीवन का संचार हो गया। मैं कमरे ... प्रवेश कर गया। मेरे अड़ोसी और पड़ोसी ... के दरवाजे भी बंद हो गए। संभव है, ... से मिस्टर गिलगिलो के विषय में मैडम कारकूजा ... का अनुमान पक्की जानकारी में बदल ... होगा, वह धरती से बहुत ऊपर मान ... होने की ऊँचाई पा लेता है वह दूसरे मानव ... मांस क्या अपनी देह का मांस भी खा ... है। यह तो विश्व-विकास का नमूना व्यवसायी ... विश्व दिखा रहा है। संभव है मैडम साँभर ... लेने के बाद मेरे कमरे का कॉल बेल दबाते ... अपने अनुमान के पक्की जानकारी में ... होने के बाद साँभर की कटोरी में चम्मच ... डालकर मेरे हाथों में पकड़ा दें। मैं साँभर ... स्वाद लेता हुआ उनके साथ मिस्टर गिलगिलो ... को कोसने में समय लगाता लेकिन बिजली ... गई थी। सबके कमरे के भीतर की जिन्दगी ... की जिन्दगी को निगल कर सो गयी।

Scanned with OKEN Scanner

नोआ में जी-८ देशों के सम्मेलन का व्यापक विरोध

दुनिया के सर्वाधिक धनी एवं औद्योगीकृत संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, जापान इटली, ब्रिटेन, कनाडा एवं रूस के राष्ट्र का २७वाँ सम्मेलन इटली के तटीय शहर में सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन का व्यापक जेनोआ की सड़कों पर हुआ। विरोध इतने प्रबल थे कि उन्हें दबाने के लिए को गोली चलानी पड़ी जिसमें एक कारी की मौत हो गयी। इस सम्मेलन के बिन्दुओं में प्रमुख थे — विश्व व्यापार , अमेरिकी मंदी, एड्स, गरीबी और वार्मिंग।

प्रदर्शनकारी ज्यादातर शांतिपूर्ण प्रदर्शन रहे थे। उनकी मुख्य माँग वर्तमान व्यापारिक नीतियों में बदलाव की थी ताकि गरीब राष्ट्रों कर्ज का बोझ न बढ़े और वैश्वीकरण के हानिकारक प्रभावों को रोका जा सके। इस वैश्वीकरण विरोधी प्रदर्शनों पर इटली की सरकार का रूख बहुत ही कड़ा रहा।

प्रदर्शनकारी की मौत का स्थान जल्दी ही एक पूजा स्थल बन गया। इस प्रदर्शन के दौरान दर्जनों गिरफ्तार हुए और सैकड़ों पुलिस बर्बरता में घायल हुए।

सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग पर हो रहे बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति बुश और बाकी राष्ट्राध्यक्षों के बीच तीखे मतभेद थे। ब्लादिमिर पुतिन ने मिसाइल रक्षा प्रणाली का मुद्दा उठाया। वाशिंगटन के क्योटो समझौते को न मानने की घोषणा ने बहुत से यूरोपीय राष्ट्रों को नाराज किया है बुश की मिसाइल रक्षा योजना पर भी इस सम्मेलन में तीखी बहस हुई और पुतीन ने चेतावनी दी कि अमेरिका के इस कदम से पुनः हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। इस सम्मेलन में मध्यपूर्व पर भी चर्चा हुई। जी-८ देशों के विदेशमंत्रियों की बैठक में यह तय हुआ था कि इस्राइल फिलीस्तीन सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक भेजे जाएं इस सम्मेलन में यूगोस्लाविया के पूर्व राष्ट्रपति मिलोसेविच पर भी चर्चा हुई। शुक्रवार को सभी राष्ट्राध्यक्षों ने खुले व्यापार पर बातचीत का आह्वान किया ताकि एक निश्चित आर्थिक विकास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाया जा सके। उन्होंने कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी से इस वर्ष के अंत तक उबर जाएगी इसके साथ ही जोड़ा कि यूरोप अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधर रही है।

जी-८ देशों ने एड्स के रोकथाम के लिए १.२ बिलियन डॉलर का एक कोष संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत बनाने के लिए घोषणा की। ■

खादी के लिए नई तकनीकी

चरखे का पुनः उदय हो रहा है। इस उदय परिणाम स्वरूप दुनिया के सबसे बहतरीन बनेंगे।

इस नवोदय में ऐतिहासिक जमनालाल ज केन्द्रीय खोज संस्थान बी॰सी॰आर॰आई॰), वर्धा और भारतीय गिक संस्थान के तकनीकी सहयोग से अब ण विकास को एक नयी दिशा मिलेगी। बी॰सी॰आर॰आई॰ का उद्‌घाटन १९३५ में त के महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों सर्वश्री दीशचन्द्र बोस एवं श्री चंद्रशेखर वेंकट रमण ३५ में गाँधी जी के आग्रह पर किया तथा और के कार्यकारी परिषद् के सदस्य रहे थे। त्मा गाँधी एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे की सोच इस समय के किसी भी ई-बिजनेस ल से आगे की थी। उनके विचार से ग्रामीण र्थव्यवस्था आधारित देश के विकास के लिए जिससे राष्ट्र स्वावलंबी बनेगा लघु एवं कुटीर द्योगों के लिए लगातार, तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्रिये होनी आवश्यक थीं।

पिछले सप्ताह चरखे ने अपना एक चक्र पूरा किया जिसके अंतर्गत पुनः ग्रामीण उद्योग एवं अत्याधुनिक तकनीक के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की गई। दिल्ली में एक सेमिनार में के॰वी॰आई॰सी॰ जो जे॰बी॰सी॰आर॰आई॰ की संचालक है ने घोषणा की कि जे॰बी॰सी॰आर॰आई॰ एवं भा॰प्रौ॰सं॰ दिल्ली के बीच एक समझौता हुआ है अगले तीन वर्षों के लिए प्रौ॰सं॰ दिल्ली जे॰बी॰सी॰आर॰आई॰ वर्धा को महत्वपूर्ण तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराएगा।

भा॰प्रौ॰सं॰ में इस त्रिवर्षीय परियोजना के प्रमुख प्रो॰ राजेन्द्र प्रसाद के अनुसार वे लोग ग्रामीण हस्तशिल्पियों से संबंध बढ़ाने के इच्छुक हैं और न केवल 'खादी' बल्कि अन्य ग्रामीण उद्योगों के उत्पादों का भी पुनरुद्धार करना चाहते हैं। यद्यपि गाँधी जी के सपनों की खादी के॰वी॰आई॰सी॰ का ध्वजवाहक है तथापि के॰वी॰आई॰सी॰ अन्य उत्पाद भी अपनी जगह बना चुके हैं।

वर्षों से ग्रामीण उद्योग में विज्ञान का प्रवेश होता रहा है इसमें नए चरखे, सीमेंट के नए तरीके और रबर उद्योग के विकास शामिल है। इस समझौते का वर्धा में स्वागत कहीं हुआ है। वहाँ जे॰बी॰सी॰आर॰आई॰ को चलाने के ढंग पर आपत्ति उठ रही है। १९५७ में उसके के॰वी॰आई॰सी॰ के अंतर्गत आने के बाद से इसके उपयोगिता में कमी आयी है। लोगों का यहाँ तक कहना है कि यह सफेद हाथी है जिसका सामाजिक योगदान नहीं है।

जे॰बी॰सी॰आर॰आई॰ के उपनिदेशक एस॰एस॰ जैसवाल के अनुसार "नए विकास न होने पर हस्तशिल्पी अपनी-अपनी पीढ़ी को पारिवारिक कार्य करने की आज्ञा नहीं देते है। हम उम्मीद करते हैं कि आधुनिक तकनीक के आगमन से इस स्थिति में बदलाव आएगा और नई पीढ़ी अपने पारिवारिक व्यवसाय में दिलचस्पी लेगी जिससे ग्रामीण उद्योगों को एक नयी जिंदगी मिलेगी।"

२ अक्तूबर गाँधी जयंती के अवसर पर यह समझौता लागू होगा। इसका परिणाम भविष्य के गर्भ में हैं। हम उम्मीद करते हैं इससे स्वदेशी एवं स्वराष्ट्र के साथ ग्राम स्वावलम्बन के राष्ट्रपिता के सपनों को साकार होने में मदद मिलेगी। ■

Scanned with OKEN Scanner

डाक पंजीयन संख्या डीएल-१३०२७/२००१ आर. एन. आई. पंजीयन संख्या

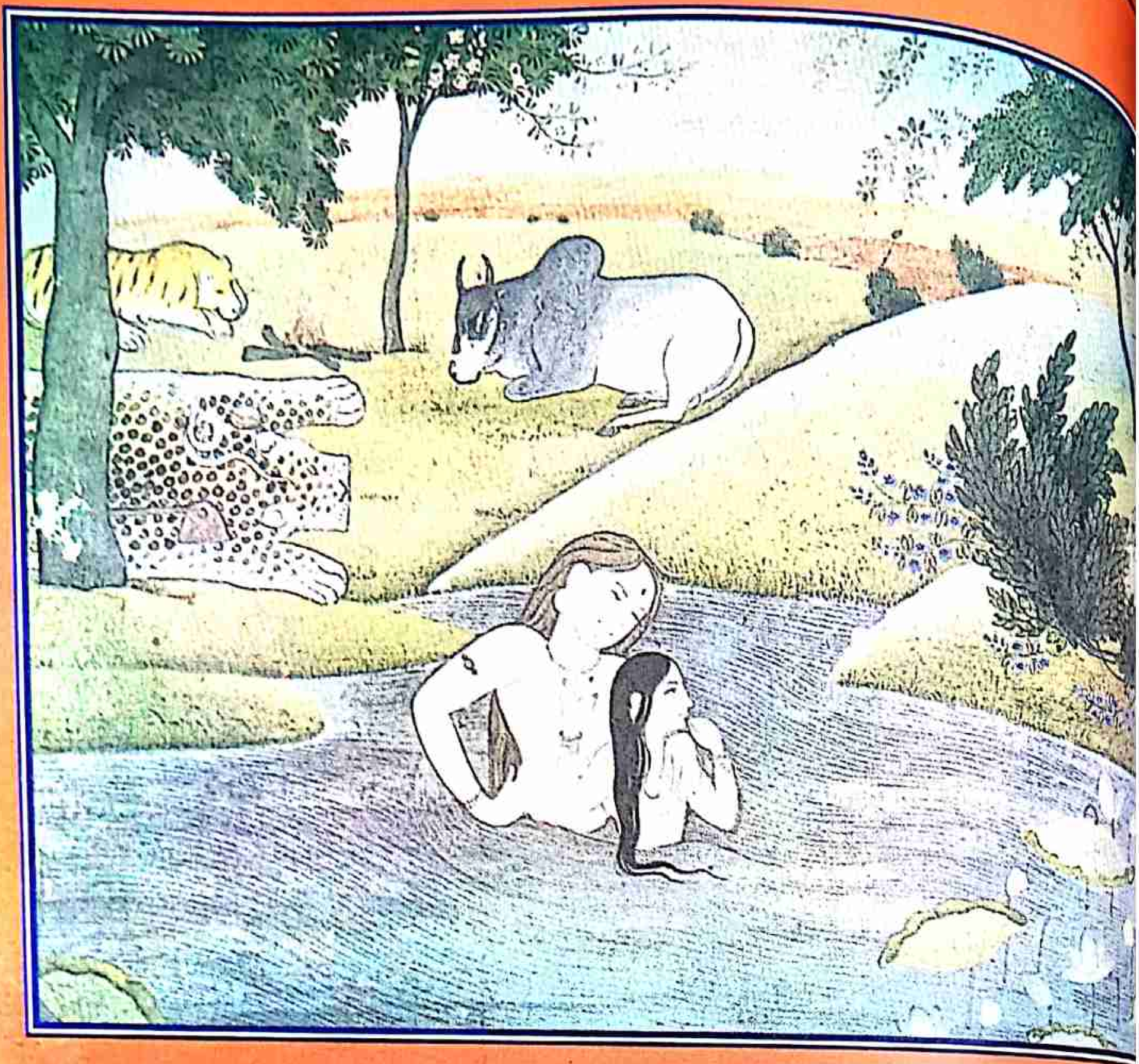

स्वदेशी खाद्य "धन्नजय" का प्रयोग करें।

INDO JAPAN AGROTECH. LTD.

(Manufacturer of : "Dhnanjay " Bio Organic Fertilizer)

"धन्नजय" कार्बनिक जैविक खाद्य के निर्माता

Head Office : 100-A, Cycle Market, Jhandewalan Extn. New Delhi-1100055
Tel.: 91-011-7517013 Fax : 91-011-3556436 Res.: 2260773, 2264642 Mobile:98100-17327
Factory : GIDC-Tharsa, Gujrat

आपकी अपनी स्वदेशी कम्पनी

ईश्वर दास महाजन द्वारा स्वदेशी जागरण फाऊंडेशन के लिए कुमार ब्रदर्स प्रिंटिंग प्रेस, नवीन शाहदरा, दिल्ली-३२ से मुद्रित एवं ६०, नॉर्थ एवेन्यू से

Scanned with OKEN Scanner